R.N.I. No.HIN/2002/8718 www.aksnews.com M.P./BHOPAL/642/2024-26

In Pursuit of Truth

पाक्षिक

अक्स

वर्ष : 23 । अंक : 23
01 से 15 सितंबर 2025
पृष्ठ : 48
मूल्य : 25 रु.

टैरिफ वार: विश्व में बन रहा महाशक्ति का त्रिकोण

अमेरिका की बादशाहत खत्म!

भारत, रूस और चीन की जुगलबंदी खत्म करेगी अमेरिका की दादागिरी

ट्रंप की चुनौतियों से निपटने भारत हर मोर्चे पर मुकाबले के लिए तैयार

इन्वेस्ट मध्यप्रदेश
अनंत संभावनाएं
उद्योग एवं रोज़गार वर्ष 2025
डॉ. मोहन यादव, मुख्यमंत्री
नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री
प्रदेश के कृषि फीडर्स को सौर ऊर्जीकृत करने का अभियान
नवीकरणीय ऊर्जा से समृद्ध होता मध्यप्रदेश
व्यापक निवेश अवसर
सूर्य मित्र कृषि फीडर योजना
योजना के प्रमुख उद्देश्य
• मध्यप्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी को कम मूल्य पर बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित कराना
• ट्रांसमिशन हानि कम करना एवं सीधे खपत स्थल पर बिजली पहुंचाना
• 33/11 केवी उपकेंद्रों पर ओवरलोडिंग, लो-वोल्टेज और पावर कट की समस्या कम करना
• किसान को सिंचाई के लिये दिन में बिजली उपलब्ध कराना
नवीकरणीय ऊर्जा का विस्तार
• सब-स्टेशन की 100% क्षमता तक की परियोजनाओं की स्थापना
• परियोजनाओं को पीएम कुसुम-सी योजनांतर्गत उपलब्ध केंद्रीय अनुदान का लाभ लेने का विकल्प
• 1900 से अधिक विद्युत सबस्टेशन एवं 14500 मेगावॉट क्षमता और परियोजनाओं के चयन हेतु उपलब्ध
• पीएम कुसुम योजना में 3.45 लाख पम्प का लक्ष्य
• वोकल फॉर लोकल - स्थानीय उद्यमियों के लिए निवेश एवं रोज़गार सृजन का उचित अवसर
• वित्त पोषण की सुगमता के लिए बैंकों से समन्वय
• परियोजनाओं में AIF के तहत 7 वर्षों तक 3% ब्याज में छूट
• Reactive Power प्रबंधन से अतिरिक्त आय

इस अंक में

बिजली

9 | बिजली विभाग में नियुक्तियों...

मप्र में युवाओं को सरकारी नौकरी उपलब्ध कराने के लिए सरकार की ओर से प्रयास जारी है। इसी कड़ी में विभिन्न विभागों में रिक्त पदों को भरा जा रहा है। इसी क्रम में बिजली विभाग में एक हजार से ज्यादा लोगों को नियुक्ति पत्र...

डायरी

10-11 | अनुराग जैन के लिए...

मप्र में बीते कुछ दिनों से चर्चाएं हो रही थीं कि मुख्य सचिव अनुराग जैन को एक्सटेंशन मिलेगा या नहीं। 28 अगस्त को इन अटकलों पर विराम लग गया है। मुख्य सचिव अनुराग जैन को एक साल का एक्सटेंशन मिला है।

विडंबना

14 | मानसून सत्र में मौन रहे 68...

मप्र विधानसभा के मानसून सत्र में सत्तापक्ष और विपक्ष के नेताओं ने सवालों की झड़ी लगा दी। प्रदेश के 230 में से 162 विधायकों ने सत्र के दौरान सवाल पूछे हैं। वहीं शेष 68 विधायक चुप्पी साधे रहे। यानी उन्होंने एक भी सवाल नहीं किया है। यही नहीं सत्र के...

अपराध

18 | सौरभ शर्मा के बाद करीबियों...

मप्र परिवहन विभाग के करोड़पति पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा की प्रॉपर्टी अप्रैल में अटैच की गई थी। ईडी ने इसे लेकर चालान भी पेश किया था। अब आयकर विभाग सौरभ की अटैच प्रॉपर्टी का ब्यौरा खंगालने की तैयारी में है। बता दें कि विभाग की बेनामी विंग ने सौरभ शर्मा, उसके सहयोगी...

आवरण कथा 24, 25, 26, 27, 28

अपनी मनमानी नीतियों के कारण विश्व के अन्य देशों पर टैरिफ लगाकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दादागिरी करने का जो अभियान चलाया है, उसका परिणाम यह देखने को मिल रहा है कि अमेरिका की बादशाहत ही खतरे में पड़ गई है। अमेरिका की सबसे बड़ी चुनौती भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाने के बाद शुरू हुई है, क्योंकि इसके बाद विश्व में महाशक्तियों का त्रिकोण बनने लगा है। यानि भारत, रूस और चीन एक साथ आ गए हैं। इससे ब्रिक्स सहित अन्य देश महाशक्ति के त्रिकोण...

राजनीति

30-31 | बिहार में आर-पार

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले राज्य का चुनावी माहौल गरमा गया है। संसद से लेकर सड़क तक घमासान मचा हुआ है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने जनता को साधने के लिए वोटर अधिकार यात्रा निकाली है। इस यात्रा में गठबंधन के नेताओं ने लोगों से सीधे संवाद किया...

महाराष्ट्र

35 | खुद डूबे और उद्धव को...

बीएमसी चुनाव से पहले उद्धव और राज ठाकरे को बड़ा झटका लगा है। करीब दो दशक बाद साथ आए ठाकरे बंधु को बृहन्मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट (बेस्ट) क्रेडिट सोसायटी के चुनाव में करारी शिकस्त मिली है। शिवसेना और एमएनएस का पैनल 21 सीटों पर चुनाव लड़ा...

बिहार

38 | सीट बंटवारे पर उठा-पटक

बिहार विधानसभा चुनाव अक्टूबर-नवंबर के बीच कराए जा सकते हैं। उससे पहले राजनीतिक पार्टियां सीट शेयरिंग फॉर्मूला बैठाने में लगी हुई हैं। सूबे के सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) में सीटों के बंटवारे पर विचार-विमर्श...

6-7 अंदर की बात
41 महिला जगत
42 अध्यात्म
43 कहानी
44 खेल
45 फिल्म
46 व्यंग्य

पाक्षिक अक्स

वर्ष-23, अंक-23, पृष्ठ-48
1 से 15 सितंबर, 2025

प्रकाशक एवं संपादक : राजेन्द्र आगाल

सम्पादकीय कार्यालय :
प्लाट नम्बर 150, जोन-1 मनोरमा कॉम्पलेक्स,
एफ-03, 04, प्रथम तल, एम.पी. नगर
भोपाल- 462011 (म.प्र.),
टेलीफेक्स - 0755-4017788

email : akshmagazine@gmail.com
Website : www.akshnews.com
RNI NO. HIN/2002/8718 MPBPL/642/2021-23

प्रमुख संवाददाता

भावना सक्सेना-भोपाल, जय मतानी-भोपाल,
हर्ष सक्सेना-भोपाल,
दक्ष दवे-इंदौर, संदीप वर्मा-इंदौर,
विपिन कंधारी-इंदौर, गौरव तिवारी-विदिशा,
ज्योत्सना अनूप यादव-गंजबासौदा, राजेश तिवारी-उज्जैन,
टोनी छाबड़ा-धार, आशीष नेमा-नरसिंहपुर,
अनिल सोडानी-नई दिल्ली, हसमुख जैन-मुंबई,
इंद्र कुमार बिन्नानी-पुणे।

प्रदेश संवाददाता

पारस सरावगी (इंदौर)
09329586555
नवीन रघुवंशी (इंदौर)
09827227000 (इंदौर)
धर्मेन्द्र कथूरिया (जबलपुर)
098276 18400
श्यामसिंह सिकरवार (उज्जैन)
094259 85070
सुभाष सोमानी (रतलाम)
089823 27267
मोहित बंसल (विदिशा)
075666 71111

क्षेत्रीय कार्यालय

नई दिल्ली : ईसी 294 माया इंक्लेव मायापुरी, फोन : 9811017939
जयपुर : सी-37, शांतिपथ, श्याम नगर (राजस्थान) मोबाइल-09829 010331
भिलाई : नेहरू भवन के सामने, सुपेला, रामनगर, भिलाई, मोबाइल 094241 08015
देवास : जय सिंह, देवास मो.-7000526104, 9907353976

स्वात्वाधिकारी, मुद्रक व प्रकाशक, राजेन्द्र आगाल द्वारा आगाल प्रिंटर्स, प्लाट नं. 150, जोन-1, प्रथम तल, एफ-03, मनोरमा काम्पलेक्स, एम.पी. नगर भोपाल 462011 (म.प्र.), से मुद्रित एवं प्रकाशित

इस अंक में प्रकाशित सामग्री लेखकों के अपने विचार हैं इनसे सम्पादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं हैं समस्त विवादों के लिए न्याय क्षेत्र भोपाल होगा।

अपनी बात

आखिर कैसे कायम रहेगा सुशासन...?

लोकतंत्र में राजनेताओं को लेकर किसी ने क्या खूब लिखा है...

सत्ता के सिंघासन पर भी, श्रम जिसका अविराम रहेगा,
कीचड़-सी राजनीति में, कमल के जैसा काम रहेगा।

लेकिन उपरोक्त पंक्तियां चाल, चरित्र और चेहरे वाली पार्टी के कुछ माननीय तार-तार कर रहे हैं। जिस पार्टी के राजनेता और पूर्व प्रधानमंत्री स्व. अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है, उसी पार्टी के नेता सुशासन की परिकल्पना को मिटाने में लगे हैं। देश में मप्र का भाजपा संगठन सबसे संस्कारी माना जाता है, लेकिन पिछले कुछ समय से पार्टी के विधायकों, सांसदों और नेताओं के बोल पार्टी की गरिमा को धूमिल कर रहे हैं। गौरतलब है कि मप्र के जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह के कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर दिए विवादित बयान से देशभर में भाजपा की किरकिरी हुई। इसके बाद पचमढ़ी में 14 से 16 जून के बीच प्रशिक्षण शिविर में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह सहित कई बड़े नेताओं ने सांसद-विधायकों और मंत्रियों को यह समझाया कि क्या बोलना है, क्या नहीं। हालांकि इसका कोई असर होता नहीं दिख रहा। अपनी ही सरकार को कठघरे में खड़ा करने वाले बयान थम नहीं रहे हैं। माननीय अपने बिगड़े बोल और उटपटांग हरकतों के कारण पार्टी के लिए मुश्किल खड़ी कर रहे हैं। भाजपा देश की सबसे सुसंस्कृत और शिष्ट पार्टी मानी जाती है। पार्टी की बराबर कोशिश रहती है कि नेता पार्टी की गाइडलाइन के अनुसार काम करें। लेकिन भाजपा नेताओं के चाल, चेहरा और चरित्र पर सवाल उठने लगे हैं। इसको लेकर पचमढ़ी में भाजपा ने तीन दिन के संवाद कौशल प्रशिक्षण आयोजित किया था। इसमें नेताओं को सुशासन का पाठ पढ़ाया गया था, लेकिन ऐसा लगता है कि प्रशिक्षण वर्ग में मिली सीख का भी पार्टी के जनप्रतिनिधियों पर कोई असर नहीं हुआ। यही वजह है कि आए दिन भाजपा के जनप्रतिनिधि अधिकारियों से अभद्रता करने के साथ सार्वजनिक बयानबाजी करके पार्टी ही नहीं, सरकार की भी जमकर किरकिरी करा रहे हैं। गौरतलब है कि प्रदेश अध्यक्ष बनते ही हेमंत खंडेलवाल ने दो टूक कहा था कि दाएं-बाएं होने वाले जनप्रतिनिधियों की खैर नहीं। वह अपने डेढ़ माह के कार्यकाल में संघ की कार्यपद्धति का उदाहरण देकर जनप्रतिनिधियों को बार-बार अनुशासन का पाठ पढ़ा रहे हैं, लेकिन भिंड जिले में कलेक्टर के साथ भाजपा विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाह द्वारा अभद्रता की गई। इस घटना ने यह साफ कर दिया है कि सीख का जनप्रतिनिधियों पर कोई असर नहीं हुआ है। वहीं गुना के चांचौड़ा से भाजपा विधायक प्रियंका पैची ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कहा था कि गुना के एसपी अंकित सोनी मंत्री-विधायक की सलाह के बिना ही पुलिसकर्मियों के स्थानांतरण कर रहे हैं। उन्होंने यह तक कहा कि रोज नई-नई कहानियां गढ़कर एसपी और चांचौड़ा एसडीओपी उन्हें प्रताड़ित कर रहे हैं। मुख्यमंत्री से उन्होंने तुरंत कार्रवाई का अनुरोध किया था। मई में लिखा पत्र सार्वजनिक होने के बाद बड़े नेताओं को दखल देना पड़ा। पैची को पार्टी कार्यालय बुलाकर समझाइश दी थी। दमोह में भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष प्रीतम सिंह लोधी ने सार्वजनिक कार्यक्रम में भाजपा नेता संजय सेन और उनकी पत्नी कविता राय से जमकर बहस की थी। संचालन कर रहे संजय सेन ने प्रीतम लोधी का नाम नहीं लिया, इस बात से विवाद इतना बढ़ा कि पुलिस बुलानी पड़ी। मामला प्रदेश संगठन तक पहुंचा। 16 जून को हटा विधानसभा क्षेत्र में स्थित एक अस्पताल में विवाद के बाद थाने के घेराव में प्रीतम लोधी ने कहा कि उसी को सांसद-विधायक चुनें जो लोधी समाज के साथ खड़ा रहे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल का कहना है कि कुछ घटनाएं सामने आई हैं, उसको लेकर हिदायत दी है हाल ही में एक-दो मामले सामने आए हैं, उनको भी पार्टी गंभीरता से संज्ञान ले रही है। इनमें जो भी निर्णय करना होगा या निर्देश देना होगा, वह करेंगे।

- राजेन्द्र आगाल

पत्र–संपादक के नाम

akshnews.com

अफसरों पर कार्यवाही हो

कैग की रिपोर्ट के मुताबिक, किसानों के सहकारी विकास के लिए तय 5.31 करोड़ रुपए में से 90 प्रतिशत यानी 4.79 करोड़ रुपए अफसरों ने लग्जरी गाड़ियां खरीदने में खर्च कर दिए। सरकार को ऐसे भ्रष्ट अफसरों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करनी चाहिए।

● **आनंद तिवारी,** आगर (म.प्र.)

राजस्व हानि कम हो

साल 2020-21 की शराब नीति को 1 अप्रैल से लागू किया गया, लेकिन चार महीने बाद अगस्त में इस नीति को कैंसिल कर दिया। इससे सरकार को 471.38 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान हुआ। जो अभी तक नहीं मिला है। सरकार को राजस्व हानि को कम करने के लिए नीति लानी चाहिए।

● **रूपेश नागफंसे,** भोपाल (म.प्र.)

8 हजार गांवों को मिलेगा पानी

मप्र में जल जीवन मिशन में छूटे करीब 8 हजार गांवों में नलों से पानी की सप्लाई का रास्ता साफ हो गया है। इसमें खर्च होने वाली पूरी राशि राज्य सरकार वहन करेगी। इस पर करीब 2,800 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सरकार के इस कदम से 7.5 लाख घरों को पानी पहुंचेगा, जो सराहनीय है।

● **जुबेर खान,** इंदौर (म.प्र.)

प्रकृति से न हो खिलवाड़

उत्तराखंड में उत्तरकाशी के धराली में बादल फटने के बाद अचानक आई बाढ़ ने एक झटके में पूरे गांव को उजाड़ दिया। ऐसा ही कुछ हिमाचल प्रदेश में मंडी जिले के सराज में भी देखने को मिला। इन आपदाओं ने हमें एक बार फिर चेतावनी दी है कि हिमालय जैसे संवेदनशील इलाकों में जलवायु परिवर्तन और मानवीय गलतियां मिलकर तबाही मचा रही हैं। बादल फटने का पैटर्न बदल रहा है। ऊंचे इलाकों में होने वाली ऐसी घटनाएं अब नीचे बसे गांवों को प्रभावित कर रही हैं। धराली की 54 करोड़ साल पुरानी ढीली मिट्टी और खड़ी ढलानें इसे और जोखिम में डालती हैं। क्या प्रकृति हमें चेतावनी दे रही है कि हम उसके साथ खिलवाड़ न करें। अगर ऐसा है तो हमें इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

● **प्राची गावटे,** गुना (म.प्र.)

भाजपा को बनाना होगा समन्वय

भाजपा ने सत्ता में बने रहने के लिए जिस तरह से अलग-अलग विचारधाराओं के नेताओं और कार्यकर्ताओं को पार्टी से जोड़ा उससे पार्टी के अंदर ही अंदर काफी रोष फैला हुआ है। इसके अलावा भाजपा अगड़ी जातियों का प्रतिनिधित्व करती रही है। अब सत्ता में बने रहने के लिए भाजपा को जिस तरह से एससी और ओबीसी जातियों की जी-हुजूरी करनी पड़ रही है, उससे अगड़ी जातियों के नेता और कार्यकर्ता कसमसा रहे हैं। भाजपा को इन सभी वर्गों के बीच समन्वय बनाकर रखना होगा, ताकि भविष्य में उसे तकलीफ न हो।

● **हीना कुरैशी,** मुरैना (म.प्र.)

प्रदर्शन में उलझा रहा विपक्ष

विधानसभा, सरकार और विपक्ष के लिए अपनी बात रखने का सबसे उपयुक्त मंच होता है। मानसून सत्र में विपक्ष के पास भरपूर अवसर था कि वह वजनदारी से सदन में मुद्दे उठाता और सरकार को मजबूर करता कि वह जवाब दे लेकिन इसके स्थान पर पूरा विपक्ष प्रदर्शन में उलझा रहा। विधानसभा के मानसून सत्र में सत्तापक्ष को घेरने कांग्रेस ने कमोबेश हर दिन नए-नए स्टंट किए। लेकिन एक मजबूत विपक्ष के तौर पर अपने आपको साबित नहीं कर पाई।

● **जीवन यादव,** ग्वालियर (म.प्र.)

पाठकों से निवेदन

कृपया अपनी प्रतिक्रियाएं पक्ष या विपक्ष जो भी संभव हो इस पते पर भेजें

अक्स

150 जोन-1, मनोरमा काम्पलेक्स,
एफ-02, 03, एमपी नगर, भोपाल

विदेश नीति का मजाक!

पिछले 11 साल में अमेरिका, चीन, रूस से पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव तक के भारत रिश्तों पर अपनी विदेश नीति का क्या अर्थ बना है? चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को झूला झुलाने से लेकर नवाज शरीफ के घर जाकर पकौड़े खाने से अबकी बार ट्रंप सरकार के नारे का वह एक सिलसिला, जिससे दुनिया में सिर्फ यह साबित हुआ है कि भारत का कोई अर्थ नहीं है फिर भले भारत का विदेश मंत्रालय दुनिया के देशों से अपने प्रधानमंत्री को चाहे जितने राष्ट्रीय सम्मान दिलाए। भारत तो एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम तक झूला झूलने की विदेश नीति में देश के रक्षा-सामरिक हितों तक का भी ध्यान नहीं रखता। इसी मई में, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, चीन और उसके सेनाधिकारी इस्लामाबाद में बैठकर पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल मुनीर को गाइड करते थे। भारत के खिलाफ पाकिस्तानी सेना को चीन लड़ाकू विमान और मिसाइल, सैटेलाइट बैकअप देता था। दुनिया ने तब देखा और जाना कि चीन और पाकिस्तान किस हद तक एक-दूसरे के सगे हैं। तब रूस भी पाकिस्तान का ही सगा था। भारत के लिए वह नहीं बोला। वह तटस्थ रहा। इसलिए क्योंकि यह अब वैश्विक सत्य है कि चीन उसका आज मालिक है। चीन के दम पर ही राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन से लड़ रहे हैं।

देश कांग्रेस मॉडल पर ही चल रहा है!

कांग्रेस के नेता राहुल गांधी इन दिनों मूर्तिभंजन में लगे हैं। वे प्रतिमाओं के सिंदूर खरोंच रहे हैं। वे इस संकल्प और रणनीति के साथ काम कर रहे हैं कि अगर हम चुनाव नहीं जीत सकते हैं तो चुनाव की पूरी प्रक्रिया को संदिग्ध बना दिया जाए। अगर हम किसी मुकदमे में फंसे हैं तो जांच की पूरी प्रक्रिया और हर जांच एजेंसी को संदिग्ध बना दिया जाए। अगर हमारी खबरों को प्रमुखता से जगह नहीं मिलती है तो मीडिया की साख को संदिग्ध बना दिया जाए। अगर कारोबारी हमें चंदा नहीं देते हैं या कम देते हैं तो सभी कारोबारियों को क्रोनी कैपिटलिस्ट साबित कर दिया जाए। अगर अधिकारी हमें सलामी नहीं देते हैं तो पूरी नौकरशाही को भ्रष्ट और सरकार का पिछलग्गू बता दिया जाए। अगर न्यायपालिका से मनमाफिक फैसला नहीं आता है तो उसे सरकार के लिए प्रतिबद्ध बता दिया जाए। इस तरह वे हर संस्था को तहस-नहस करने की दिशा में बढ़ गए हैं। ऐसी अराजक राजनीति कुछ समय पहले आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल ने शुरू की थी। हालांकि मुख्यमंत्री रहने और दो राज्यों में सरकार बनाने के बाद उनकी राजनीति में ठहराव आ गया है। अब राहुल गांधी ने केजरीवाल की राजनीतिक किताब का एक पन्ना खोलकर उसे पढ़ना शुरू किया है।

चुनाव आयोग की साख को बट्टा

देश में गिनी चुनी संस्थाएं थीं, जिनके कामकाज को देश के अंदर और बाहर भी सराहा जाता था। उनमें एक संस्था चुनाव आयोग था। टीएन शेषन के समय लोगों ने जाना कि चुनाव आयोग एक संस्था होती है और वह चाहे तो सरकारों को कुछ भी करने के लिए मजबूर कर सकती है। लेकिन अब चुनाव आयोग खुद एक ऐसी मजबूर संस्था दिख रही है, जिस पर दया आती है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने दोनों चुनाव आयुक्तों के साथ पिछले दिनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उसकी ऐसी दयनीयता सामने आई, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। विपक्ष के आरोपों पर ऐसे-ऐसे बेसिरपैर के तर्क दिए जा रहे थे, जैसे तर्क टेलीविजन की बहसों में पार्टी के प्रवक्ता भी नहीं देते हैं। चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नेता प्रतपिक्ष राहुल गांधी को धमकाया कि आपने जो आरोप लगाए हैं उन्हें हलफनामे के साथ चुनाव आयोग के सामने दायर करें या देश से माफी मांगें। सोचें, पहले चुनाव आयोग सिर्फ एक लाइन कह देता था कि आरोपों की जांच कराई जाएगी और मामला खत्म हो जाता था। अब आयोग को हलफनामा चाहिए तब जांच होगी! चुनाव आयोग की साख और हैसियत ऐसी हो गई है कि विपक्षी पार्टियों के नेता खुलेआम उसे धमकी दे रहे हैं।

संसद की क्या हालत हो गई!

संसद का मानसून सत्र समाप्त हुआ। समापन के बाद बताया गया कि कितना कामकाज हुआ। अगर उस हिसाब से देखेंगे तो लगेगा कि संसद का सत्र काफी उपलब्धियों वाला रहा क्योंकि एक महीने के इस सत्र में लोकसभा में 12 और राज्यसभा में 15 विधेयक पास हुए। ऑनलाइन गेमिंग रोकने से लेकर स्पोर्ट्स और डोपिंग से जुड़े बिल पास हुए तो जहाजरानी मंत्रालय से जुड़ा बिल भी पास हुआ। नए आयकर कानून को दोबारा पेश करके पास कराया गया। इसके अलावा गिरफ्तारी या 30 दिन की हिरासत पर मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों और प्रधानमंत्री को कुर्सी से हटाने के लिए तीन विधेयक भी पेश किए गए, जिनको संसद की संयुक्त समिति के पास भेज दिया गया। इस लिहाज से दिखेगा कि संसद में कामकाज हुआ है। लेकिन इन पर बहस, विचार कितना हुआ है। अफसरों ने बिल बनाए, कैबिनेट ने ठप्पा लगाया और जनप्रतिनिधियों की बिना बहस, विचार, संशोधनों के बिल पास हो गए। लोकसभा और राज्यसभा में जो पास हुए हैं वो सारे बिल बिना किसी चर्चा के हुए हैं।

मंत्रियों का मामला...

भारत सरकार के मंत्रियों की क्या हैसियत हो गई है? राष्ट्रीय अध्यक्ष की हैसियत के नेता नरेंद्र मोदी के लिए माला पकड़कर खड़े होते हैं। उस माला में घुसने की इजाजत उनको नहीं होती है। यह धारणा बनी है कि ले देकर एक अमित शाह हैं, जिनकी कोई हैसियत है लेकिन संसद के मानसून सत्र में यह भी दिखा कि पक्ष और विपक्ष में उनकी हैसियत पर ही चिंदियां गिरती दिखीं। वे गिरफ्तारी और 30 दिन की हिरासत पर मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों और प्रधानमंत्री को कुर्सी से हटाने वाला विधेयक पेश कर रहे थे तो उसे उन्होंने अगली पंक्ति में अपनी निर्धारित सीट से पेश नहीं किया, बल्कि चौथी पंक्ति में अपने सांसदों के बीच खड़े होकर पेश किया। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि डर के मारे अमित शाह ने चौथी लाइन में खड़े होकर बिल पेश किया। जिस समय वे बिल पेश कर रहे थे उस समय विपक्ष की ओर से बिल की प्रति फाड़ी गई और कागज के गोले बनाकर उनकी ओर उछाले गए।

दो कप्तानों ने कराई किरकिरी

जिलों में कानून व्यवस्था की कमान संभालने की जिम्मेदारी जिन आईपीएस अधिकारियों के पास होती है, कभी-कभार वे अपनी करतूतों से सरकार की जमकर किरकिरी कराते हैं। ऐसे ही दो कप्तान इन दिनों चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। इत्तेफाक से दोनों विंध्य क्षेत्र के जिलों में पदस्थ हैं। इनमें से एक 2018 बैच के आईपीएस अधिकारी जबसे विंध्य क्षेत्र के एक जिले में कप्तान बने हैं, उनकी चाल-ढाल ही बदल गई है। अक्सर लोग उन्हें सड़कों पर लहराते देखकर चौंक जाते हैं। लोगों का कहना है कि साहब सूखा नशा करने के आदी हो गए हैं। वे जब भी जिला मुख्यालय पर भ्रमण के लिए निकलते हैं, तो सूखे नशे की कश लगाकर निकलते हैं। कई बार तो स्थिति ऐसी हो जाती है कि वे लोगों से पूछ लेते हैं कि क्या मैं नशे में हूं। लोग उनका सवाल सुनकर चौंक जाते हैं। वहीं दूसरे 2012 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। आरोप लगाया जा रहा है कि कप्तान साहब के संरक्षण में नशे का पूरा कारोबार चल रहा है। कप्तान के खिलाफ लगातार शिकायतें प्रशासनिक वीथिका तक पहुंच रही हैं। गत दिनों तो एक विधायक ने उनकी काली कमाई का हिसाब-किताब मंच से उवाच दिया। इससे सरकार की सुशासन वाली छवि धूमिल हो रही है। सूत्रों का कहना है कि अब कप्तान साहब की काली कमाई का हिसाब-किताब लगाने के लिए पड़ताल कराई जा रही है।

अफसर की जमीन भी नहीं छोड़ी

मप्र में एक तरफ सरकार सुशासन पर जोर दे रही है, वहीं दूसरी तरफ सत्तारूढ़ पार्टी के कुछ माननीय ऐसे हैं, जो सरकार और संगठन के दिशा-निर्देशों को दरकिनार कर कमाई में जुटे हुए हैं। ऐसे ही एक माननीय इन दिनों राजनीतिक और प्रशासनिक वीथिका में चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। शोबाजी करने वाले नेताओं की श्रेणी में इनकी गणना सबसे ऊपर होती है। आए दिन आयोजनों के नाम पर ये अपने विधानसभा क्षेत्र में चंदा वसूली करते रहते हैं। यह तो उनकी पुरानी परिपाटी है, लेकिन इनकी सबसे अधिक चर्चा इस बात पर हो रही है कि इन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र में उगाही के लिए तरह-तरह के हथकंडे अपना रखे हैं। इनमें से एक है जमीनों को हड़पना। सूत्रों का कहना है कि उनकी इस आदत से आम लोग तो परेशान हैं ही, प्रशासनिक अधिकारी भी शिकार बन रहे हैं। बताया जाता है कि उन्होंने एक एक्जीक्यूटिव कलेक्टर की जमीन पर हाथ डाला है। उन्होंने साफ-साफ शब्दों में कह दिया है कि इस जमीन के लिए 50 हजार रुपए महीना किराया दो, नहीं तो बुलडोजर चलवा देंगे। सूत्र बताते हैं कि माननीय अपने क्षेत्र में बुलडोजर की धमकी देकर जमकर उगाही कर रहे हैं।

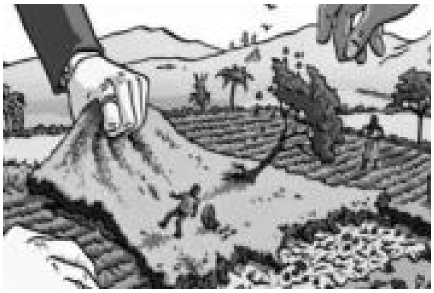

धंधा लेने कुछ भी करेंगे

प्रदेश के एक सबसे बड़े कारोबारी अपने पुराने कारोबार के अलावा अन्य धंधों में भी हाथ डाल रहे हैं। बताया जाता है कि दूसरे धंधों को लेने के लिए वे तरह-तरह के हथकंडे भी अपना रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि वर्तमान में उक्त कारोबारी स्वास्थ्य विभाग से जुड़े एक संस्थान को कब्जाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। जिस संस्थान का संचालन करने के लिए वे हाथ-पांव मार रहे हैं, उक्त संस्थान मेडिकल इक्यूपमेंट सप्लाई करता है। इसके लिए वे राजनीतिक और प्रशासनिक संपर्कों का सहारा ले रहे हैं। गौरतलब है कि उक्त कारोबारी देश के प्रख्यात सड़क, पुल आदि निर्माता कंपनी चलाते हैं। उक्त कंपनी विदेशों में भी निर्माण कार्य करती है। सूत्रों का दावा है कि एक राजनेता के संरक्षण में फर्श से अर्श पर पहुंची उक्त कंपनी का मूल कारोबार इस समय अच्छा नहीं चल रहा है। इसकी एक वजह यह है कि उनको राजनीतिक संरक्षण देने वाले राजनेता से उनकी दूरियां बढ़ गई हैं। ऐसे में कारोबारी इस कोशिश में लगे हुए हैं कि मूल कारोबार के अलावा अन्य काम भी किया जाए, ताकि रसूख बना रहे। अब देखना यह है कि उक्त कारोबारी अपने मिशन में सफल हो पाते हैं या नहीं। यहां यह बता दें कि गत 15 सालों के दौरान उक्त कारोबारी का काम-धंधा मप्र में इस तेजी से बढ़ा था कि उनकी गिनती देश के बड़े कारोबारियों में होने लगी थी। लेकिन इस समय उनका काम-धंधा कमजोर पड़ा हुआ है।

नहीं बदला अफसरों का मन

मप्र की प्रशासनिक वीथिका में इन दिनों यह चर्चा जोरों पर हो रही है कि प्रदेश के कुछ ब्यूरोक्रेट्स पूर्व मुख्यमंत्री के मोहफांस में इस कदर फंसे हैं कि उससे बाहर नहीं आ पा रहे हैं। भले ही शासन और प्रशासन का चेहरा बदल गया है, लेकिन अफसर अभी भी पुरानी सरकार के प्रति वफादारी निभाने में लगे रहते हैं। सूत्रों का कहना है कि पूर्व मुख्यमंत्री के शासनकाल में जमकर मलाई खाने वाले कुछ अफसर गाहे-बगाहे उनका गुणगान गाने का मौका नहीं चूक रहे हैं। यानी सरकार भले ही बदल गए हैं लेकिन कुछ अफसरों का मन अभी भी नहीं बदला है। ऐसे कुछ अफसरों को वर्तमान में भी बड़े पद मिले हैं, लेकिन उनकी वफादारी पूर्व मंत्री के साथ ही हैं। सूत्रों का कहना है कि ऐसे ही कुछ अफसर वर्तमान सरकार के खिलाफ माहौल बनाने की लगातार कोशिश करते रहते हैं। बताया जा रहा है कि सरकार को इसकी भनक लग गई है और ऐसे अफसरों को सूचीबद्ध किया जा रहा है। सूत्र बताते हैं कि जल्द ही ऐसे अफसरों की पहले क्लास लगाई जाएगी, फिर उन्हें उनकी गलती का अहसास कराकर लूपलाइन में डाल दिया जाएगा।

सृजन अभियान बना विसर्जन

देश का हृदय प्रदेश मप्र राजनीति का भी केंद्र है। माना जाता है कि इस राज्य में जो पार्टी दमदार होती है, उसका देशभर में प्रभाव पड़ता है। इसको देखते हुए कांग्रेस आलाकमान ने मप्र में संगठन को मजबूत करने के लिए अभियान चलाया था। राहुल गांधी द्वारा कांग्रेस को नए सिरे से तैयार करने के लिए लागू किए गए संगठन सृजन अभियान का परिणाम सामने आ गया है। इस परिणाम के सामने आने के बाद कांग्रेस के नेता ही यह सवाल उठाने लगे हैं कि यह सृजन है या विसर्जन है। सूत्रों का कहना है कि पहले से ही इस बात की आशंका थी कि कांग्रेस के नेताओं ने इस पूरे अभियान को हाईजैक कर लिया है। हर नेता अपने समर्थक को पद पर बैठाने के लिए नियम-कायदे को दरकिनार करवाने में लगा हुआ है। अब जब इस अभियान के तहत सभी जिला तथा शहर कांग्रेस अध्यक्ष की सूची जारी हुई है तो यह स्पष्ट हो गया है कि कार्यकर्ताओं की भावना, जनता के बीच में इमेज के आधार पर अध्यक्ष के चुनाव का दावा कागजी था। जिसका कोई नाम लेने वाला भी नहीं था, उसे अध्यक्ष बना दिया गया।

बढ़ रही अफसर-विधायकों में तकरार

मप्र में अफसरों और जनप्रतिनिधियों के बीच टकराव की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। भिंड में कलेक्टर के विधायक को उंगली दिखाने पर विधायक द्वारा कलेक्टर पर मुट्ठी तानने तक ही स्थिति बन गई। इससे पहले भाजपा के तीन अन्य डिंडौरी, चाचौड़ा और पिछोर विधायक भी जिलों के कलेक्टर और एसपी से आमने-सामने आ चुके हैं। कहीं कलेक्टर पर जनसुनवाई नहीं करने और विकास कार्य रोकने के आरोप लगे हैं तो कहीं एसपी पर मनमानी के मामले में शिकायत की गई। ऐसे में प्रदेश में लगातार अधिकारियों और भाजपा विधायकों के साथ हो रही घटनाओं ने उनके आपसी संबंधों पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

भिंड कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव के साथ भाजपा विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाह द्वारा किए गए आचरण पर मप्र आईएएस एसोसिएशन ने चिंता व्यक्त की है। एसोसिएशन के अध्यक्ष मनु श्रीवास्तव ने कहा कि इस संबंध में मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव से चर्चा कर रहे हैं। किसी भी अधिकारी के साथ इस तरह का व्यवहार अनुचित और चिंतनीय है। दरअसल, भिंड से भाजपा विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाह ने खाद संकट को लेकर समर्थकों के साथ कलेक्टर बंगले के बाहर धरना-प्रदर्शन किया था। जब कलेक्टर विधायक से मिलने बंगले से बाहर निकले तो गेट पर ही विधायक कुशवाह ने कलेक्टर पर हाथ उठाया, उन्हें मारने की कोशिश की। सुरक्षाकर्मियों ने कलेक्टर को बचाया। इस दौरान विधायक समर्थकों ने कलेक्टर चोर के नारे लगाए। पूरे घटनाक्रम का वीडियो वायरल हो रहा है। किसी कलेक्टर या प्रशासनिक अधिकारी के साथ की गई अभद्रता का यह पहला प्रकरण नहीं है। इससे पहले भी बड़वानी कलेक्टर काजल जावला को हटाने के लिए मंत्री गौतम टेटवाल मुख्यमंत्री को पत्र लिख चुके हैं। इसी तरह मंडला विधायक नारायण सिंह पट्टा ने प्रशिक्षु आईएएस एसडीएम आकिब खान पर घर में घुसकर विधायक की मां को धक्का देने का आरोप लगाया था। भोपाल सांसद आलोक शर्मा नगर निगम आयुक्त हरेंद्र नारायण पर फोन न उठाने का आरोप लगा चुके हैं। वहीं राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल अवैध शराब मामले में रायसेन कलेक्टर को घेर चुके हैं।

भाजपा विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाह का लंबा आपराधिक इतिहास रहा है। वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव में उनके शपथ पत्र में दी गई जानकारी के अनुसार कुशवाह के विरूद्ध लोक सेवक को उसके कर्तव्य निर्वहन से रोकने के लिए हमला या आपराधिक बल प्रयोग से संबंधित छह महीने की सजा भी सुनाई जा चुकी है। अभी यह मामला अपील में है। भिंड देहात थाने का आईपीसी धारा-342, 506बी, 504, 34 का एक मामला विचाराधीन है। शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करने और दंगा करवाने के मामले में भी अपराध दर्ज रहा है। एसटी-एससी एक्ट, अगवा कर मारपीट करने जैसे मामले भी कुशवाह के खिलाफ दर्ज हैं। भिंड कलेक्टर के साथ भाजपा विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाह द्वारा घूंसा मारने के प्रयास से अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी नाराज हैं। अधिकारियों ने कहा कि सरकारी कामकाज में बाधा डालने और कलेक्टर के साथ गाली-गलौज करने के मामले में विधायक कुशवाह के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाना चाहिए। उन्होंने विधायक को गिरफ्तार किए जाने की भी मांग की है। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर मप्र आईएएस एसोसिएशन ने नाराजगी जताई है। मप्र आईएएस एसोसिएशन ने कहा कि वे इस मामले में मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव से मिलकर अपनी बात रखेंगे।

दरअसल, कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव द्वारा अवैध खनन को रोकने की दिशा में की गई सख्ती के कारण विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाह नाराज हैं। विधायक को यह पसंद नहीं कि रेत परिवहन कर रही गाड़ियों को कोई रोके। इसी बात के लिए वह कलेक्टर को पहले भी फोन पर धमका चुके थे। ग्वालियर-चंबल में अवैध खनन को रोकना या रेत परिवहन की गाड़ियों के विरूद्ध कार्रवाई करना आसान नहीं है। वर्ष 2012 में रेत परिवहन को रोकने में अखिल भारतीय पुलिस सेवा के प्रशिक्षु अधिकारी नरेंद्र कुमार की जान जा चुकी है। खनन माफिया ने नरेंद्र पर ट्रैक्टर-ट्राली चढ़ा दी थी। उनकी पत्नी आईएएस मधुरानी तेवतिया अभी दिल्ली में पदस्थ हैं। कलेक्टर पर विधायक द्वारा किए गए हमले का मामला मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और मुख्य सचिव के पास पहुंच गया है। फिलहाल इस मामले में सीधे तौर पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। बताया गया कि भिंड कलेक्टर से घटना की रिपोर्ट मांगी है। इधर, भाजपा संगठन ने भी विधायक के व्यवहार पर चिंता जाहिर की है। हालांकि मप्र भाजपा ने अधिकृत रूप से इस मामले में बयान नहीं दिया है। घटना को लेकर विधायक को तलब कर हिदायत दी जा सकती है।

● सुनील सिंह

पचमढ़ी का प्रशिक्षण भी नहीं आ रहा काम

भाजपा ने अपने नेताओं और जनप्रतिनिधियों के बयान और जनता के बीच आचरण को लेकर पचमढ़ी में प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया था। इस शिविर में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह शामिल हुए थे। उन्होंने पार्टी के मंत्री, विधायक, सांसदों और संगठन के पदाधिकारियों और जिम्मेदार पदों पर बैठे नेताओं को अपने आचरण और वक्तव्यों में सावधानी रखने की सीख दी थी, लेकिन भिंड में कलेक्टर और विधायक के बीच ताजा तकरार के वीडियो से उस पर अमल होता दिख नहीं रहा है। जानकारों का कहना है कि ये सब घटनाएं सामने आ रही हैं, इसका कारण बड़ा स्पष्ट है कि सरकार और प्रशासन में समन्वय ही नहीं है। यदि सरकार की तरफ से अफसरों को संदेश हो कि हमारे जनप्रतिनिधियों से कैसे बातचीत करना है तो ऐसी नौबत ही नहीं आए। इसके अलावा ऐसी घटनाएं यह भी बताती हैं कि सरकार की पकड़ कमजोर है। इसलिए नौकरशाह हावी हो रहे हैं।

बिजली विभाग में नियुक्तियों की बहार

मप्र में युवाओं को सरकारी नौकरी उपलब्ध कराने के लिए सरकार की ओर से प्रयास जारी है। इसी कड़ी में विभिन्न विभागों में रिक्त पदों को भरा जा रहा है। इसी क्रम में बिजली विभाग में एक हजार से ज्यादा लोगों को नियुक्ति पत्र दिए गए। वहीं, आने वाले समय में 51 हजार और नियुक्तियां की जानी हैं। राजधानी भोपाल के रवींद्र भवन में आयोजित समारोह में छह विद्युत कंपनियों के नवनियुक्त 1,060 कार्मिकों को नियुक्ति-पत्र वितरित किए गए। वहीं, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का अभिनंदन किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा है कि वर्तमान युग में विद्युत (ऊर्जा) का महत्व वायु और जल के समान है। प्रदेशवासियों की बिजली की मांग के साथ देश की बिजली की जरूरत को भी पूरा कर रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली की मेट्रो ट्रेन मप्र की बिजली से चल रही है। अब इस तरह की योजना बनाई जा रही है कि वर्ष 2047 तक बिजली की कोई कमी नहीं होगी, प्रदेश ऊर्जा क्षेत्र में सरप्लस रहेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में क्लीन एनर्जी के लिए गतिविधियों का विस्तार हो रहा है। प्रदेश में पिछले 11 वर्षों में सौर ऊर्जा 30 प्रतिशत बढ़ी है। बिजली कंपनियों की ओर से एक हजार से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे हैं। प्रदेश की बिजली कंपनियों में 51 हजार से अधिक नए पद भरे जाएंगे। इससे बिजली कंपनियों की स्थिति सुदृढ़ होगी। किसान भाइयों को लगभग 20 हजार 267 करोड़ रुपए की सब्सिडी इस वर्ष दी जा रही है। प्रदेश के एक करोड़ से अधिक परिवारों को बिजली विभाग ने 6445 करोड़ रुपए की सब्सिडी प्रदान की है। प्रदेश में बिजली तैयार करने के लिए हर उपलब्ध संसाधन का उपयोग किया जा रहा है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है। सांची को प्रदेश की पहली सोलर सिटी बनाया गया है। राज्य के 32 लाख किसानों को सोलर पंप प्रदान किए जा रहे हैं। प्रदेश में उत्पादित क्लीन एनर्जी से बिजली, उद्योग का रूप ले रही है। प्रदेश के अन्य विभागों द्वारा अपनी स्वयं की बिजली बनाने की पहल लोक स्वास्थ्य विभाग ने आरंभ की है। इससे ऊर्जा विभाग की जिम्मेदारी बढ़ेगी तथा प्रबंधन के लिए दक्ष मानव संसाधन की आवश्यकता होगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश को सभी क्षेत्रों में देश के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में शामिल कराने के लिए संकल्पित है।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि नई नियुक्तियों में तकनीकी कर्मचारियों की संख्या को प्राथमिकता दी जाएगी। क्योंकि बिजली व्यवस्था की रीढ़ तकनीकी स्टाफ ही होता है। हालांकि इसके साथ ही गैर-तकनीकी और स्वास्थ्य से जुड़े पदों पर भी भर्तियां की गई हैं। ये सभी नियुक्तियां पारदर्शी तरीके से एमपी ऑनलाइन के माध्यम से की जा रही हैं। संकल्प-पत्र में किए गए वादों को धरातल पर उतारने की दिशा में सरकार का यह कदम युवाओं के लिए उम्मीद की किरण साबित होगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि वर्तमान युग में विद्युत (ऊर्जा) का महत्व वायु और जल के समान है। गर्व का विषय है कि हम उद्योगों और किसानों सहित सभी प्रदेशवासियों की बिजली की मांग के साथ देश की बिजली की जरूरत को भी पूरा कर रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली की मेट्रो ट्रेन मप्र की बिजली से चल रही है। अब इस तरह की योजना बनाई जा रही है कि वर्ष 2047 तक बिजली की कोई कमी नहीं होगी, प्रदेश ऊर्जा क्षेत्र में सरप्लस रहेगा। प्रदेश में विद्युत उत्पादन के लिए सभी उपलब्ध संसाधनों का उपयोग किया जा रहा है। देश में क्लीन एनर्जी के लिए गतिविधियों का विस्तार हो रहा है। प्रदेश में पिछले 11 वर्षों में सौर ऊर्जा 30 प्रतिशत बढ़ी है।

ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा कि ऊर्जा विभाग लगातार बिजली उपभोक्ताओं और किसानों के हित में कार्य कर रहा है। किसानों को अब कड़कड़ाती ठंडी रातों में सिंचाई नहीं करनी पड़ेगी। अब इन्हें सिंचाई के लिए दिन में बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। अपर मुख्य सचिव ऊर्जा नीरज मंडलोई ने कहा कि प्रदेश का ऊर्जा विभाग सौर ऊर्जा और पारंपरिक ऊर्जा क्षेत्र में नवाचारों के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमारी कोशिश है कि प्रदेश में आने वाले नए उद्योगपतियों को हरसंभव सहयोग उपलब्ध कराया जाए।

● प्रवीण सक्सेना

बिजली कंपनियों को मिला जीवनदान

ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा कि बिजली कंपनियों में बड़ी संख्या में नियुक्ति देकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बिजली कंपनियों को जीवनदान प्रदान किया है। उन्होंने कहा कि पहली बार इतनी बड़ी संख्या में नियमित पद स्वीकृत किए गए हैं। इसीलिए आज मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का अभिनंदन किया गया है। उन्होंने कहा कि ऊर्जा विभाग लगातार बिजली उपभोक्ताओं और किसानों के हित में कार्य कर रहा है। किसानों को अब कड़कड़ाती ठंडी रातों में सिंचाई नहीं करनी पड़ेगी। अब इन्हें सिंचाई के लिए दिन में बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने अधोसंरचना सुधार के लिए राशि की जरूरत पर भी बल दिया। अपर मुख्य सचिव ऊर्जा नीरज मंडलोई ने कहा कि 1000 से अधिक युवा आज ऊर्जा विभाग से नियुक्ति-पत्र लेकर जाएंगे। उनका और उनके अभिभावकों का हार्दिक अभिनंदन है। प्रदेश की 6 ऊर्जा कंपनियों में 51 हजार 700 नए स्थाई पद स्वीकृत किए गए हैं। यह प्रयास प्रदेश को भारत में ऊर्जा क्षेत्र में नए मानकों के साथ स्थापित करेगा। ऊर्जा विभाग ने हमेशा प्रदेश और देश की ऊर्जा मांग को पूरा किया है। प्रदेश का ऊर्जा विभाग सौर ऊर्जा और पारंपरिक ऊर्जा क्षेत्र में नवाचारों के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमारी कोशिश है कि प्रदेश में आने वाले नए उद्योगपतियों को हर संभव सहयोग उपलब्ध कराया जाए।

अनुराग जैन के लिए बदल गया इतिहास

मप्र में बीते कुछ दिनों से चर्चाएं हो रही थीं कि मुख्य सचिव अनुराग जैन को एक्सटेंशन मिलेगा या नहीं। 28 अगस्त को इन अटकलों पर विराम लग गया है। मुख्य सचिव अनुराग जैन को एक साल का एक्सटेंशन मिला है। यह मप्र के इतिहास में पहली बार हुआ है कि किसी मुख्य सचिव को इकट्ठे एक साल का एक्सटेंशन मिला है। बताया जाता है कि मुख्य सचिव अनुराग जैन दिल्ली के खास हैं। पीएमओ का उन पर अटूट भरोसा है। इस बार सेवा विस्तार पीएमओ के दखल के बाद ही मिला है। वह अब अगस्त 2026 तक मुख्य सचिव बने रहेंगे।

दरअसल, मुख्य सचिव अनुराग जैन 31 अगस्त को रिटायर हो रहे थे। 29 अगस्त को उनका आखिरी वर्किंग डे था। आखिरी वक्त तक यह चर्चाएं चल रही थीं कि सेवा विस्तार मिलेगा या फिर मप्र को कोई नया मुख्य सचिव मिलेगा। दो पूर्ववर्ती मुख्य सचिवों को सेवा विस्तार मिलता रहा है। बताया जा रहा है कि पीएमओ से मंजूरी मिलने के बाद फोन आया, इसके बाद मप्र सरकार रेस हो गई। 28 अगस्त शाम 6 बजे के करीब कार्मिक विभाग को मप्र सरकार ने पत्र भेजा। करीब डेढ़ घंटे बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अनुराग जैन के सेवा विस्तार की घोषणा कर दी। साथ ही सोशल मीडिया पर उन्हें बधाई दे दी। जैन प्रदेश के सातवें मुख्य सचिव हैं, जिन्हें सेवा विस्तार दिया गया है। उनको रिटायरमेंट के तीन दिन पहले एक साल का सेवा विस्तार दिया गया। इससे पहले प्रदेश में हाल ही में इकबाल सिंह बैंस, वीरा राणा को भी सेवा विस्तार दिया गया था। नवंबर 2022 में जब इकबाल सिंह बैंस रिटायर हो रहे थे, तब उनके सेवा विस्तार को लेकर लंबे समय तक संशय रहा। रिटायरमेंट के आखिरी दिन ही उन्हें 6 माह का विस्तार दिया गया। सितंबर 2023 में बैंस के विस्तार की अवधि पूरी होने से पहले ही वीरा राणा को प्रभारी मुख्य सचिव बनाया गया। हालांकि राणा को भी तीन हफ्ते पहले ही छह माह का विस्तार मिल गया। सितंबर 2024 में जब राणा का कार्यकाल खत्म हुआ, उसी दिन अनुराग जैन को मुख्य सचिव नियुक्त किया गया।

मुख्य सचिव अनुराग जैन की छवि साफ सुथरी है। साथ ही काम को समय पर डिलीवर करने के लिए जाने जाते हैं। साथ ही पीएमओ के भरोसेमंद अधिकारियों में उनकी गिनती होती है। 4 अक्टूबर 2024 को वह पहली बार मप्र के मुख्य सचिव बनकर पहुंचे थे। उस वक्त भी कहा गया था कि वह दिल्ली की पसंद हैं। 31 अगस्त 2025 को रिटायरमेंट से पहले उन्हें एक साल का एक्सटेंशन मिल गया है। इससे पहले वीरा राणा को छह महीने और इकबाल सिंह बैंस को छह-छह महीने कर दो बार एक्सटेंशन मिला था। अनुराग जैन पहले ऐसे मुख्य सचिव हैं, जिन्हें इकट्ठे एक साल का एक्सटेंशन मिला है। यह मप्र के इतिहास में पहली बार हुआ है।

कौन होगा गृह विभाग का अगला मुखिया

मप्र में मुख्य सचिव को एक साल के लिए एक्सटेंशन मिलने के बाद अब चर्चा होने लगी है कि प्रदेश गृह विभाग का अगला मुखिया कौन होगा? गृह विभाग के मुखिया के नामों को लेकर न सिर्फ चर्चा शुरू हो गई बल्कि दावेदारों के नाम भी सामने आए हैं। दरअसल गृह विभाग के एसीएस जेएन कंसोटिया रिटायर्ड हो गए हैं। उनके सेवानिवृत्ति के साथ ही होम एसीएस के लिए कई नामों की चर्चा जोरों पर चल रही है। एसीएस राजेश राजौरा को गृह विभाग का अतिरिक्त प्रभार मिल सकता है। वहीं एसीएस अनुपम राजन, एसीएस अशोक वर्णवाल और एसीएस केसी गुप्ता के नाम भी चर्चा में हैं।

पीएमओ से है डायरेक्ट लिंक

अनुराग जैन की गिनती प्रधानमंत्री मोदी के खास अफसरों में होती है। अनुराग जैन पीएमओ में संयुक्त सचिव के तौर पर 2015 में तैनात रहे हैं। इनके पास सभी मंत्रालयों से समन्वय की जिम्मेदारी थी। अपने काम से इन्होंने पीएमओ में अच्छी छाप छोड़ी थी। यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी के फेवरेट लिस्ट में हैं। वहीं, सड़क परिवहन मंत्रालय में रहने के दौरान भी इन्होंने कई प्रोजेक्ट्स को गति दी है। इसमें सबसे अहम पीएम गति शक्ति परियोजना है। इनके काम की वजह से दिल्ली में इन्हें लोग हाईवे मैन भी कहते हैं। अनुराग जैन हमेशा सादगीपूर्ण रहते हैं लेकिन काम को लेकर 24 घंटे एक्टिव रहते हैं। लाइमलाइट से दूर रहकर काम पर ही फोकस करते हैं। सहकर्मियों के साथ भी व्यवहारिक हैं। साथ ही मप्र में काम करने का लंबा अनुभव है।

अगले सीएस के लिए ये दावेदार

अनुराग जैन को एक साल का एक्सटेंशन मिलने के बाद अब अगले सीएस के दावेदारों के नाम भी चर्चा में आने लगे हैं। हालांकि अगस्त 2026 के बाद ही प्रदेश में नया सीएस बनाया जाएगा। ऐसे में अभी से भावी सीएस के लिए गुणा-भाग लगाया जा रहा है। जिसमें 1990 बैच के राजेश राजौरा का नाम सबसे ऊपर है। जब अनुराग जैन का एक्सटेंशन खत्म होगा तब राजौरा के रिटायर होने में 9 माह का समय रहेगा। ऐसे में सरकार उन्हें भी सीएस बनने का मौका दे सकती है। अनुराग जैन के एक्सटेंशन के दौरान 1990 बैच की अलका उपाध्याय रिटायर हो जाएंगी। ऐसे में 1991 बैच के अशोक वर्णवाल सीएस के दावेदारों में शामिल हो सकते हैं। हालांकि जैन का एक्सटेंशन समाप्त होने पर वर्णवाल की नौकरी 5 महीने की ही बचेगी। ऐसे में उनके चांस कम लगते हैं। इस कड़ी में मनोज गोविल भी सीएस के दावेदार माने जा रहे हैं। वैसे जिस तरह दिल्ली से मुख्य सचिव बनाए जा रहे हैं, ऐसे में 1992 बैच के पंकज अग्रवाल भी मुख्य सचिव के दावेदार हैं। अग्रवाल वर्तमान में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं। उनका रिटायरमेंट नवंबर 2029 में होगा।

कहां अटक गई तबादला सूची?

मप्र में आईएएस और आईपीएस अधिकारी पिछले कई महीनों से थोकबंद तबादले की आस लगाए बैठे हैं। सरकार आए दिन 2-2, 4-4 अफसरों के तबादले कर रही है, लेकिन थोकबंद तबादले की सूची कहां अटकी है, यह पता ही नहीं चल रहा है। इस साल जनवरी में ही खबर आई थी कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और मुख्य सचिव अनुराग जैन की जोड़ी प्रदेश में अफसरों की मंत्रालय से लेकर मैदान तक नई जमावट करने जा रही है। इसके लिए दोनों में कई दौर की बातचीत हो चुकी है। सरकार की कोशिश है कि बेहतर काम करने वाले अफसरों को बड़ी जिम्मेदारी दी जाए। इसके लिए अफसरों की कार्यप्रणाली का आंकलन कर कुंडली बनाई जा रही है। उसके बाद बेस्ट परफॉर्मर को बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। लेकिन आज 8 महीने बाद भी सूची का इंतजार सभी को है।

गौरतलब है कि प्रदेश में इन दिनों जिलों से लेकर राजधानी तक और राजधानी से लेकर जिलों तक सिर्फ एक ही बात है कि कलेक्टर-एसपी और मंत्रालय में पदस्थ बड़े अधिकारियों की ट्रांसफर लिस्ट कब आ रही है। कलेक्टरों और कमिश्नरों के साथ ही मंत्रालय में प्रमुख सचिव व अपर मुख्य सचिव स्तर के अधिकारियों के दायित्व में परिवर्तन किया जाएगा। पुलिस अधीक्षक, पुलिस महानिरीक्षक और अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक स्तर के अधिकारियों के भी तबादले होंगे। प्रदेश में अपनी सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंत्रालय से लेकर जिलों में प्रशासनिक आधार पर कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और कमिश्नर बदले थे। अधिकारियों को काम करने के लिए फ्री-हैंड भी दिया। लेकिन अभी तक आईएएस-आईपीएस की थोकबंद तबादले की सूची नहीं आ पाई है। जानकारी के अनुसार, सामान्य प्रशासन विभाग ने तबादलों की सूची तैयार कर ली है और इसे मुख्य सचिव अनुराग जैन के साथ ही मुख्यमंत्री सचिवालय से भी हरी झंडी मिल गई है। लेकिन सूची अभी तक जारी नहीं हुई है।

...तो नहीं मिलेगा प्रमोशन!

भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के लिए एक चेताने वाली खबर है। जरा सी लापरवाही के चलते उनका प्रमोशन लटक सकता है। जी हां, मप्र कैडर के अफसरों ने अगर समय रहते अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया तो उनके लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। चल और अचल संपत्ति का ब्यौरा देने में देरी करने या ब्यौरा नहीं देने वाले मप्र कैडर के आईएएस अफसरों का प्रमोशन अगले साल से अटक सकता है। केंद्र सरकार के कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के निर्देश के बाद यह बात सामने आई है। डीओपीटी ने साफ कहा है कि 31 जनवरी तक ब्यौरा नहीं देने वालों को प्रमोशन नहीं मिलेगा। इसके बाद राज्य के सामान्य प्रशासन विभाग ने मप्र में यह निर्देश जारी किए हैं। निर्देशों में कहा गया है कि भारत सरकार की वेबसाइट स्पैरो (एसपीएआरआरओडब्ल्यू) पर वार्षिक अचल संपत्ति पत्रक (इम्मूवल प्रॉपर्टी रिपोर्ट) हर साल 31 जनवरी तक ऑनलाइन सबमिट की जाएगी। इसमें बीते हुए वर्ष में 31 दिसंबर तक की स्थिति में आईएएस अधिकारी के पास मौजूद अचल संपत्ति की जानकारी दिया जाना है, जिसमें पैतृक और आईएएस अफसर द्वारा खुद या पत्नी के नाम पर खरीदी गई संपत्ति शामिल रहती है। डीओपीटी ने कहा कि अखिल भारतीय सेवा कंडक्ट रूल्स 1968 के नियम 16 (2) के अंतर्गत यह निर्देश जारी किए जा रहे हैं और अफसरों की अगली वेतन मैट्रिक्स (पदोन्नति) के लिए यह जरूरी है।

8 साल से एसआई भर्ती नहीं हुई

मप्र में पुलिस भर्ती का मुद्दा एक बार फिर सुर्खियों में है। गृह विभाग ने 24 अगस्त की शाम 5 बजकर 53 मिनट पर ट्वीट कर जानकारी दी थी कि राज्य सरकार पुलिस विभाग में 7500 पदों पर भर्ती करेगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से लेकर डीजीपी कैलाश मकवाना तक कई मंचों से इस भर्ती का जिक्र कर चुके हैं। जून 2025 में इंदौर में भी इस मुद्दे पर चर्चा हुई और सोशल मीडिया पर बार-बार भर्ती का आश्वासन दिया गया, लेकिन हकीकत यह है कि अभी तक विज्ञापन तक जारी नहीं हुआ। उल्लेखनीय है कि सब इंस्पेक्टर (एसआई) भर्ती आखिरी बार 2017 में हुई थी। 8 साल से उम्मीदवार इंतजार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 15 अगस्त को कहा था कि अगले तीन साल में 22,500 पदों पर भर्ती होगी। हर साल 7500-7500 पदों पर भर्तियां होंगी। इसके लिए एक नया पुलिस भर्ती बोर्ड बनाया जाएगा। हालांकि तब तक भर्ती ईएसबी (मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मंडल) से कराई जा सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि नया बोर्ड बनने की प्रक्रिया में लंबा समय लगेगा। जैसे- परीक्षा एजेंसी तय करना, लाइसेंस लेना और सुरक्षा संबंधी औपचारिकताएं पूरी करना। इस कारण भर्ती और महीनों टल सकती है।

● राजेन्द्र आगाल

अपर मुख्य सचिव बने दीपाली रस्तोगी और शिव शेखर शुक्ला

राज्य शासन ने हाल ही में 2 आईएएस अफसरों को अपर मुख्य सचिव के पद पर प्रमोट किया है। यह आदेश 1 सितंबर से प्रभावशील होगा। मुख्य सचिव अनुराग जैन और अपर मुख्य सचिव जेएन कंसोटिया के रिटायरमेंट के बाद यह माना जा रहा था कि सिर्फ दीपाली रस्तोगी को ही प्रमुख सचिव के पद से अपर मुख्य सचिव के पद पर प्रमोट किया जाएगा। लेकिन, राज्य सरकार ने दीपाली रस्तोगी के साथ प्रमुख सचिव शिव शेखर शुक्ला को भी अपर मुख्य सचिव बनाया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने दोनों ही आईएएस अफसर को उनके वर्तमान विभाग में ही अपर मुख्य सचिव के पद पर पदस्थ किया है। दरअसल, नियमों के मुताबिक मुख्य सचिव का पद रिक्त नहीं होने से शिव शेखर शुक्ला के प्रमोट होने का मामला अटक गया था। ऐसे में सरकार ने शिव शेखर शुक्ला को एसीएस बनाया है।

जिलाध्यक्षों को मिशन 2028 का टास्क

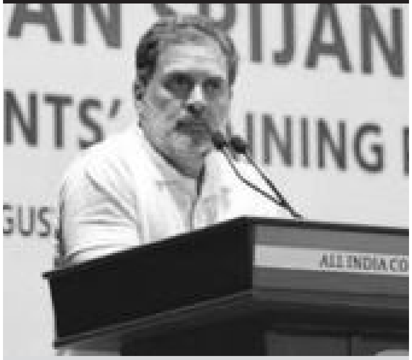

मप्र कांग्रेस के नवनियुक्त 71 शहर और ग्रामीण जिला अध्यक्षों की दिल्ली में पहली ट्रेनिंग हुई। इसमें लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नए जिला अध्यक्षों को पार्टी को मजबूत करने की सीख दी। वहीं, दूसरी तरफ कई जिलों में नवनियुक्त जिला अध्यक्षों को लेकर हो रहा विरोध प्रदर्शन दिल्ली में भी हुआ। राहुल गांधी ने बताया कि पार्टी और संगठन को कैडर मजबूत करना है। उन्होंने कैडर मैनेजमेंट विषय पर नए जिला अध्यक्षों को टिप्स दिए। इस दौरान जिला अध्यक्षों को तीन महीने के भीतर जिले और ब्लॉक स्तर पर टीम बनाने का लक्ष्य दिया गया है।

राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जिला कांग्रेस अध्यक्षों को वोटर लिस्ट की निगरानी के लिए आगाह किया है। उन्होंने भाजपा पर वोट काटने के आरोप लगाते हुए कहा कि एसआईआर जैसे तरीकों से ऐसा किया जा सकता है। खड़गे ने वोटर अधिकार यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि चुनाव आयोग के एसआईआर पर नैरेटिव को सुप्रीम कोर्ट से भी झटका लगा है। कांग्रेस अब अपनी सभी राज्य इकाइयों विशेषकर जिला कांग्रेस अध्यक्षों को अपने-अपने इलाकों में वोटर लिस्ट की पूरे 5 वर्षों तक निगरानी के लिए आगाह करने लगी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मप्र के नवनियुक्त जिलाध्यक्षों से कहा कि भाजपा आगे भी एसआईआर जैसे तरीकों से हमारे लोगों के वोट काटेगी।

जिलाध्यक्षों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि पूरे 5 वर्ष सावधान रहते हुए वोटर लिस्ट की सघन जांच करते रहें, ताकि अगर भाजपा के लोग या बीएलओ हमारे लोगों के नाम काटें तो हम उन्हें तुरंत पकड़ लें। कांग्रेस मुख्यालय इंदिरा भवन में दोनों राज्यों में संगठन सृजन के तहत नियुक्त जिला कांग्रेस अध्यक्षों के प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए खड़गे ने यह बात कही। बिहार में मतदाता सूची के विशेष सघन पुनरीक्षण यानि एसआईआर में गड़बड़ियों के विरूद्ध लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा का जिक्र करते हुए खड़गे ने कहा कि बड़ी संख्या में लोग यात्रा में शामिल होकर इसके विरूद्ध खड़े हो रहे हैं। चुनाव आयोग तथा भाजपा के एसआईआर पर नैरेटिव को सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा झटका लगा है। खड़गे ने कहा कि 2024 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में 8 सीटों पर 22,779 वोटों के अंतर से सत्ता हाथ से निकल गई। मप्र में भी 2023 में करीब 27 ऐसी सीटें रहीं, जहां वोट चोरी की बातें सामने आई हैं।

मतदाता सूची का निरीक्षण करते रहें

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हाल ही में राहुल गांधी ने एक विस्तृत प्रस्तुति दी थी कि किस तरह कर्नाटक की महादेवपुरा सीट पर एक साजिश के तहत रणनीतिक तरीके से वोट चुराए गए। हमें यह सब छह महीने के शोध के बाद पता चला। चुनाव आयोग ने पहले तो कोई जवाब नहीं दिया। अब पूरा देश इसे समझ रहा है। बिहार में एसआईआर पर भाजपा सरकार और चुनाव आयोग के बयान को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। मानसून सत्र को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि विपक्ष चाहता था कि संसद चले और जनता के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हो, लेकिन भाजपा सरकार नहीं चाहती थी कि एसआईआर (मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण) और वोट चोरी जैसे महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा हो। भाजपा एसआईआर जैसी योजनाओं से हमारे लोगों के वोट काटती रहेगी। जिला अध्यक्ष की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि हमें पूरे 5 साल सावधान रहना है। हमें अपनी मतदाता सूची की गहन जांच करते रहना होगा ताकि अगर भाजपा के लोग या बीएलओ हमारे लोगों के नाम काटते हैं, तो हम उन्हें तुरंत पकड़ सकें। उन्होंने कांग्रेस नेताओं से कहा कि कि वे लोगों को बताएं कि इस देश में सभी को वोट देने का अधिकार कांग्रेस की देन है। राजीव गांधी ने ही मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी ताकि लोकतंत्र में युवाओं की भागीदारी बढ़ाई जा सके। गौरतलब है कि राहुल गांधी की बिहार में मतदाता अधिकार यात्रा में लाखों लोग शामिल हो रहे हैं।

चुनाव से पहले 7 महीने में वहां सिर्फ 4 लाख वोटर बढ़े, मगर आखिर के 2 महीने में 16 लाख वोटर बढ़ गए।

राहुल गांधी ने कर्नाटक की महादेवपुरा विधानसभा सीट पर हुई वोट चोरी का अध्ययन कर देश को इसकी हकीकत बता दी है और चुनाव आयोग इसका जवाब नहीं दे रहा है। कांग्रेस के संगठनात्मक ढांचे से लेकर पार्टी की सत्ता में दस्तक तक जिला अध्यक्षों की महत्वपूर्ण भूमिका बताते हुए खड़गे ने मंडल और बूथ कमेटी के गठन में वफादार लोगों को रखने की सलाह दी जो कांग्रेस की विचाराधारा के प्रति इतने दृढ़ हों कि कोई प्रलोभन उन्हें डिगा न सके। अंदरूनी गुटबाजी को किनारे रखने की नसीहत देते हुए उन्होंने कहा कि सभी लोगों को एकजुट रहते हुए गुटबाजी नहीं पनपने देनी है। कांग्रेस जब एकजुट रहती है, तभी चुनाव जीतती है। वोटर अधिकार यात्रा में एक दिन के ब्रेक के बीच दिल्ली लौटे राहुल गांधी ने भी जिलाध्यक्षों से सीधा संवाद किया।

मप्र कांग्रेस की ओर से सभी जिलाध्यक्षों ने एक स्वर में संकल्प दोहराया कि हम लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए हर हाल में संघर्ष करेंगे। भाजपा की वोट चोरी की साजिशों को बेनकाब करेंगे और जनता के विश्वास की लड़ाई को जीतेंगे। टीम मप्र कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए अथक परिश्रम करेगी। कांग्रेस जिलाध्यक्षों ने कहा कि राहुल गांधी का संघर्ष प्रत्येक कांग्रेस सिपाही के लिए ऊर्जा और प्रेरणा का स्रोत है। आज की बैठक ने संगठन में नई ऊर्जा और जोश का संचार किया है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी और सभी जिला अध्यक्ष एक दिन पहले ही दिल्ली पहुंच गए थे। इसकी जानकारी पटवारी ने खुद ट्वीट कर दी। उन्होंने लिखा- ऊर्जा और उत्साह से भरी हुई टीम मप्र कांग्रेस के वैचारिक प्रवाह को नई गति दे रही है! जन अपेक्षाओं को साकार करने के लिए भी हम सभी प्राण-प्रण से संघर्ष करेंगे। प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी के साथ सभी नव-नियुक्त जिला कांग्रेस अध्यक्षों ने संकल्प लिया- हम मिलकर लड़ेंगे, हर हाल में जीतेंगे! दिल्ली में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी और प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी के साथ सभी जिलाध्यक्षों ने एआईसीसी ऑफिस का भ्रमण कर पूरी कार्यपद्धति समझी। इसके बाद मप्र कांग्रेस के सभी जिलाध्यक्षों के लिए हरीश चौधरी ने डिनर का आयोजन भी किया।

● **अरविंद नारद**

बिछेगा सड़क, फ्लाईओवर का जाल

एक ही रोड से जुड़ेंगे कान्हा, पन्ना, बांधवगढ़ और पेंच टाइगर रिजर्व

टाइगर स्टेट कहे जाने वाले मप्र में केंद्र सरकार बाघों के लिए अलग कॉरिडोर बनाने जा रही है। नितिन गडकरी ने बाघों के लिए फेमस मप्र में 5500 करोड़ की लागत से टाइगर कॉरिडोर बनाने की घोषणा की। यह कॉरिडोर प्रदेश के 4 टाइगर रिजर्वों को आपस में जोड़ेगा और उसके केंद्र में जबलपुर होगा। 5500 करोड़ की लागत से बनने वाला टाइगर कॉरिडोर प्रदेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। इसमें मप्र के 4 नेशनल पार्क एक-दूसरे से सीधे जुड़ जाएंगे। ऐसा होने से प्रदेश के टाइगर टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। इस प्रोजेक्ट के तहत जबलपुर से बांधवगढ़, कान्हा, पेंच और पन्ना टाइगर रिजर्व को जोड़ा जाएगा। नितिन गडकरी ने कहा, इस टाइगर कॉरिडोर के बनने के बाद मप्र में टाइगर देखने आने वाले पर्यटकों को सहूलियत होगी।

देश के हृदय प्रदेश मप्र में सड़कों, फ्लाईओवर सहित अन्य विकास कार्यों का जाल बिछेगा। इसके लिए केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने 73 हजार करोड़ से अधिक की परियोजनाओं की घोषणा की है। दरअसल, 23 अगस्त को जबलपुर में बनकर तैयार मप्र के सबसे लंबे ऐतिहासिक फ्लाईओवर का केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने मप्र में विकास कार्यों के लिए 73 हजार करोड़ रुपए की स्वीकृति दी। इसमें नई सड़कों का निर्माण, पुरानी सड़कों का चौड़ीकरण और टाइगर कॉरिडोर आदि शामिल हैं। इसके साथ ही नितिन गडकरी ने जबलपुर से भोपाल तक के लिए ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस-वे का काम शुरू करने की भी घोषणा की है।

केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि मप्र के लिए 3 लाख करोड़ रुपए की सड़कों के प्रावधान हैं। इनमें से 75000 करोड़ रुपए की सड़क बन चुकी हैं और 65000 करोड़ रुपए के काम अभी चल रहे हैं। साथ ही उन्होंने इस मौके पर कई सौगातों की घोषणा की। इनमें एक बड़ी घोषणा जबलपुर से भोपाल के बीच में बनने वाले ग्रीन फील्ड कॉरिडोर की भी है। इसके साथ ही लखनादौन से रायपुर तक एक्सप्रेस-वे भी बनाया जा रहा है, जो आगे जाकर विशाखापट्टनम एक्सप्रेस-वे से भी जुड़ जाएगा। नितिन गडकरी का कहना है कि इस सड़क के बनने के बाद मप्र समुद्र तट से सीधे जुड़ सकेगा। नितिन गडकरी और मप्र के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव जबलपुर में 1250 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुए फ्लाईओवर का उद्घाटन करने के लिए आए थे। यह फ्लाईओवर जनता के लिए खोल दिया गया है। इसके चालू होने से दमोह नाका से मदन महल तक की दूरी करीब 7 मिनट में पूरी होगी। इस फ्लाईओवर में देश का सबसे बड़ा केबल ब्रिज भी है, जो कि मदन महल रेलवे स्टेशन के ऊपर बनाया गया है।

इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने कई सड़क परियोजनाओं की घोषणा की। जबलपुर से मंडला और छत्तीसगढ़ सीमा तक 2.5 हजार करोड़ रुपए का 150 किलोमीटर का 6 लेन के चौड़ीकरण का कार्य किया जाएगा, यह कार्य 6 महीने में शुरू होगा। सिवनी-छिंदवाड़ा-सावनेर 4 लेन चौड़ीकरण का कार्य 2.5 हजार करोड़ रुपए लागत से आगामी 6 माह में शुरू किया जाएगा। खरगोन-देशगांव-जुलवानिया मार्ग के 108 किलोमीटर 4 लेन चौड़ीकरण का कार्य 2300 करोड़ रुपए से किया जाएगा तथा महाराष्ट्र सीमा तक बैतूल-परसवाड़ा 2 लेन मार्ग को भी मंजूरी दी गई है। बालाघाट से मंडला के बीच बेहतर संपर्क के लिए सड़क बनाई जाएगी। मप्र में टाइगर कॉरिडोर बनाया जाएगा। इसके अंतर्गत जबलपुर से बांधवगढ़ तक 4600 करोड़ रुपए की लागत से 4 लेन सड़क बनाई जानी थी, जिसे बढ़ाकर अब 5500 करोड़ रुपए किया गया है। यह सड़क कान्हा, बांधवगढ़, पन्ना और पेंच टाइगर रिजर्व को कनेक्ट करेगी। इससे मप्र के टूरिज्म, आर्थिक विकास और रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी होगी।

इस मौके पर नौरादेही वन्य जीव अभयारण्य के भीतर 4 लेन की एक सड़क का भी लोकार्पण किया गया। यह सड़क लगभग 178 करोड़ रुपए में बनकर तैयार हुई है। इस सड़क में भी 23 जगह पर एनिमल अंडर पास बनाए गए हैं। इसे राष्ट्रीय राजमार्ग 45 पर हिरण सिंदूर खंड के नाम से जाना जाता है। जबलपुर से भोपाल जाने वाली सड़क पर दोनों और अभयारण्य के भीतर चैन लिंक फेंसिंग की गई है। इसके साथ ही राष्ट्रीय राजमार्ग 30 में कटनी में 252 करोड़ रुपए की एक परियोजना का भी लोकार्पण किया गया है, जिसमें कटनी बायपास सड़क को 4 लेन बनाया गया है। नितिन गडकरी ने इस मौके पर बताया कि मप्र का शायद ही ऐसा कोई कोना होगा, जहां केंद्र सरकार के सड़क एवं परिवहन मंत्रालय से सड़क नहीं बनाई जा रही होगी। नितिन गडकरी का कहना है कि अभी भी उनके पास और गुंजाइश है। यदि सरकार उनके विभाग से और काम मंजूर करवाती है, तो मप्र के विकास में पीछे नहीं हटेंगे।

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को बताया कि भारत सरकार प्रदेश में जिला स्तर तक जल्द ड्राइविंग सेंटर आरंभ करने की इच्छुक है। इसके लिए प्रस्ताव राज्य सरकार की ओर से शीघ्रता से भेजे जाएं। केंद्र द्वारा इन्हें तत्काल स्वीकृति प्रदान की जाएगी। उन्होंने बताया कि प्रदेश में सीआरएफ फंड से 1500 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की घोषणा की जा रही है। इससे उज्जैन, जबलपुर और रीवा में नए फ्लाईओवर बनाए जाएंगे। उज्जैन में 510 करोड़ रुपए की लागत से नई सड़क और फ्लाईओवर बनेंगे। अशोकनगर से विदिशा के बीच 96 करोड़ रुपए की लागत से सड़क बनाई जाएगी। उज्जैन में कालभैरव मंदिर की कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए ब्रिज बनाया जाएगा। गडकरी ने कहा कि भोपाल से जबलपुर के बीच 255 किलोमीटर लंबा नया ग्रीन फील्ड हाईवे बनाया जाएगा, जिसकी लागत 15 हजार करोड़ रुपए होगी। इसके लिए डीपीआर दिसंबर तक पूर्ण कर लिया जाएगा। भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूर्ण होने पर अप्रैल-मई 2026 से हाईवे निर्माण का कार्य शुरू किया जाएगा।

● **नवीन रघुवंशी**

मानसून सत्र में मौन रहे 68 विधायक

मप्र विधानसभा के मानसून सत्र में सत्तापक्ष और विपक्ष के नेताओं ने सवालों की झड़ी लगा दी। प्रदेश के 230 में से 162 विधायकों ने सत्र के दौरान सवाल पूछे हैं। वहीं शेष 68 विधायक चुप्पी साधे रहे। यानी उन्होंने एक भी सवाल नहीं किया है। यही नहीं सत्र के दौरान सिर्फ 3 विधायकों ने ही कोटे के बराबर सवाल पूछा है। ये आंकड़े यह दर्शाते हैं कि जनता की आवाज बने माननीय अपने कर्तव्य के प्रति कितने सचेत हैं। प्रदेश की जनता अपने जनप्रतिनिधि को चुनकर इस उम्मीद से भेजती है कि वे विधानसभा में क्षेत्र के लोगों की आवाज बनेंगे। जनता से जुड़ी समस्याओं को सरकार के समक्ष उठाएंगे, लेकिन मप्र के कई विधायक विधानसभा में जनता से जुड़े सवाल तो छोड़िए पर्याप्त सवाल ही नहीं पूछ रहे।

गौरतलब है कि प्रदेश के 230 विधायकों में से भाजपा के विधायकों की संख्या 132, कांग्रेस के विधायकों की संख्या 65 और भारत आदिवासी पार्टी का एक विधायक है। हाल ही में खत्म हुए विधानसभा सत्र के दौरान सिर्फ 3 विधायक ही ऐसे रहे, जिन्होंने सदन में सवालों की झड़ी लगा दी। जबकि 5 विधायकों ने 1-1 सवाल पूछे। 6 अगस्त तक चले मप्र विधानसभा के मानसून सत्र में विधायकों ने कुल 3377 सवाल पूछे। 36 विधायक ऐसे हैं जिन्होंने कितने सवाल पूछे इस पर ही सवाल है। विधानसभा में विधायक सवाल पूछते हैं और उन सवालों का जवाब मंत्री परिषद के सदस्य देते हैं। सवाल विपक्ष के विधायक ही नहीं, बल्कि सत्तापक्ष के विधायक भी पूछ सकते हैं। सबसे पहले बताते हैं कि मप्र विधानसभा की मौजूदा स्थिति क्या है। विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष 1 है, जबकि उपाध्यक्ष का पद खाली है। मंत्रिमंडल के सदस्यों की संख्या 31 है।

नियम के हिसाब से विधानसभा के एक दिन की बैठक के लिए विधायक ज्यादा से ज्यादा 4 ही सवाल लगा सकते हैं। इस तरह यदि 10 दिन का सत्र है तो विधायक 40 सवाल ही लगा सकते हैं। विधानसभा सचिवालय के प्रमुख सचिव अवधेश प्रताप सिंह कहते हैं कि यह संख्या इसलिए निर्धारित की जाती है, ताकि बहुत ज्यादा सवाल न आएं। वैसे भी यदि विधानसभा की सदस्य संख्या के हिसाब से ही हर विधायक 4 सवाल लगाए तो एक दिन में 920 सवाल होते हैं। सवालों को विभागों में भेजा जाता है, इसके बाद विभाग जवाब तैयार कर भेजते हैं।

मप्र विधानसभा में विधायक एक सत्र के दौरान कितने सवाल लगा सकते है यह निर्धारित होता है। सत्र के दौरान विधायक प्रति बैठक अधिकतम 4 सवाल लगा सकते हैं। विधानसभा के मानसून सत्र में कुल 10 बैठकें होनी थीं, इस तरह विधायक 40 सवाल लगा सकते थे। कई विधायक ऐसे रहे, जिन्होंने निर्धारित संख्या के हिसाब के बराबर पूरे सवाल लगाए, यानि इन विधायकों ने हर रोज 4 सवाल विधानसभा में भेजे। ताबड़तोड सवाल लगाने वाले ऐसे विधायकों की संख्या तीन है। इनमें से दो विधायक सत्तापक्ष के हैं जबकि एक विधायक कांग्रेस से हैं। कांग्रेस के प्रताप ग्रेवाल, भाजपा के मनोज सिंह राठौर और राजेंद्र पांडे ने 40-40 सवाल पूछे। वहीं मप्र विधानसभा के मोबाइल एप ई-विधान पर से मिली जानकारी के मुताबिक नेता प्रतिपक्ष सहित 9 विधायक सबसे ज्यादा सवालों से एक सवाल पीछे रह गए। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने 39 सवाल लगाए। उनके अलावा सुरेश राजे, सतीश सिकरवार, हरिशंकर खटीक, पूर्व मंत्री जयवर्द्धन सिंह, यादवेंद्र सिंह, विधायक कालू सिंह ठाकुर ने भी 39-39 सवाल लगाए। इसके अलावा कैलाश कुशवाहा, दिलीप सिंह परिहार, पंकज उपाध्याय, रजनीश हरवंश सिंह, सुनील उइके और अभिलाष पांडेय ने 38-38 सवाल विधानसभा में लगाए। इसके अलावा उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत खंडेलवाल ने 37 सवाल पूछे।

हेमंत खंडेलवाल भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद पहली बार विधानसभा की कार्यवाही में शामिल हुए। उन्होंने 4 सवाल लगाए। सभी सवाल बैतूल जिले से संबंधित थे, इनमें ग्राम पंचायतों में 50 लाख से अधिक अव्ययित राशि, जेएस कॉलेज बैतूल में इंफ्रास्ट्रक्चर, बैतूल में जिला अस्पताल में 600 अस्पताल की स्वीकृति और बैतूल में उपयंत्री सहायक यंत्री के खाली पदों और कार्यरत पदों की जानकारी से जुड़े सवाल पूछे।

● डॉ. जय सिंह सेंधव

5 विधायकों ने पूछा सिर्फ एक सवाल

ई-विधान एप पर अपलोड जानकारी के अनुसार 10 दिनों तक चलने वाले मप्र विधानसभा के सत्र में 5 विधायक ऐसे भी रहे, जिन्होंने अपने क्षेत्र या प्रदेश से जुड़ा एक ही सवाल पूछा। ऐसे विधायकों की सूची में इंदौर की पूर्व महापौर मालिनी गौड़ का नाम भी शामिल है। इसके अलावा भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा, संतोष बरकड़े, रमाकांत भार्गव और कांग्रेस विधायक केदार डाबर का नाम शामिल है। हालांकि भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने विधेयकों पर हुई चर्चा में खुलकर हिस्सा लिया। खासतौर से मेट्रोपॉलिटन एक्ट को लेकर उन्होंने भोपाल शहर को लेकर सदन में बात रखी। उधर, कई विधायक ऐसे भी रहे, जिन्होंने 10 दिन के सत्र के लिए सिर्फ दो सवाल ही लगाए। इनमें पूर्व मंत्री सुरेंद्र पटवा, नागेंद्र सिंह, विधायक भगवानदास सबनानी, गायत्री राजे पवार, राजकुमार कर्राहे, अरविंद माधव मारू ने दो-दो सवाल ही विधानसभा में लगाए। गायत्री राजे ने ध्यानाकर्षण में भी देवास को लेकर मुद्दा उठाया। ई-विधान एप पर अपलोड जानकारी के अनुसार 11 विधायक ऐसे भी हैं, जिन्होंने इस बार सिर्फ 4 और 5 सवाल ही लगाए। इसमें भाजपा विधायक सिद्धार्थ तिवारी, विधायक वीर सिंह भूरिया, राकेश कुमार शुक्ला, योगेश पंडाग्रे, मथुरा लाल डामर, मनोज नारायण सिंह चौधरी, अनिल जैन कालूहेडा, छाया गोविंद मौरे, गौरव सिंह मारधी, जयंत मलैया और हजारीलाल दांगी का नाम शामिल है। इन विधायकों ने 4-4 सवाल ही लगाए। इसके अलावा विक्रम सिंह, अरविंद पटैरिया और पूर्व मंत्री प्रभुराम चौधरी ने 5-5 सवाल लगाए।

इंदौर-उज्जैन मेट्रो चलाने की डीपीआर तैयार

वर्ष 2028 में महाकाल की नगरी उज्जैन में सिंहस्थ का आयोजन होगा। इसको देखते हुए सरकार यातायात व्यवस्था सुगम बनाने में लगी हुई है। इसी कड़ी में इंदौर से उज्जैन को मेट्रो ट्रेन से जोड़ा जा रहा है, ताकि लोग आसानी से महाकुंभ का लाभ उठा सकें।

इंदौर से उज्जैन तक (45 किलोमीटर) मेट्रो दौड़ेगी। इसकी डीपीआर (डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट) तैयार हो गई है। जल्द ही मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव रिव्यू करेंगे। इसके बाद इसे कैबिनेट बैठक में रखा जाएगा। हालांकि, फंड और डिपो के लिए सरकारी जमीन जैसी कुछ अड़चनें हैं, जिससे प्रोजेक्ट ने रफ्तार नहीं पकड़ी है। दिल्ली मेट्रो ने दोनों शहरों की फिजिबिलिटी स्टडी रिपोर्ट तैयार की थी, जिसमें इसे मेट्रो के लिए अच्छा बताया था। इसके बाद डीपीआर तैयार की गई। इस प्रोजेक्ट में करीब 10 हजार करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। वहीं, लगभग 45 किमी के ट्रैक में 11 स्टेशन बनेंगे। 4.5 किमी का ट्रैक उज्जैन शहर में अंडरग्राउंड रखने का प्रस्ताव है। मेट्रो लवकुश नगर से शुरू होकर उज्जैन रेलवे स्टेशन तक जाएगी।

मेट्रो चलने से इंदौर-उज्जैन के बीच सफर में समय कम लगेगा और महाकाल मंदिर तक पहुंचने में दर्शनार्थियों को आसानी होगी। उज्जैन पहुंचने का समय लगभग आधा रह जाएगा। अभी बस से करीब 2 घंटे तो कार से करीब डेढ़ घंटे लगते हैं। दोपहिया से लगभग दो घंटे लगते हैं। मेट्रो 45 से 50 मिनट में लवकुश चौराहा से उज्जैन पहुंचेगी। डीपीआर में भौंरासला, बारोली, धरमपुरी, तराना, सांवेर, पंथ पिपलई, निनोरा, त्रिवेणी घाट, नानाखेड़ा, उज्जैन आईएसबीटी, उज्जैन रेलवे स्टेशन पर मेट्रो स्टेशन बनेंगे। उज्जैन में मेट्रो को कहां से अंडरग्राउंड किया जाना है, इस पर निर्णय होना है। इंदौर-उज्जैन के बीच प्रस्तावित मेट्रो के लिए दिल्ली मेट्रो ने फिजिबिलिटी स्टडी की। इसके बाद डीपीआर का ड्राफ्ट बनाया गया। इसमें लागत, स्टेशनों की संख्या तय की गई है। इस प्रोजेक्ट में स्टेशनों की संख्या कम रहेगी। इंदौर-उज्जैन के बीच सड़क मार्ग की दूरी करीब 55 किमी है। इसके आसपास से ही मेट्रो गुजर सकती है। यह रोड पहले से ही सिक्स लेन किया जा रहा है। वहीं, यहां पर ज्यादा भू-अर्जन भी नहीं करना पड़ेगा।

इंदौर में पहले से मेट्रो का संचालन हो रहा है, इसलिए दूसरे डिपो की जरूरत नहीं होगी। इंदौर के लवकुश चौराहे से उज्जैन तक मेट्रो पहुंचेगी। उज्जैन में डिपो के लिए जमीन तलाश की गई। कुल 49.7 एकड़ सरकारी जमीन उज्जैन के आसपास नहीं मिली। इस वजह से सांवेर के पास रेवती में जमीन मांगी गई। देश में कई शहरों में मेट्रो और रैपिड रेल चल रही हैं। दिल्ली मेट्रो सबसे बड़ी प्रणाली है और इसके अलावा रैपिड रेल दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ कॉरिडोर पर भी चल रही है। रैपिड रेल गुरुग्राम में भी उपलब्ध है। इसमें सीटिंग व्यवस्था ज्यादा रहेगी, क्योंकि यात्रियों को लंबी दूरी की यात्रा करना पड़ती है।

इंदौर-उज्जैन के बीच मेट्रो चलाने के लिए साल 2022-23 में फिजिबिलिटी स्टडी दिल्ली मेट्रो ने ही की थी, जो सरकार को सौंपी गई थी। इस रिपोर्ट के बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इंदौर में बतौर प्रभारी मंत्री बैठक ली। इसमें कहा था कि मेट्रोपोलिटन सिटी में दोनों शहरों की फिजिबिलिटी रिपोर्ट सबसे बेहतर है। इसके बाद प्रोजेक्ट को लेकर रफ्तार तेज तो हुई, लेकिन फंड को लेकर अड़चन है। मेट्रो से जुड़े एक अफसर ने बताया कि इस प्रोजेक्ट को पूरा होने में कम से कम 3 साल लगेंगे। ऐसे में यह सिंहस्थ से पहले शुरू नहीं हो सकता। भोपाल में प्रायोरिटी कॉरिडोर के सुभाष नगर से एम्स के बीच कुल 8 मेट्रो स्टेशन बन रहे हैं। एक स्टेशन की लागत 50 करोड़ रुपए से अधिक है। दूसरी ओर, इंदौर और उज्जैन के बीच मेट्रो के कम स्टेशन रहेंगे। इससे राशि बचेगी और लागत भी कम आएगी।

मेट्रो कॉर्पोरेशन सूत्रों के अनुसार इंदौर-उज्जैन रोड पर मेट्रो को एलिवेटेड रखा जाएगा। इसके लिए सड़क के बीच स्थित डिवाइडर पर मेट्रो के पिलर खड़े किए जाएंगे। वहीं, नानाखेड़ा से उज्जैन रेलवे स्टेशन तक मेट्रो अंडरग्राउंड रहेगी। हालांकि कितने किमी का कितना हिस्सा एलिवेटेड रहेगा और कितना अंडरग्राउंड रहेगा, यह डीपीआर तैयार होने के बाद ही पता चलेगा। इंदौर व उज्जैन के बीच हाइब्रिड मोड में मेट्रो का संचालन किया जा सकता है। इसकी अधिकतम रफ्तार 135 किलोमीटर प्रतिघंटा तक रहेगी। वर्तमान में दिल्ली एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन में इस तरह हाइब्रिड मोड में मेट्रो का संचालन किया जा रहा है। पूर्व में सिंहस्थ के पहले इंदौर से उज्जैन के बीच मेट्रो चलाने की योजना बनाई जा रही थी, लेकिन 10 हजार करोड़ रुपए का बजट जुटाना राज्य शासन के लिए आसान नहीं है। यही वजह है कि यह प्रोजेक्ट सिंहस्थ के पहले पूरा नहीं हो पाएगा।

● **जितेंद्र तिवारी**

एक तिहाई रह जाएगा ट्रैफिक

इंदौर और उज्जैन का करीब 75 प्रतिशत ट्रैफिक सड़क मार्ग से ही आना-जाना करता है। हजारों लोग इंदौर-उज्जैन में अप-डाउन करते हैं। इससे सड़क पर ट्रैफिक का दबाव बना रहता है। कई बार हादसे भी हो चुके हैं। ऐसे में इंदौर और उज्जैन के बीच मेट्रो बेहतर कनेक्टिविटी का बड़ा विकल्प हो सकता है। दोनों शहरों के बीच मेट्रो चलने के बाद सड़क मार्ग का ट्रैफिक एक तिहाई रह जाएगा।

कई राज्यों में पेयजल, सिंचाई आदि के लिए पानी मुहैया कराने वाली नर्मदा नदी पर बने सरदार सरोवर बांध को लेकर मप्र और गुजरात के बीच वर्षों से शीतयुद्ध चल रहा है। कभी पानी के बंटवारे तो कभी मुआवजे को लेकर दोनों राज्य आमने-सामने आते रहते हैं। वर्तमान में सरदार सरोवर बांध के 7,669 करोड़ के मुआवजे को लेकर मप्र पड़ोसी राज्य गुजरात पर दबाव बना रहा है, लेकिन गुजरात लगातार बच रहा है।

7,669 करोड़ के मुआवजे की लड़ाई

सरदार सरोवर बांध के मुआवजे को लेकर मप्र और गुजरात सरकार झगड़ रही हैं। मप्र 7,669 करोड़ रुपए गुजरात से मांग रहा है तो वहीं गुजरात 281 करोड़ रुपए पर ही विचार करने की बात कह रहा है।

हालत यह है कि मप्र सरकार ने गुजरात के रवैये को गुमराह करने वाला और झूठा बताया है। विवाद का खामियाजा डूब क्षेत्र में आने वाले मप्र के वो लोग भुगत रहे हैं, जो पुनर्वास के इंतजार में हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन की मेधा पाटकर के मुताबिक, आज भी करीब 10 हजार लोगों का पूरी तरह से पुनर्वास नहीं हुआ है। अधिकारी हर बार फंड की कमी का हवाला देते हैं।

23 साल से चल रहे विवाद को सुलझाने के लिए जुलाई के आखिरी सप्ताह में गुजरात के केवड़िया में दोनों राज्यों के मध्यस्थों की बैठक होने वाली है। दोनों राज्यों के बीच हुए गोपनीय पत्राचार और दस्तावेजों की पड़ताल और दोनों राज्यों के अफसरों से बात में कई बातें निकलकर सामने आई हैं। मप्र सरकार के नर्मदा घाटी विकास विभाग के तत्कालीन प्रमुख सचिव ने पहले पत्र में वन वृद्धि क्षेत्र के लिए 112.51 करोड़ रुपए मुआवजा मांगा। दूसरे पत्र में सरकारी जमीन के लिए 157.61 करोड़ रुपए और तीसरे पत्र में डूब क्षेत्र में आने वाली वन भूमि के लिए 11.34 करोड़ रुपए मांगे। इस तरह कुल 281.46 करोड़ रुपए का मुआवजा मांगा गया। उस समय सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई 90 मीटर थी।

सरदार सरोवर बांध परियोजना की नींव 5 अप्रैल 1961 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी। 56 साल बाद 17 सितंबर 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांध का उद्घाटन किया। इतने सालों में बांध की ऊंचाई 5 बार बढ़ाई गई। 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने बांध की ऊंचाई 80.3 मीटर तक सीमित रखने को कहा था। मगर, लगातार बांध की ऊंचाई बढ़ती गई और 2014 में इसे 138.68 मीटर कर दिया गया। साल 2019 में जब बांध को पूरी क्षमता के साथ भरा गया, तब मप्र ने डूब क्षेत्र में आई अपने हिस्से की जमीन का फिर से आंकलन किया और साल 2019-20 के बाजार मूल्य के हिसाब से गुजरात सरकार से 7,669 करोड़ रुपए के संशोधित मुआवजे की मांग की।

गोपनीय दस्तावेजों के मुताबिक, गुजरात ने पुरानी मुआवजा राशि (281.46 करोड़ रुपए) को लेकर 23 सितंबर 2003 को मप्र सरकार के तीनों पत्रों का जवाब दिया। इसमें साफ कहा कि वो भुगतान नहीं करेंगे। इसके बाद 7 अक्टूबर 2003 को दोनों राज्य सरकारों के अधिकारियों की एक बैठक गुजरात के वडोदरा में हुई। बैठक का कोई नतीजा नहीं निकला। इसके बाद मप्र सरकार ने एनडब्ल्यूडीटी अवॉर्ड के तहत विवाद को मध्यस्थता (आर्बिट्रेशन) के लिए ले जाने का निर्णय लिया। इसके बाद दो दशक तक बैठकों का दौर चलता रहा, मगर कोई नतीजा नहीं निकला। इसी कड़ी में 12-13 अगस्त 2024 को दोनों ही राज्यों के मध्यस्थों की गुजरात के गांधीनगर में एक बैठक हुई, जिसके बाद 17 अगस्त 2024 को गुजरात सरकार ने मध्यस्थों के सामने पत्र के माध्यम से लिखित प्रस्तुतिकरण (सबमिशन) पेश किया। गुजरात सरकार ने अपने **प्रस्तुतिकरण** में कई जरूरी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए थे। मप्र सरकार ने दोनों सरकारों के बीच हुए पत्राचार और कुछ दस्तावेज जुटाए। जिसके बाद अपना जवाब पेश किया जिसमें गुजरात सरकार के कथन को पूरी तरह झूठा और भ्रामक बताया।

17 अगस्त 2024 को गुजरात ने मप्र के मुआवजा संबंधी दावों पर सवाल उठाए थे। गुजरात ने जो सबमिशन (प्रस्तुतिकरण) दिया, उसमें लिखा कि मप्र ने मुआवजे के संबंध में मांगी गई जानकारी नहीं दी। मप्र द्वारा की गई संशोधित मुआवजे की मांग पर भी सवाल उठाए। मप्र ने तर्कों से इन सभी दावों को खारिज कर दिया। गुजरात का दावा है कि मप्र ने मुआवजे के संबंध में मांगी जानकारी नहीं दी। वहीं मप्र सरकार ने इसका जवाब देते हुए लिखा

दोनों राज्यों में समन्वय नहीं

सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई को लेकर पिछले 30 साल से लड़ाई लड़ रहीं नर्मदा बचाओ आंदोलन की मेधा पाटकर कहती हैं कि नर्मदा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल यानी एनडब्ल्यूडीटी का फैसला कानून है। वन भूमि, शासकीय भूमि और पुनर्वास का खर्चा गुजरात को देना है। गुजरात अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर रहा है लेकिन मप्र उसके सामने क्यों चुप है, ये समझ से परे है। मप्र को अपना हक लेना चाहिए और लोगों का हक उन्हें देना चाहिए। लोग बिना पुनर्वास के ही मर रहे हैं। अगर ये राशि मिल जाए तो पुनर्वास आसानी से हो जाएगा। वहीं, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि इस मामले का समाधान बड़ी आसानी से हो सकता है, क्योंकि दोनों राज्यों और केंद्र में भाजपा की सरकार है। केंद्र सरकार गुजरात को भुगतान करने के लिए बाध्य करे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को दृढ़ता से ये बात प्रधानमंत्री से करनी चाहिए।

कि गुजरात ने जानकारी मांगने वाला पत्र 16 सितंबर 2003 को लिखा था। जो 26 सितंबर 2003 को हमें मिला। इस पत्र का कोई महत्व नहीं है क्योंकि इसके तुरंत बाद गुजरात सरकार ने 23 सितंबर 2003 को मुआवजे के दावे पर विचार करने से साफतौर पर मना कर दिया था।

गुजरात का दावा है कि 157.61 करोड़ रुपए की मांग को खारिज नहीं किया। मप्र का तर्क है कि गुजरात ने यह बयान बाद में सोचा है और यह पूरी तरह से झूठा और भ्रामक है। 7 अक्टूबर 2003 को दोनों राज्यों के अधिकारियों के बीच बैठक हुई थी। जिसमें डूब क्षेत्र में आने वाली मप्र की राजस्व और वन भूमि के **मूल्यांकन** से जुड़े विवाद का हल निकलना था, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकला। गुजरात ने मुआवजा देने से साफ इनकार किया, इसलिए मध्यस्थता के लिए जाना पड़ा। गुजरात का दावा है कि मप्र ने 2 सितंबर 2006 को मध्यस्थता आयोग को पत्र लिखा और मुआवजा दावा पेश किया। मप्र का तर्क है कि जून 2015 तक तो मध्यस्थता प्रक्रिया शुरू ही नहीं हुई थी। मध्यस्थों की पहली बैठक 23 जून 2015 को गुजरात के गांधीनगर में हुई, जिसमें मप्र से मुआवजे के संबंध में अपना दावा प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। इसके बाद अगले 6 साल तक बैठक नहीं केवल पत्राचार हुआ। बैठकों का सिलसिला 1 सितंबर 2021 से शुरू हुआ।

गुजरात का दावा है कि मप्र ने मुआवजा संबंधित दस्तावेज नहीं दिए। वहीं मप्र का तर्क है कि 12 अक्टूबर 2021 को मध्यस्थों की बैठक हुई थी, जिसमें मप्र सरकार से चार महीने के भीतर 11 फरवरी 2022 तक अपना मुआवजा दावा पेश करने के लिए कहा था। मप्र ने 10 फरवरी 2022 को ये दावा सौंप दिया था। इस बैठक में ये भी तय हुआ था कि गुजरात इस दावे पर 12 मई 2022 तक जवाब देगा। ऐसा न करते हुए गुजरात दस्तावेज मांगने लगा।

मप्र ने तर्कों से गुजरात के सारे दावों को खारिज किया तो गुजरात ने दो साल तक कोई जवाब नहीं दिया। 21 मार्च 2024 को मध्यस्थों की फिर बैठक हुई। बैठक के मिनट्स के मुताबिक, गुजरात ने एक पत्र में सुझाव दिया था कि वह 2001 में किए गए मप्र के दावों पर विचार करने के लिए तैयार है। यानी वह 281 करोड़ रुपए की पुरानी मुआवजा राशि को लेकर विचार कर सकता है। आगे लिखा कि उसके बाद के दावे खारिज किए जा सकते हैं। यानी करीब 8 हजार करोड़ की मुआवजा राशि देने पर वह सहमत नहीं है। इस पर मध्यस्थों ने संयुक्त रूप से कहा कि मप्र सरकार ने जो दावे 2022 में प्रस्तुत किए गए थे, वो ही माने जाएंगे।

मध्यस्थता बैठकों में शामिल रहे एनवीडीए के एक मौजूदा अधिकारी बताते हैं कि 2017 में जब पहली बार बांध भरा गया था, तब तक जमीन अधिग्रहण हो रहा था, इसलिए मध्यस्थता हो न हो, गुजरात जो भी पैसा दे रहा था वो पुनर्वास में खर्च हो रहा था। अब लेन-देन का पूरा वाजिब हिसाब करना है, जिसे लेकर दोनों राज्यों के बीच विवाद है। इसे लेकर मध्यस्थता हो रही है। मध्यस्थता में संबंधित पक्ष अपना दावा पेश करते हैं। कौन सही है और क्या सही है, ये मध्यस्थ ही तय करते हैं। इस विवाद का राजनीतिक हल निकल सकता है या नहीं, ये तो दोनों राज्यों के नेता ही तय करेंगे।

गुजरात के सरदार सरोवर नर्मदा निगम लिमिटेड के चीफ इंजीनियर शुभम गोयल ने माना कि मुआवजा विवाद से जुड़ी बैठकें हो रही हैं। करीब 8 हजार करोड़ की राशि पर विवाद है। हम लोग ये जांच रहे हैं कि मप्र ने जो डूब क्षेत्र बताया है, वो सही है या गलत है। जहां तक मप्र ने गुजरात के तथ्यों को झूठा और भ्रामक बताया है, वो सब आधारहीन हैं। इस विवाद का हल ढूंढने के लिए दोनों राज्य ठीक तरीके से काम कर रहे हैं, ताकि अंतिम फैसले पर पहुंचा जा सके।

गुजरात के आर्बिट्रेटर पीके लाहेरी ने बताया कि दोनों पक्षों ने पांच बैठकों में अपने-अपने प्रजेंटेशन दे दिए हैं। अब मुद्दे तय होंगे और सुनवाई आगे बढ़ेगी। समाधान कब तक होगा, यह दोनों राज्यों पर निर्भर करता है। दोनों राज्यों के बीच मुआवजे की राशि को लेकर बहुत बड़ा अंतर है। मप्र का एक पुराना क्लेम है और 2022 में उन्होंने एक संशोधित क्लेम पेश किया है। दूसरा क्लेम स्वीकार्य है या नहीं, यह भी मुद्दे तय करते समय साफ होगा। तभी हम लोग सटीक सुनवाई कर पाएंगे। अगर हमारे फैसले पर सहमति नहीं होगी तो सुप्रीम कोर्ट से जज की अपॉइंटमेंट ली जाएगी।

● **श्याम सिंह सिकरवार**

मां की तरह कई राज्यों को पाल रही नर्मदा

नर्मदा नदी मप्र की जीवन रेखा मानी जाती है। मप्र के विकास में अहम योगदान इसी नदी का माना जाता है। प्रदेश की जीवनदायनी नर्मदा नदी तीन हजार किलोमीटर लंबाई में बहती है और हरियाली के साथ आसपास के क्षेत्रों की समृद्धि और विकास को फैलाती है। नर्मदा नदी इंदौर, जबलपुर, भोपाल सहित कई शहरों और गांवों की प्यास बुझा रही है। नर्मदा मप्र में 1077 किलोमीटर, महाराष्ट्र में 32 किलोमीटर, महाराष्ट्र-गुजरात में 42 किलोमीटर एवं गुजरात में 161 किलोमीटर प्रवाहित होकर कुल 1312 किलोमीटर पश्चात् अंततः गुजरात में भरूच के निकट खंभात की खाड़ी के अरब सागर में समाहित होती है। मप्र और गुजरात की जीवनदायिनी नर्मदा का उद्गम स्थल अनूपपुर जिले के अमरकंटक में है। गांधी सागर, ओंकारेश्वर बांध, सरदार सरोवर जैसे बड़े बांध इसी नदी पर बने हैं। प्रदेश के सबसे बड़े शहर इंदौर की प्यास नर्मदा नदी 47 सालों से बुझा रही है। 1978 में नर्मदा के पहले चरण के कदम इंदौर में पड़े थे। इसके बाद दो चरण और तैयार हुए। अब चौथे चरण को लाने की तैयारी हो रही है। हर दिन तटबंधों को लांघकर मां नर्मदा 70 किलोमीटर की यात्रा करती है। 540 एमएलडी पानी हर दिन इंदौर की 40 लाख की आबादी की प्यास बुझाता है।

सौरभ शर्मा के बाद करीबियों की बारी

म प्र परिवहन विभाग के करोड़पति पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा की प्रॉपर्टी अप्रैल में अटैच की गई थी। ईडी ने इसे लेकर चालान भी पेश किया था। अब आयकर विभाग सौरभ की अटैच प्रॉपर्टी का ब्यौरा खंगालने की तैयारी में है। बता दें कि विभाग की बेनामी विंग ने सौरभ शर्मा, उसके सहयोगी चेतन सिंह गौर, शरद जायसवाल और अविरल कंस्ट्रक्शन की कई प्रॉपर्टीज को बेनामी प्रतिषेध अधिनियम के तहत अटैच किया था। अब उसके करीबियों और रिश्तेदारों की प्रॉपर्टी की जानकारी इकट्ठा की जा रही है। आयकर विभाग की टीम लगातार दस्तावेज खंगाल रही है। माना जा रहा है कि जल्द सौरभ शर्मा के रिश्तेदारों की प्रॉपर्टी भी अटैच कर ली जाएगी।

आयकर विभाग अब बेनामी रिकॉर्ड खंगाल रही है। पूर्व कॉन्स्टेबल और सहयोगियों की संपत्तियां पहले ही अटैच की जा चुकी हैं। अब उसके रिश्तेदारों की संपत्तियों की जानकारी जुटाई जा रही है। बताया जा रहा है कि रिश्तेदारों के नाम पर जमीन और प्रॉपर्टी की खरीदी की गई थी। इसकी जांच अब इनकम टैक्स विभाग कर रहा है। जानकारी के मुताबिक सौरभ शर्मा के जीजा और उनके परिवार की भी संपत्ति को आयकर विभाग अटैच कर सकता है। गौरतलब है कि 19 सितंबर 2024 को मेंडोरी के जंगल से आयकर विभाग ने करीब 52 किलो सोना और 11 करोड़ कैश जब्त किया था। इसके बाद भी ईडी और आयकर विभाग ने मामले की जांच शुरू कर दी थी। गाड़ी चेतन के नाम से रजिस्टर्ड थी। हालांकि सौरभ ने दावा किया था कि गाड़ी से बरामद हुए सोना और कैश उसका नहीं है।

सौरभ की मां उमा शर्मा के नाम पर विनय नगर ग्वालियर में प्लाट नंबर 103 है। जिसका मूल्य 30 लाख 33 हजार 500 रुपए है। उमा शर्मा के नाम पर चार अन्य प्रॉपर्टीज हैं। इसमें ग्वालियर में 130.11 वर्गमीटर का प्लॉट जिसकी कीमत 26 लाख 54 हजार 244 रुपए है। इसी तरह ग्वालियर के खेरियाकुलाठ में 0.387 हेक्टेयर खेती की जमीन जिसका मूल्य 14 लाख 24 हजार 160 रुपए है। साथ ही उमा शर्मा के नाम वाली ग्वालियर के कुशराजपुर में 1 बीघा खेती की जमीन जिसकी कीमत 19 लाख 51 हजार 500 रुपए है। वहीं भोपाल के अरेरा कॉलोनी में हाउसिंग बोर्ड का मकान ई-7 में डबल स्टोरी है जिसकी कीमत 1 करोड़ 67 लाख रुपए है। सौरभ की रिश्तेदार रेखा तिवारी को सौरभ की पत्नी दिव्या तिवारी द्वारा गिफ्ट की गई भोपाल के मुगालिया कोट में 0.506 हेक्टेयर जमीन जिसका मूल्य 32 लाख रुपए है। दिव्या तिवारी और रेखा तिवारी के नाम पर भैरोपुर भोपाल में 0.460 हेक्टेयर भूमि जिसका मूल्य 1 करोड़ 20 लाख रुपए है। इंदौर के सांवेर में शाकम्बरी एवेन्यू में प्लॉट नंबर 33 जिसका मालिक राजमाता भारत माता शिक्षा और समाज कल्याण समिति भोपाल है और कीमत 25 लाख 53 हजार 600 रुपए है। भोपाल के रत्नागिरी में फ्लैट नंबर एमआईजी 26 जो शरद जायसवाल के नाम पर है और कीमत 14 लाख 75 हजार रुपए है। भोपाल के हिनौतिया आलम में प्लाट नम्बर 1/1 जिसका एरिया 185.68 वर्गमीटर है। शरद जायसवाल इसका मालिक हैं और कीमत 25 लाख 62 हजार 384 रुपए है। भोपाल में अलंकार हाइट्स बावड़िया कला का एलआईजी फ्लैट 201 जिसका मालिक शरद जायसवाल है और कीमत 25 लाख 50 हजार रुपए है। भोपाल के हिनौतिया आलम में 66.91 वर्ग फीट का प्लॉट नंबर 1/2 जिसका मालिक शरद जायसवाल है और कीमत 9 लाख 23 हजार 358 रुपए है। भोपाल के शाहपुरा सेक्टर बी में निर्माणाधीन स्कूल जो 1851 वर्गमीटर में बन रहा था और इसका मालिक राजमाता भारतमाता शिक्षा और समाज कल्याण समिति भोपाल है। इसका मूल्य 13 करोड़ 9 लाख 95 हजार 232 रुपए है।

शरद जायसवाल और कुशल मंगल के नाम पर 2383.86 वर्गमीटर का प्लॉट एम्मार कांटिनेंटल सिटी नैनोद गांव इंदौर में है जिसका मूल्य 4 करोड़ 20 लाख रुपए है। इंदौर के एम्मार इंडिया लिमिटेड के 2104 वर्गमीटर का प्लाट शरद जायसवाल और गणेश इन्फ्रास्ट्रक्चर (रिपुसूदन पचौरी) के नाम पर है जिसकी कीमत 4 करोड़ 10 लाख 340 रुपए है। भोपाल के अरेरा कालोनी में ई-7/78 में दो मंजिला मकान जिसका मालिकाना हक इंस्टेंट यूआर इन्फ्रास्ट्रक्चर के नाम पर है और कीमत 1 करोड़ 84 लाख रुपए है। इंदौर में 352.36 वर्गमीटर का प्लाट एबी रोड पर जिसका मालिक इंस्टेंट यूआर इन्फ्रास्ट्रक्चर है और मूल्य 1 करोड़ 80 लाख रुपए है। भोपाल के सेवनिया गौड़ में रेखा तिवारी के नाम पर 1.22 हेक्टेयर खेती की जमीन जिसका मूल्य 72 लाख रुपए है। भोपाल में रेखा तिवारी के नाम पर 0.400 हेक्टेयर खेती की जमीन जिसका मूल्य 20 लाख रुपए है।

● **बृजेश साहू**

अविरल कंस्ट्रक्शन की ये संपत्तियां हो चुकी अटैच

भोपाल के भैरोपुर में 0.290 हेक्टेयर खेती की जमीन जिसका मालिक अविरल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन को बताया है और इसकी कीमत 87 लाख रुपए है। भोपाल के भैरोपुर में अविरल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की 0.27 हेक्टेयर जमीन जिसका मूल्य 90 लाख रुपए है। अविरल कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड की 0.41 हेक्टेयर खेती की जमीन जो भोपाल के भैरोपुर में है और उसकी कीमत 1 करोड़ 25 लाख रुपए है। भोपाल के भैरोपुर में ही अविरल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की खसरा नंबर 171/3 (5) की जमीन का मूल्य 52 लाख 14 हजार रुपए है। भोपाल के सेवनिया गौड़ में 0.1005 हेक्टेयर जमीन जिसका मालिक अविरल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है, कीमत 24 लाख रुपए है। भोपाल के कुशलपुरा में 0.405 हेक्टेयर जमीन जो अविरल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की है और मूल्य 20 लाख रुपए है। अविरल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की 0.200 हेक्टेयर भैरोपुर की जमीन जिसका मूल्य 68 लाख रुपए है। इंदौर जिले के सांवेर में 0.955 हेक्टेयर, 0.299 हेक्टेयर, 0.656 हेक्टेयर और 0.223 हेक्टेयर खेती की जमीन जो अविरल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के नाम पर है और कीमत 1 करोड़ 18 लाख 83 हजार रुपए है। अविरल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की 0.3251 हेक्टेयर खेती की जमीन जो इंदौर के हातोद तहसील के रेवती गांव में है। इसका मूल्य 59 लाख रुपए है। अविरल इंटरप्राइजेज लिमिटेड की भोपाल के बावड़िया कला में 0.30 हेक्टेयर जमीन जिसका मूल्य 1 करोड़ 97 लाख 50 हजार रुपए है।

तय नहीं हो पाया अग्निवीरों का कोटा

देश में अग्निवीर योजना लागू होने के बाद अर्द्धसैनिक बलों और राज्यों की सरकारों ने अपने यहां की पुलिस भर्ती में पूर्व अग्निवीरों के लिए कोटा तय किया है। इसी कड़ी में मप्र के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भी पुलिस और सशस्त्र बलों की भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को भर्ती करने की घोषणा की थी, लेकिन उनकी घोषणा के बाद भी कोटा तय नहीं हो पाया है। जानकारी के अनुसार, पूर्व अग्निवीर जवानों को आरक्षण देने संबंधी प्रस्ताव करीब तीन महीने से पुलिस मुख्यालय (पीएचक्यू) में अटका है। पीएचक्यू के वरिष्ठ अधिकारी तय नहीं कर पा रहे हैं कि पूर्व अग्निवीरों को पुलिस बल की भर्ती में आरक्षण दिया जाए या नहीं और दिया जाए, तो कितना?

उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2022 में अग्निपथ योजना लॉन्च की थी। अग्निपथ योजना के तहत हर साल 40-45 हजार युवाओं को सेना में शामिल करने का प्लान है, ये युवा साढ़े 17 साल से 23 साल की उम्र के बीच के होंगे। ये युवा अग्निवीर जवान कहलाते हैं। योजना में युवाओं को 4 साल तक नौकरी का मौका मिलता है। इसके बाद अग्निवीर रिटायर्ड हो जाते हैं। रिटायर्ड होने के बाद अग्निवीरों का क्या होगा, इसको लेकर योजना की शुरुआत से सवाल उठते रहे हैं। अग्निवीरों भविष्य सुरक्षित रहे और अधिक से अधिक युवा अग्निवीर बनने के लिए प्रेरित हों, इसलिए राज्य सरकारें उन्हें पुलिस व सशस्त्र बल में आरक्षण दे रही हैं। केंद्र सरकार ने वर्ष 2022 में अग्निपथ योजना लॉन्च की थी। इस योजना के तहत अग्निवीर जवानों के पहले बैच की 4 साल की सेवाएं सेवाएं वर्ष 2026 में पूरी हो जाएंगी। केंद्र सरकार इन अग्निवीर जवानों को रोजगार देने को लेकर सक्रिय हो गई है। मप्र समेत अन्य सभी राज्यों को पुलिस बलों की भर्ती में अग्निवीरों के लिए पद आरक्षित करने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। केंद्र सरकार का यह कदम पहले बैच के अग्निवीरों को नागरिक जीवन में स्थानांतरित करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है।

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 26 जुलाई 2024 को कारगिल विजय दिवस पर प्रदेश में पूर्व अग्निवीर जवानों को पुलिस और सशस्त्र बलों की भर्ती में आरक्षण देने की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था, अग्निवीर जवानों को मप्र में पुलिस और सशस्त्र बलों की भर्ती में आरक्षण दिया जाएगा। लेकिन उनकी घोषणा के एक साल बाद भी मप्र में पूर्व अग्निवीर जवानों के लिए पुलिस बल की भर्ती में आरक्षण देने को लेकर सरकार अंतिम निर्णय नहीं ले पाई है। जानकारी के मुताबिक केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने गत अप्रैल में मप्र सरकार को चिट्ठी लिखकर पुलिस बलों की भर्ती में पूर्व अग्निवीर जवानों को 20 प्रतिशत पद आरक्षित करने की सिफारिश की थी। पत्र में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त अग्निवीरों को राज्य स्तरीय कानून व्यवस्था बलों में स्थान देना उनके अनुभव का सही उपयोग होगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय से प्राप्त पत्र का अध्ययन करने के बाद गृह विभाग ने इसे पुलिस मुख्यालय को भेज दिया था। पुलिस मुख्यालय से कहा गया था कि वह पूर्व अग्निवीर जवानों को आरक्षण के संबंध में अंतिम निर्णय लेकर विभाग को अवगत कराए।

आधिकारिक जानकारी के मुताबिक पीएचक्यू के वरिष्ठ अधिकारियों का मानना है कि मप्र में पुलिस बल की भर्ती में वर्तमान में कुल 60 प्रतिशत (एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस) आरक्षण का प्रावधान है। यदि इसमें 35 प्रतिशत महिला आरक्षण को जोड़ दें, तो रिजर्वेशन का कोटा बढ़कर 95 प्रतिशत हो जाता है। ऐसे में पुलिस बल की भर्ती में पूर्व अग्निवीर जवानों को आरक्षण का प्रावधान करना व्यावहारिक और तर्कसंगत नहीं है। यही वजह है कि पीएचक्यू स्तर पर अब तक पूर्व अग्निवीरों को आरक्षण के संबंध में अंतिम निर्णय नहीं लिया जा सका है। गृह विभाग को आरक्षण के संबंध में पीएचक्यू के अभिमत का इंतजार है, ताकि इस दिशा में आगे की कार्रवाई की जा सके। विभाग इसको लेकर पीएचक्यू को रिमाइंडर भी भेज चुका है। अग्निवीरों को आरक्षण पुलिस आरक्षक भर्ती में दिया जाएगा। इसी आधार पर नए भर्ती नियम बनाए जाएंगे। सूत्रों का कहना है कि मप्र सरकार पुलिस बलों की भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने को लेकर विचार-विमर्श कर रही थी, लेकिन केंद्रीय मंत्री शाह ने मप्र में पुलिस बलों की भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को 20 प्रतिशत आरक्षण देने की सिफारिश की है। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव जेएन कंसोटिया का कहना है कि करीब तीन महीने पहले पूर्व अग्निवीर जवानों को आरक्षण देने संबंधी प्रस्ताव पुलिस मुख्यालय को भेजा गया था। वहां से प्रस्ताव वापस नहीं आया है। इस संबंध में पुलिस मुख्यालय को रिमाइंडर भी भेजा गया है। प्रस्ताव वापस आने के बाद ही इस दिशा में आगे कार्रवाई की जाएगी।

● **धर्मेंद्र कथूरिया**

विभागों के बीच समन्वय नहीं

मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि सामान्य प्रथा यह है कि मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा करने के बाद मुख्यमंत्री सचिवालय घोषणा को लागू करने के लिए संबंधित विभाग के साथ समन्वय करता है, लेकिन पूर्व अग्निवीरों को आरक्षण के मामले में मुख्यमंत्री सचिवालय और गृह विभाग के अधिकारियों ने सक्रियता नहीं दिखाई। यही वजह है कि अब तक इस संबंध में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया जा सका। अग्निवीर कोटा के मामले में आरक्षण प्रतिशत तय होने के बाद भर्ती नियम और अन्य विवरणों को सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अंतिम रूप दिया जाएगा। अपर मुख्य सचिव गृह एसएन मिश्रा का कहना है कि पूर्व अग्निवीर जवानों को पुलिस भर्ती में आरक्षण देने की प्रक्रिया चल रही है। हरियाणा और ओडिशा की भाजपा सरकारों ने पूर्व अग्निवीरों को पुलिस भर्ती में आरक्षण देने का निर्णय लिया है। हरियाणा सरकार ने तय किया है पूर्व अग्निवीरों को पुलिस भर्ती में 10 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। जो अग्निवीर 4 साल देश सेवा के बाद खुद का बिजनेस शुरू करना चाहेगा, उसे राज्य सरकार 5 लाख तक का बिना ब्याज लोन देगी।

कानूनी शिकंजे में माननीय

कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद पर धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज करने के बाद मप्र में उन विधायकों की कतार में एक नाम और जुड़ गया है, जिन पर बीते एक महीने में कानूनी शिकंजा कसा है और संकट बढ़ा है। मप्र में एक-दो नहीं सत्ता और विपक्ष के कुल पांच विधायक ऐसे हैं जिन पर अलग-अलग मामलों में कानूनी कार्रवाई की तलवार लटक रही है। कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा के साथ विधायक हेमंत कटारे और आरिफ मसूद की मुश्किलें इसी महीने में बढ़ी हैं। उधर भाजपा से विधायक अम्बरीश शर्मा के परिजनों पर कसे कानूनी शिकंजे की वजह से उनकी मुसीबत बढ़ गई हैं। भाजपा के ही विधायक संजय पाठक पर भी संकट बढ़ा है। मप्र के ये वो विधायक हैं जिन्हें तीन साल बाद जनता की अदालत में जाने के पहले इन मामलों से बरी होना जरूरी है। कांग्रेस के विधायक आरिफ मसूद पर जो मामला दर्ज किया गया है वो कॉलेज को मान्यता दिलाने से जुड़ा है। इसमें ये कहा गया है कि उन्होंने अपने कॉलेज को मान्यता दिलवाने में फर्जी कागजात दिलवाए थे। जबलपुर हाईकोर्ट ने इस कार्रवाई के निर्देश दिए थे। जिसके बाद भोपाल की एडिशनल डीसीपी शालिनी दीक्षित का कहना है कि कोर्ट ने जो आदेश दिया है उसके मुताबिक ही ये कार्रवाई की गई है, विधायक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। जिस कॉलेज के मामले में आरिफ मसूद पर एफआईआर हुई है उस इंदिरा प्रियदर्शिनी कॉलेज की मान्यता भी रद्द हो चुकी है और नए दाखिले भी रोक दिए गए हैं। इस पूरे मामले की जांच अब एसआईटी को सौंप दी गई। 90 दिन का समय जांच रिपोर्ट सौंपने के लिए दिया गया है। मसूद इस कॉलेज में सचिव हैं।

कांग्रेस के विधायक आरिफ मसूद के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। उन पर शहर के एक कॉलेज के लिए दो दशक पहले सरकारी मान्यता प्राप्त करने के वास्ते कथित तौर पर जाली दस्तावेजों के इस्तेमाल करने का आरोप है। मप्र उच्च न्यायालय द्वारा मसूद की ओर से ही दायर एक याचिका की सुनवाई के दौरान दिए गए आदेश के बाद यह कार्रवाई की गई है, जिसमें उन्होंने उच्च शिक्षा विभाग द्वारा कॉलेज की मान्यता रद्द किए जाने के फैसले को चुनौती दी थी। सहायक पुलिस आयुक्त अनिल बाजपेयी ने बताया कि कोहेफिजा पुलिस थाने में भारतीय दंड संहिता की धाराओं 420 (धोखाधड़ी) और 471 (जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन और न्यायमूर्ति प्रदीप मित्तल की जबलपुर स्थित खंडपीठ ने गत दिनों भोपाल पुलिस आयुक्त को तीन दिन के भीतर मसूद के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है। इसके अलावा, अदालत ने कहा कि पुलिस महानिदेशक मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल गठित करें। सरकार ने अमन एजुकेशन सोसाइटी द्वारा संचालित भोपाल स्थित इंदिरा प्रियदर्शिनी कॉलेज की मान्यता रद्द कर दी थी। इस कॉलेज के सचिव मसूद हैं। मसूद ने इस फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय का रुख किया था। उच्च न्यायालय ने मान्यता प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत किए गए कॉलेज की जमीन से संबंधित दस्तावेज मांगे। न्यायमूर्तियों ने समीक्षा के बाद पाया कि 2 अगस्त, 1999 को प्रस्तुत पहला बैनामा जाली था और एक और बैनामा प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया, लेकिन दूसरा बैनामा भी राजस्व अभिलेखों में दर्ज नहीं था। अदालत ने कहा कि इसके बावजूद भी कॉलेज दो दशकों से उसी बैनामा के आधार पर संचालित किया जा रहा था।

उधर, कांग्रेस विधायक हेमंत कटारे के खिलाफ बलात्कार का मामला री-ओपन हो गया है। अब 2018 के इस मामले की जांच फिर से कराई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में ये कहा है कि भोपाल रेंज के डीआईजी की देखरेख में इस मामले की जांच कराई जाए। कटारे को इतनी राहत दी है कि कोर्ट ने ये कह दिया है कि फिलहाल उनकी गिरफ्तारी नहीं की होगी। लेकिन उन्हें जांच में पूरा सहयोग देना होगा। मप्र सरकार ने 2 दिसंबर 2023 के हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए याचिका लगाई थी। उसी याचिका की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया है।

उधर, कांग्रेस के विधायक अभय मिश्रा पर मारपीट के मामले में मुश्किलें बढ़ गई हैं। उन पर एक कर्मचारी ने आरोप लगाया है कि जब विधायक से भुगतान मांगा गया तो उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर मारपीट की। पुलिस ने विधायक अभय मिश्रा समेत पांच लोंगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर ली है। हालांकि अभय मिश्रा का कहना है कि ये पूरा मामला राजनीतिक षड्यंत्र का है, जिसमें उन्हें फंसाया जा रहा है। उधर, भिंड जिले की लहार सीट से भाजपा के विधायक अम्बरीश शर्मा पर उनके परिजनों की वजह से संकट बढ़ गया है। विधायक के साले सुधांशु द्विवेदी पर एक महिला से ज्यादती करने के आरोप पर मामला दर्ज हुआ। जबकि पहले उन पर निवेशकों से 100 करोड़ से ज्यादा की रकम की ठगी का भी आरोप लगा, जिसमें वो जेल में हैं। इस मामले में पहले उन्हें मुंबई की ऑर्थर रोड जेल में बंद किया गया था। लेकिन विपक्ष का आरोप है कि सरकार के दबाव में उन्हें लहार की जेल में शिफ्ट करवा लिया गया ताकि उन्हें सारी सुविधाएं मिल सकें। पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉ. गोविंद सिंह ने ये आरोप लगाया है कि सुधांशु द्विवेदी को लहार लाया ही इसलिए गया है कि उन्हें वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा सके।

● **लोकेश शर्मा**

विधानसभा में उठ चुका संजय पाठक का मामला

भाजपा से विधायक और पूर्व मंत्री संजय पाठक लंबे समय से मुश्किलों में हैं। जानकारी के मुताबिक, अवैध खनन के मामले में संजय पाठक से जुड़ी कंपनियों से 400 करोड़ रुपए से ज्यादा की वसूली हो सकती है। ये मामला लौह अयस्क की खदानों का है। जिसमें पाठक की कंपनियों से करीब 443 करोड़ रुपए की वसूली होनी है। असल में ये मामला विधानसभा में भी उठा था। कांग्रेस विधायक अभिजीत शाह ने प्रश्न उठाया कि आखिर आनंद माइनिंग, निर्मला मिनरल्स और पैसिफिक एक्सपोर्ट में जितने की मंजूरी है उससे ज्यादा माइनिंग और सरकार को 1 हजार करोड़ की राशि नहीं जमा करने को लेकर जो शिकायत की गई उसमें क्या कार्रवाई हुई। इस पर सरकार की ओर से मंत्री चेतन कश्यप ने जवाब दिया था कि इस शिकायत को लेकर जांच दल बनाया गया था। इस दल ने जो प्रतिवेदन सौंपा उसमें करीब 443 करोड़ रुपए की वसूली करने का कहा गया है। सरकार ने सदन में ये भी बताया कि कार्रवाई की वजह से फिलहाल ये वसूली नहीं हो सकी है।

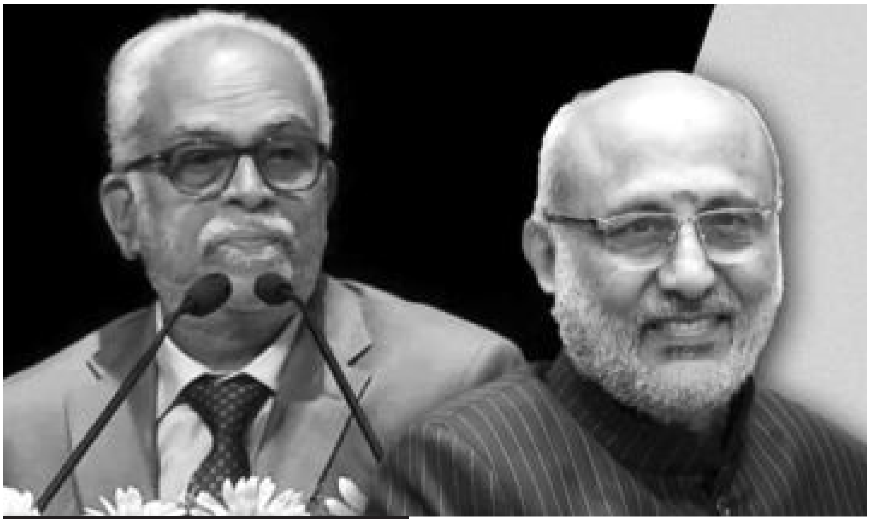

दक्षिण बनाम दक्षिण

नए उपराष्ट्रपति के सामने हैं काफी चुनौतियां

पिछले उपराष्ट्रपति चुनाव में लोकसभा में भाजपा के अपने ही 303 सांसद थे, लेकिन 2024 के चुनाव के बाद यह संख्या सिकुड़कर 240 रह गई है। दो बार पूर्ण बहुमत की सत्ता के बाद भाजपा को गठबंधन के सहयोगियों पर आश्रित होकर सरकार चलानी पड़ रही है। इसलिए रेड्डी के जरिये वह भाजपा के दक्षिणी दांव की काट के साथ ही उसके राजनीतिक समर्थन में भी सेंधमारी की उम्मीद लगाए है। इसके बावजूद राधाकृष्णन के उपराष्ट्रपति बनने की राह में कोई खास कांटे नहीं दिख रहे हैं। सरकार उनके चुनाव को लेकर आश्वस्त है और आंकड़े भी पूरी तरह उसके पक्ष में हैं। हालांकि चुनाव के बाद नए उपराष्ट्रपति को काफी चुनौतियों के साथ जूझना होगा। इसमें सबसे बड़ी चुनौती उच्च सदन में विपक्ष को साथ लेकर चलने की होगी, जो चुनाव आयोग से लेकर तमाम मुद्दों पर सरकार के खिलाफ आक्रामक है।

पिछले महीने जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे से रिक्त हुए उपराष्ट्रपति पद के लिए 9 सितंबर को मतदान होना है। सत्तापक्ष और विपक्ष ने अपने-अपने उम्मीदवार भी तय कर लिए हैं। जहां भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी राजग ने महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को प्रत्याशी बनाया है, वहीं विपक्षी दलों के मोर्चे आईएनडीआईए ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस बी. सुदर्शन रेड्डी पर दांव लगाया है। वे आंध्र के हैं, जबकि सीपी राधाकृष्णन तमिलनाडु के। स्पष्ट है कि दक्षिण बनाम दक्षिण का यह मुकाबला कई पैमानों पर रोचक होने जा रहा है। संवैधानिक व्यवस्था और आदर्श लोकतांत्रिक ढांचे में उपराष्ट्रपति से राजनीतिक रूप से निरपेक्ष एवं तटस्थ रहने की अपेक्षा होती है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति जैसे पदों की शपथ भी इस मायने में कुछ अलग होती है। उसमें संविधान के प्रति निष्ठा जैसे अन्य-पहलुओं के साथ संविधान की रक्षा के बिंदु पर भी जोर होता है। उपराष्ट्रपति केवल एक महत्वपूर्ण संवैधानिक पद ही नहीं, बल्कि उसके पास राज्यसभा के संचालन का दायित्व भी होता है। ऐसे में, राजनीतिक कारणों और विधायी एजेंडे की दृष्टि से सत्तापक्ष के लिए इस पद की अहमियत और बढ़ जाती है। वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए इस चुनाव का महत्व भी काफी बढ़ गया है।

जब जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया था तब तात्कालिक रूप से यही कारण बताया गया कि स्वास्थ्य के आधार पर वे अपना पद छोड़ रहे हैं, लेकिन उसके बाद का घटनाक्रम दर्शाता है कि उनकी एकाएक विदाई के पीछे कुछ और कारण रहे। सार्वजनिक जीवन में धनखड़ की सक्रियता के एकदम सीमित हो जाने से भी इन संदेहों को बल मिला कि बात उतनी सीधी भी नहीं, जितनी बताई गई। कई विपक्षी राजनीतिक दलों ने धनखड़ द्वारा सार्वजनिक जीवन से एकाएक दूरी बनाए जाने को लेकर सवाल भी उठाए। अब इससे इनकार करना मुश्किल है कि सत्तापक्ष के साथ असहज हुए राजनीतिक समीकरण ही धनखड़ के इस्तीफे का कारण बने। राजग के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन के स्वागत समारोह में प्रधानमंत्री मोदी की यह टिप्पणी कि वे राजनीतिक खेल नहीं करेंगे, उन्हीं अटकलों को बल देती है कि धनखड़ और सरकार के बीच अविश्वास की खाई इतनी चौड़ी हो गई थी कि फिर कभी भर नहीं पाई।

दोनों खेमों के प्रत्याशियों पर नजर डालें तो प्रत्येक पक्ष ने बहुत संभलकर कदम बढ़ाए हैं। धनखड़ का भाजपा की मूल विचारधारा के साथ बहुत गहरा संबंध नहीं था और वह दूसरे दलों से होते हुई भाजपा में आए और पार्टी ने अपनी परंपरा से इतर उन्हें एक शीर्ष संवैधानिक पद पर बिठाया। उनके साथ हुए अनुभव से सबक लेते हुए भाजपा ने इस बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ाव रखने वाले अपने खांटी कार्यकर्ता सीपी राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाया है। उनके पास लंबा राजनीतिक अनुभव भी है। भाजपा के लिए अपेक्षाकृत अनुर्वर राजनीतिक भूमि तमिलनाडु से वे पार्टी के सांसद भी रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष के रूप में उनकी सक्रियता खासी चर्चित रही। उन्होंने केरल जैसे राज्य में चुनाव प्रभार का जिम्मा भी संभाला।

पहले झारखंड और फिर महाराष्ट्र में राज्यपाल भी रहे। उनके माध्यम से भाजपा कई निशाने साधने के प्रयास में है। तमिलनाडु में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पार्टी एक राजनीतिक संदेश देने का भी काम करेगी। राज्य में सत्तारूढ़ द्रमुक केंद्र सरकार को लेकर खासी आक्रामक रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नीट परीक्षा, हिंदी भाषा एवं वित्तीय संसाधनों और संभावित लोकसभा परिसीमन के मुद्दे पर राज्य सरकार ने केंद्र और भाजपा को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ा। परिसीमन के मुद्दे पर तो दक्षिण के अन्य राज्यों को भी लामबंद करने का प्रयास किया। ऐसे में राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति बनाकर भाजपा ऐसे हमलों की धार कुंद करने की कोशिश करेगी।

विपक्षी खेमे ने भी भाजपा की इस रणनीति को भांपते हुए दक्षिण भारत से ही अपना उम्मीदवार बनाया। इसके जरिये उसने दोहरी व्यूह रचना की है। एक तो मुकाबले को दक्षिण बनाम दक्षिण करना और तमिल बनाम तेलुगु अस्मिता के जरिये राजग की सबसे बड़ी सहयोगी तेलुगु देशम पार्टी के समर्थन में सेंध लगाने की कोशिश। राज्यसभा में अक्सर राजग का समर्थन करने वाली जगनमोहन रेड्डी की पार्टी के लिए भी इससे दुविधा खड़ी हो सकती है। वैसे तो चंद्रबाबू नायडू और रेड्डी से विपक्षी खेमे को समर्थन का कोई आश्वासन नहीं मिला है, लेकिन तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के बयानों से साफ है कि विपक्ष तेलुगु अस्मिता का मुद्दा खड़ा करने का प्रयास करेगा। हालांकि अगर तेलुगु अस्मिता के नाम पर नायडू और रेड्डी के समक्ष धर्मसंकट खड़ा करने का प्रयास होगा तो द्रमुक के मुखिया और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन को भी एक तमिल उम्मीदवार का पुरजोर विरोध करने की दुविधा घेरेगी। इस चुनाव के माध्यम से विपक्ष सरकार की उस कमजोर नस को दबाने में लगा है, जो पिछले आम चुनाव के बाद उभरी। यह कमजोरी है संसद में भाजपा का घटा आधार।

● विकास दुबे

अब मप्र बनेगा ऑयल सीड हब

मप्र में खेती और यहां का शरबती गेहूं देश-दुनिया में पहचान रखता है। प्रदेश में खेती को बढ़ावा देने के लिए लगातार नए प्रयोग भी होते रहे हैं। यही वजह है कि लगातार कृषि क्षेत्र में अग्रसर मप्र अब ऑयल सीड हब बनने जा रहा है। जिसके तहत प्रदेश के तीन जिलों में स्पेशल प्रोग्राम चलाया जाएगा। यहां के किसान अब तीन फसलों के बीज खरीदेंगे नहीं बल्कि उगाएंगे और ये बीज सरकार के जरिए अन्य किसानों की आपूर्ति करेंगे।

ये सभी जानते हैं कि किसी भी फसल से उसके बीज का दाम काफी ज्यादा होता है। लेकिन आमतौर पर किसान बीज सहकारी समितियों की मदद से खरीदते हैं, गेहूं-धान से हटकर मप्र में तिलहन फसलें यानी सोयाबीन, सरसों और मूंगफली की खेती भी प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्रों में लगाई जाती है। लेकिन इन फसलों के लिए बढ़ते रकबे के हिसाब से कृषि संस्थान भी पर्याप्त बीज नहीं उपलब्ध करा पा रहे हैं। यही वजह है कि अब मप्र में एक विशेष प्रोजेक्ट लाया गया है, जो किसानों को उन्नत खेती के साथ भी कमाई का नया जरिया बनेगा। भारत सरकार ने ग्वालियर के राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय को ऑयल सीड हब प्रोजेक्ट का हिस्सा बनाया है। जिसके तहत मप्र के तीन जिलों में प्रदेशभर के किसानों को तिलहन फसलों के बीज उपलब्ध कराने के लिए बीज तैयार कराए जाएंगे जिसे सीड हब नाम दिया गया है। इन सीड हब में तीन प्रमुख फसलों के बीज तैयार कराए जाएंगे। पहले ऑयल सीड हब सीहोर में स्थापित किया जाएगा। जहां सोयाबीन के बीज तैयार होंगे। दूसरा मूंगफली के लिए शिवपुरी में और तीसरा हब मुरैना में सरसों के बीज के लिए है।

राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रो. अरविंद कुमार शुक्ला ने बताया कि पिछले कुछ वर्षों में मालवा के अलावा चंबल के शिवपुरी क्षेत्र में किसान मूंगफली की फसल लगाने लगे हैं। ऐसे में उन्हें मूंगफली की नई-नई प्रजातियों की जरूरत है। कृषि विश्वविद्यालय ने मूंगफली की दो किस्में तैयार भी की हैं। इसके अलावा इस क्षेत्र में मूंगफली का रकबा भी लगातार बढ़ रहा है। पिछले साल के मुकाबले इस साल भी लगभग 1 लाख हेक्टेयर रकबा मूंगफली का बढ़ा है। ऐसे में मूंगफली के बीज किसानों को उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। सीड हब प्रोजेक्ट इसे नई दिशा देगा। सीड हब प्रोग्राम के तहत विश्वविद्यालय द्वारा किसी क्षेत्र में चयनित किसानों को फसल के बीज उपलब्ध कराए जाते हैं। इसके बाद किसान इनकी बुवाई कर फसल तैयार करता है। फसल में समय पर और जरूरी पोषण के लिए अच्छी गुणवत्ता का खाद दिया जाता है, और फसल पकने पर उसे हार्वेस्ट कर लिया जाता है। यह कार्य कृषि वैज्ञानिकों की देखरेख में पूरा किया जाता है। यही फसल उन्नत किस्म के बीज के तौर पर तैयार होगी और फिर कृषि विश्वविद्यालय उनसे यह फसल बीज के लिए लेगा। उसे प्रोसेस करेगा और फिर अन्य किसानों को उपलब्ध कराएगा।

कृषि विश्वविद्यालय के कुलगुरु के मुताबिक, आमतौर पर तैयार फसल का उपयोग किसान बीज के तौर पर नहीं कर पाते हैं। जिसकी बड़ी वजह है फसल में अलग-अलग तरह के बीजों का समावेश। असल में जब किसान खेत में फसल की बुवाई करता है तो उसके लिए कई किस्म के बीज उपयोग में ले लेता है। उदाहरण के लिए जब सरसों की बुवाई होती है तो उसमें कई बार काली सरसों के साथ कम पड़ने पर पीली सरसों या दूसरी वेराइटी के बीज बो दिए जाते हैं। जिसकी वजह से खेत में तैयार फसल में वेरिएशन आ जाता है और किसानों को उस सरसों को फसल की तरह ही बेचना पड़ता है। क्योंकि वह फसल सिर्फ तेल या सरसों के उपयोग की ही होती है। लेकिन सीड हब प्रोग्राम में किसानों को एक ही वेराइटी का बीज उपलब्ध कराया जाएगा और उससे तैयार फसल बीज के तौर पर उपयोग हो सकेगी। असल में मूल रूप से फसलों के बीज तैयार करने की व्यवस्था कृषि संस्थानों पर होती है (निजी कंपनियों को छोड़कर), लेकिन यहां लगाई जाने वाली फसलें काफी सीमित क्षेत्र में ही लगाई जा सकती हैं। ऐसे में डिमांड के अनुसार, बीज व्यापक मात्रा में यहां तैयार नहीं किया जा सकता। इस स्थिति में किसान एक बेहतरीन विकल्प है, क्योंकि किसान अपने ही खेत में बीज के लिए फसल लगाएगा तो कृषि विश्वविद्यालय को अलग से जमीन की भी जरूरत नहीं होगी। साथ ही तैयार बीज से किसानों के लिए बीज की आपूर्ति भी आसानी से हो सकेगी।

● **हर्ष सक्सेना**

किसानों को कैसे होगा फायदा?

जब सवाल आता है कि, पूरी मेहनत किसान की और बीज संस्थान लेगा तो किसानों का क्या फायदा? तो आपको बता दें कि यह किसान के लिए फायदेमंद सौदा होगा। क्योंकि, पहले तो इस प्रोग्राम के तहत कृषि वैज्ञानिक किसानों को फसल के जरिए बीज तैयार करना सिखाएंगे। जिससे भविष्य में वे खुद अपनी ही फसलों से भी बीज तैयार कर सकेंगे और उन्हें बाहर से बीज नहीं खरीदना पड़ेगा जो उनकी लागत को कम करेगा। दूसरा बड़ा फायदा फसल के दाम में अंतर आएगा। क्योंकि अमूमन आम फसल के दाम काफी कम होते हैं लेकिन उस फसल का बीज ऊंचे दाम पर बिकता है। उदाहरण के लिए सोयाबीन फसल का रेट लगभग 3 हजार से 5 हजार रुपए प्रति क्विंटल है। जबकि सोयाबीन के बीज की कीमत बाजार में 7 हजार रुपए से लेकर 35 हजार रुपए प्रति क्विंटल तक उपलब्ध है। जब विश्वविद्यालय उनकी तैयार फसल खरीदेगा तो वह बीज के रेट पर खरीदेगा और उन्हें दोगुने से तीन गुना तक ज्यादा दाम मिलेगा, जो उनकी आय बढ़ाएगा। किसान चाहे तो खुद के द्वारा तैयार बीज अन्य किसानों को भी बेच सकेंगे। जैसा कि हमने पहले बताया कि चंबल अंचल के शिवपुरी क्षेत्र में मूंगफली अब व्यापक स्तर पर किसान लगा रहे हैं। ऐसे में मूंगफली सीड हब शिवपुरी में लगाया जाएगा, इसके अलावा दूसरा प्रोजेक्ट सोयाबीन सीड हब का है।

साइलेंट किलर बन रहा फैटी लिवर

बुंदेलखंड क्षेत्र के लोगों के लिए नॉन-अल्कोहोलिक फैटी लिवर डिजीज एक नई स्वास्थ्य चुनौती बनकर फिर उभरकर सामने आई है। यह रोग धीरे-धीरे, बिना स्पष्ट लक्षणों के शरीर को अंदर से नुकसान पहुंचाता है और जब तक इसकी पहचान होती है, तब तक यह गंभीर स्तर पर पहुंच चुका होता है। स्थानीय मेडिकल कॉलेज की ओर से किए गए रिसर्च में यह सामने आया है कि क्षेत्र में इस बीमारी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। शोधकर्ताओं ने बताया कि इस बीमारी की प्रमुख वजहें बेतरतीब दिनचर्या, अनियमित खानपान, मादक पदार्थों का सेवन तथा फास्ट-फूड की अधिकता बताई जा रही है। बुंदेलखंड के ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्रों में लोगों की जीवनशैली में तेजी से बदलाव आया है, जिसमें शारीरिक मेहनत की जगह निष्क्रियता और पौष्टिक भोजन की जगह तैलीय व जंक फूड ने ले ली है।

मेडिकल कॉलेज के मेडिसिन विभाग के अध्यक्ष डॉ. कुलदीप चंदेल का कहना है कि नॉन-अल्कोहोलिक फैटी लिवर डिजीज की स्थिति में लिवर में चर्बी जमा होने लगती है, जिससे शरीर में एसजीओटी और एसजीपीटी नामक एंजाइमों का स्तर तेजी से बढ़ जाता है। ये एंजाइम इस बात का संकेत हैं कि व्यक्ति के शरीर में लिवर या हृदय की कोशिकाएं प्रभावित हो रही हैं। ऐसे में व्यक्ति को पाचन संबंधी दिक्कतें, मधुमेह, हाइपरटेंशन और कोलेस्ट्रॉल जैसी परेशानियां घेर लेती हैं। डॉ. चंदेल कहते हैं कि इस रोग के शुरुआती संकेत इतने हल्के होते हैं कि मरीज उन्हें अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। परंतु जब रोग बढ़ता है, तब शारीरिक थकावट, पेट में दर्द और भूख में कमी जैसी समस्याएं सामने आने लगती हैं। इन लक्षणों को यदि व्यक्ति के द्वारा समय रहते गंभीरता से न लिया जाए, तो व्यक्ति को लिवर सिरोसिस जैसी जानलेवा स्थिति का भी सामना करना पड़ सकता है। बुंदेलखंड के झांसी में मेडिकल कॉलेज की ओर से किए गए एक वर्ष लंबे शोध में 302 मरीजों की जांच की गई तो नतीजों ने चौंकाने वाला सच उजागर किया। 80 प्रतिशत मोटे लोगों में फैटी लिवर पाया गया। वहीं, 46 फीसदी डायबिटिक मरीज, 66 फीसदी उच्च कोलेस्ट्रॉल से ग्रसित व्यक्ति और 40 प्रतिशत थायराइड व ब्लड प्रेशर के रोगी इस बीमारी से पीड़ित पाए गए। इस अलार्मिंग स्थिति से बचने के लिए विशेषज्ञों का तो यह भी कहना है कि नियमित स्वास्थ्य जांच कराना भी अतिआवश्यक है। खासतौर पर पेट संबंधी समस्याओं या पहले से किसी गंभीर रोग से ग्रस्त व्यक्तियों को सबसे ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। फैटी लिवर की पुष्टि होने पर डॉक्टरी परामर्श के अनुसार चिकित्सा लेना और दिनचर्या में बदलाव लाना लोगों के लिए बेहद जरूरी हो जाता है। इसके लिए दिन की शुरुआत होते ही सबसे पहले योग, प्राणायाम और हल्की कसरत करनी चाहिए। भोजन में ज्यादा से ज्यादा हरी सब्जियों, फाइबर युक्त अनाज और कम वसा वाले पदार्थों का सेवन करना चाहिए। साथ ही शराब और तली-भुनी चीजों से दूर रहना बेहद जरूरी है। बुंदेलखंड की यह बदलती स्वास्थ्य तस्वीर एक चेतावनी भी है कि यदि समय रहते सचेत नहीं हुए, तो आने वाले वर्षों में यह साइलेंट किलर अनेक परिवारों की शांति भी छीन सकता है।

शराब से ही नहीं बल्कि वसा युक्त भोजन, फास्ट फूड, शुगर व थायराइड रोगी भी लिवर सिरोसिस की चपेट में आ रहे हैं। बुंदेलखंड में इन रोगियों की संख्या दिन पर दिन तेजी से बढ़ रही है। मेडिकल कॉलेज की ओपीडी में फैटी लीवर के रोजाना 35 रोगी आ रहे हैं, जिनमें से औसतन तीन में लिवर सिरोसिस मिल रही है। मेडिकल कॉलेज के वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. जकी सिद्दीकी के अनुसार, आम धारणा है कि शराब पीने के आदी लोग ही फैटी लिवर, लिवर सिरोसिस व फाइब्रोसिस के शिकार होते हैं जबकि ऐसा नहीं है। शराब पीने वालों के साथ-साथ बिना मेहनत किए ही ज्यादा वसायुक्त भोजन करने वाले तथा फास्ट फूड का सेवन करने वाले भी फैटी लिवर का शिकार हो रहे हैं। वहीं, शुगर व थायराइड के रोगियों में भी यह दिक्कत तेजी से हो रही है। उन्होंने बताया कि फैट जमा होने से लिवर पर दबाव बढ़ने लगता है और लिवर की सेल्स में चर्बी जमा होने लगती है। जब यह बढ़ जाती है, तो लिवर सिरोसिस हो जाता है। जब सिरोसिस का समय पर उपचार नहीं होता है, तो लिवर फाइब्रोसिस हो जाती है जिससे खून का संचार कम हो जाता है। इससे खून की उल्टी, पेट में पानी भरना, बेहोशी आना अथवा लीवर कैंसर हो जाता है।

● **सिद्धार्थ पांडे**

फैटी लिवर क्यों है खतरनाक?

बहुत से लोग फैटी लिवर को मामूली समस्या समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि फैटी लिवर सिर्फ एक बीमारी नहीं बल्कि कई गंभीर बीमारियों की जड़ बन सकता है। जब लिवर में फैट बढ़ता है तो यह धीरे-धीरे शरीर के अन्य अंगों तक भी फैलने लगता है। खून में फैट मिलते ही कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ जाता है जिससे दिल की नसों में चर्बी जमा होने लगती है और हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। अगर यही फैट दिमाग तक पहुंच जाए तो ब्रेन स्ट्रोक की स्थिति बन सकती है। वहीं गॉलब्लैडर में फैट जमा होने पर पथरी यानी स्टोन बनने की संभावना बढ़ जाती है और किडनी में फैट जमने से उसका सामान्य कार्य भी प्रभावित होने लगता है। कहने का मतलब यह है कि फैटी लिवर एक साइलेंट किलर की तरह पूरे शरीर की सेहत को अंदर से हिला सकता है। आईसीएमआर की रिपोर्ट में इस बात पर भी खास तौर पर रोशनी डाली गई है कि आईटी सेक्टर में काम करने वाले लोग फैटी लिवर की बीमारी से सबसे ज्यादा क्यों प्रभावित हो रहे हैं। इस क्षेत्र में काम करने वाले अधिकांश युवा दिनभर 9-10 घंटे तक लगातार कुर्सी पर बैठकर कम्प्यूटर के सामने काम करते हैं, जिससे उनकी शारीरिक गतिविधि लगभग न के बराबर रह जाती है। इसके अलावा फास्ट फूड, जंक फूड और बाहर का तला-भुना खाना उनकी रोजमर्रा की आदत में शामिल हो चुका है। पर्याप्त नींद न लेना, लगातार तनाव में रहना और समय पर भोजन न करना भी उनकी लाइफस्टाइल का हिस्सा बन गया है। इन सभी कारणों का सीधा असर उनके मेटाबोलिज्म पर पड़ता है, जो धीरे-धीरे बिगड़ने लगता है और परिणामस्वरूप लिवर में चर्बी जमा होने लगती है, जिससे फैटी लिवर की समस्या जन्म लेती है।

अपनी मनमानी नीतियों के कारण विश्व के अन्य देशों पर टैरिफ लगाकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दादागिरी करने का जो अभियान चलाया है, उसका परिणाम यह देखने को मिल रहा है कि अमेरिका की बादशाहत ही खतरे में पड़ गई है। अमेरिका की सबसे बड़ी चुनौती भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाने के बाद शुरू हुई है, क्योंकि इसके बाद विश्व में महाशक्तियों का त्रिकोण बनने लगा है। यानि भारत, रूस और चीन एक साथ आ गए हैं। इससे ब्रिक्स सहित अन्य देश महाशक्ति के त्रिकोण की ओर विश्वास भरी नजरों से देख रहे हैं। महाशक्ति के इस त्रिकोण ने अमेरिका की परेशानी और बढ़ा दी है।

● राजेंद्र आगाल

आखिरकार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगाने की अपनी धमकी पर अमल करके ही माने। उन्होंने यह मनमाना अतिरिक्त टैरिफ इस आरोप में जुर्माने के रूप में थोपा है कि भारत रूस से तेल खरीद रहा है और इस तरह यूक्रेन में युद्ध जारी रखने में उसकी मदद कर रहा है। यह है तो नितांत निराधार निष्कर्ष, लेकिन ट्रंप ऐसे ही बेतुके आरोप लगाने और निष्कर्ष निकालने के लिए जाने जाते हैं। यह अच्छा है कि भारत पहले दिन से ट्रंप की मनमानी टैरिफ नीति का मुकाबला करने की दृढ़ता दिखा रहा है। ट्रंप के टैरिफ का परिणाम यह देखने को मिल रहा है कि चीन में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) की बैठक में भारत, रूस और चीन तीन महाशक्तियां एक हो गई हैं। इसका परिणाम भी सामने आने लगा है और अमेरिका में इस मुलाकात के बाद खलबली मच गई है। जो इस बात का संकेत है कि अमेरिका की बादशाहत खत्म होती दिख रही है।

दरअसल, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस समय भारत से अपनी व्यक्तिगत खुन्नस निकाल रहे हैं। तभी तो उन्होंने सारे देशों को छोड़ सिर्फ भारत पर ही 50 फीसदी का टैरिफ ठोक दिया है। ट्रंप के दायरे में भारत ही नहीं, रूस और चीन भी आ गए हैं। इसका मतलब है कि अमेरिकी राष्ट्रपति इस समय रूस, भारत और चीन पर एकसाथ हमलावर हो गए हैं। ऐसे में हर आदमी के मन में यही सवाल उठ रहा कि क्या ये तीनों देश मिलकर अमेरिका की दादागिरी खत्म कर सकते हैं। अमेरिका को सबसे ज्यादा लाभ ग्लोबल मार्केट में डॉलर में होने वाले ट्रेड से होता है। तो क्या, रूस-भारत और चीन मिलकर डॉलर का मुकाबला कर सकते हैं। इस बात का जवाब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की झुंझलाहट से ही मिल जाता है। आपको याद होगा जब ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान ट्रंप ने डॉलर का विकल्प बनाने को लेकर रूस, भारत और चीन को धमकी दी थी। ट्रंप ने कहा था कि अगर ब्रिक्स देश मिलकर डॉलर कमजोर करने की साजिश करते हैं तो इन देशों पर 100 फीसदी टैरिफ लगा दिया जाएगा। फिलहाल भारत ने ऐसी कोई कोशिश नहीं की और उस पर ट्रंप 50 फीसदी का टैरिफ लगा चुके हैं। जाहिर है कि उनके मन में इस बात को लेकर काफी डर है कि अगर तीनों देश साथ आ गए तो डॉलर को नुकसान हो सकता है।

अमेरिकी डॉलर को टक्कर देने के लिए भारत ने भले ही अभी तक कोई खास कदम न उठाया हो, लेकिन रूस और चीन लंबे समय से कोशिश कर रहे हैं। चीन ने अपने ज्यादातर साझेदारों से स्थानीय मुद्रा युआन में कारोबार बढ़ाना शुरू कर दिया है। रूस ने भी यूक्रेन युद्ध के बाद डॉलर में लेनदेन को काफी हद तक कम किया है और अपनी स्थानीय मुद्रा में कारोबार कर रहा है। वैसे तो भारत ने भी ईरान, रूस सहित कुछ देशों के साथ रुपए में लेनदेन किया

दिसंबर में भारत दौरे पर आएंगे राष्ट्रपति पुतिन

रूसी राष्ट्रपति पुतिन इस साल दिसंबर में भारत आएंगे। रूस के राष्ट्रपति ऑफिस क्रेमलिन ने इसकी पुष्टि की है। 2022 में यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद पुतिन का यह पहला भारत दौरा होगा। यह यात्रा ऐसे समय पर हो रही है जब भारत और रूस अपनी साझेदारी को और मजबूत कर रहे हैं, जबकि अमेरिका भारत पर रूस से तेल खरीदने की वजह से आर्थिक दबाव बढ़ा रहा है। पुतिन चीन में होने वाली एससीओ समिट के दौरान भी प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। इस दौरान उनकी भारत यात्रा की तैयारियों पर भी चर्चा होगी। रूस की तरफ से यह घोषणा तब आई है जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प ने भारत के निर्यात पर कुल 50 प्रतिशत टैरिफ लगाए हैं। इसमें से 25 प्रतिशत एक्स्ट्रा टैरिफ रूसी तेल खरीद की वजह से लगाया गया है। अमेरिका का कहना है कि इससे रूस को यूक्रेन युद्ध जारी रखने में मदद मिल रही है। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजीत डोभाल ने इस महीने की शुरुआत में मॉस्को यात्रा के दौरान क्रेमलिन में पुतिन से मुलाकात की थी। यह मुलाकात सुरक्षा, आर्थिक और ऊर्जा सहयोग पर द्विपक्षीय वार्ता के लिए हुई थी। इस दौरान भारतीय एनएसए ने कहा था कि हमारा रिश्ता बहुत खास और पुराना है। हम अपनी रणनीतिक साझेदारी को बहुत महत्व देते हैं। हमें राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा की खबर से बहुत खुशी है। तारीखें लगभग तय हो चुकी हैं। पुतिन ने आखिरी बार 6 दिसंबर 2021 में भारत की यात्रा की थी। तब वे सिर्फ 4 घंटे के लिए भारत आए थे। इस दौरान भारत और रूस के बीच 28 समझौते पर दस्तखत हुए थे।

है, लेकिन अभी तक ग्लोबल मार्केट में कोई उल्लेखनीय डील स्थानीय करेंसी में नहीं हुई। हां, अगर तीनों ही देश मिलकर अपनी-अपनी करेंसी में कारोबार शुरू करते हैं तो डॉलर को कड़ी टक्कर दी जा सकती है।

क्या हो सकती है रणनीति

अमेरिका को अपनी बादशाहत कायम रखने और कारोबार बढ़ाने के लिए बड़े बाजार की जरूरत है। यह बात पूरी दुनिया को पता है कि भारत और चीन दो सबसे बड़ी जनसंख्या यानी उपभोक्ता वाले देश हैं। यही दोनों देश दुनिया की फैक्ट्री भी हैं। चीन तो सबसे बड़ा उत्पादक देश है, जबकि भारत दुनिया की दूसरी फैक्ट्री बनने की राह पर है। इसका मतलब है कि यह दोनों देश न सिर्फ बड़े उत्पादक हैं, बल्कि सबसे बड़े उपभोक्ता वाले देश भी हैं। अगर रूस के साथ मिलकर ये तीनों देश अपनी मुद्रा में लेनदेन और कारोबार करते हैं तो निश्चित रूप से डॉलर को बड़ी चुनौती मिल सकती है।

तीनों देशों में कितना कारोबार

भारत, रूस और चीन का आपस में कुल व्यापार भी लगातार बढ़ता जा रहा है। वित्त वर्ष 2023-24 में रूस और भारत के बीच द्विपक्षीय कारोबार 65 अरब डॉलर से ज्यादा रहा था, जबकि भारत और चीन का कारोबार 130 अरब डॉलर से अधिक रहा है। इसी तरह, रूस और चीन का कारोबार भी 200 अरब डॉलर से ज्यादा ही रहा। इस तरह, अगर तीनों देशों के बीच कुल कारोबार को देखा जाए तो यह करीब 390 अरब डॉलर के आसपास रहा है। इसके 400 अरब डॉलर से भी ज्यादा पहुंचने का अनुमान है।

भारत का कुल कारोबार: पिछले वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का कुल अंतरराष्ट्रीय व्यापार करीब 1,830 अरब डॉलर (1.83 ट्रिलियन डॉलर के आसपास) रहा है। इसमें प्रोडक्ट का कारोबार करीब 1,300 अरब डॉलर और सेवाओं का आयात-निर्यात 500 अरब डॉलर से ज्यादा रहा है।

चीन का कुल कारोबार: चीन ने पिछले वित्त वर्ष 3.59 ट्रिलियन डॉलर का सामान दुनियाभर में निर्यात किया और 2.56 ट्रिलियन डॉलर का सामान मंगाया। इस तरह, सामान का कुल

अमेरिका की छवि को गटर में डाल रहे ट्रंप

अमेरिका के पूर्व सुरक्षा सलाहकार जैकब जेरेमिया सुलिवन ने अमेरिका की तुलना चीन से की। उन्होंने कहा कि आज विश्व चीन को एक जिम्मेदार देश के तौर पर देख रहा है। जबकि ट्रंप सरकार अमेरिका की छवि को गटर में मिला रही है, जिस पर कोई भी देश भरोसा नहीं करना चाहता है। सुलिवन ने चीन को अमेरिका का विकल्प बताया। उन्होंने कहा कि चीन कई देशों में लोकप्रियता के मामले में अमेरिका से आगे निकल गया है। एक साल पहले तक ऐसा नहीं था। अब कई देश कह रहे हैं कि ब्रांड अमेरिका खत्म हो चुका है और चीन एक जिम्मेदार खिलाड़ी की तरह नजर आ रहा है। सुलिवन ने भारत पर टैरिफ को लेकर ट्रंप सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि टैरिफ से वाशिंगटन और दिल्ली के बीच संबंध खराब हुए हैं। ट्रंप ने भारत को चीन से बातचीत करने के लिए मजबूर किया है। जबकि बाइडन सरकार भारत से रिश्ते मजबूत करने की कोशिश कर रही थी। ताकि चीन को काउंटर किया जा सके। सुलिवन ने अमेरिकी निवेश बैंक की रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि ट्रंप ने अपने निजी गुस्से के कारण भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाया है। क्योंकि भारत ने ट्रंप के भारत-पाकिस्तान में सीजफायर वाले बयान को गलत बताया था।

कारोबार 6.15 ट्रिलियन डॉलर रहा, जबकि सेवाओं का कारोबार मिला दें तो यह आंकड़ा 7.56 ट्रिलियन डॉलर पहुंच जाता है।

रूस का कुल कारोबार: पिछले वित्त वर्ष में रूस ने दुनियाभर को 424 अरब डॉलर का सामान बेचा और दुनिया से 304 अरब डॉलर का सामान खरीदा। यानी कुल कारोबार रहा 728 अरब डॉलर का। इसमें सेवाओं का कारोबार जोड़ दिया जाए तो यह 117 अरब डॉलर और बढ़कर करीब 865 अरब डॉलर पहुंच जाएगा। इस तरह रूस, चीन और भारत का कुल अंतरराष्ट्रीय कारोबार करीब 10 ट्रिलियन डॉलर से भी ज्यादा का रहा है।

अमेरिका का ग्लोबल कारोबार

साल 2024 में अमेरिका का कुल कारोबार करीब 7 ट्रिलियन डॉलर का रहा है। इसमें प्रोडक्ट के निर्यात का हिस्सा 2 ट्रिलियन डॉलर और आयात का हिस्सा 3.37 ट्रिलियन डॉलर रहा। इसका मतलब है माल का कुल कारोबार 5.43 ट्रिलियन डॉलर रहा, जबकि सर्विस का निर्यात 928 अरब डॉलर और आयात 700 अरब डॉलर रहा। सर्विस का कुल कारोबार 1.63 ट्रिलियन डॉलर रहा है और कुल कारोबार 7 ट्रिलियन डॉलर के आसपास पहुंच गया है। अगर तीनों ही देश अकेले-अकेले अमेरिका का मुकाबला करेंगे तो यह मुश्किल होगा, क्योंकि उसका कुल कारोबार चीन से भी ज्यादा है। लेकिन, अगर चीन-भारत और रूस मिलकर अमेरिका के सामने खड़े होते हैं तो यह आंकड़ा अमेरिका के कुल कारोबार से कहीं ज्यादा बैठता है। आंकड़े साफ बताते हैं कि अगर तीनों ही देश मिलकर अमेरिकी डॉलर के सामने खड़े होते हैं तो निश्चित रूप से इसका मुकाबला ग्लोबल मार्केट में कर सकते हैं। यह इसीलिए नहीं हो पाया, क्योंकि भारत उनकी मनमर्जी वाले समझौते पर हस्ताक्षर करने को तैयार नहीं था। इसी से चिढ़े ट्रंप ने एक तो यह राग अलापना शुरू किया कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्षविराम कराया और दूसरे, इस हास्यास्पद आरोप के साथ सामने आ गए कि यूक्रेन के खिलाफ रूस के युद्ध के लिए भारत जिम्मेदार है। ट्रंप ने उस चीन को बख्श दिया है, जिसके खिलाफ वह गर्जन-तर्जन करते रहते हैं और जो भारत के मुकाबले रूस से कहीं अधिक तेल खरीदता है। चूंकि ट्रंप में इतना साहस नहीं कि वे चीन पर भारत जितना टैरिफ लगा सकें, इसलिए उनके सहयोगी तरह-तरह के कुतर्क देने में लगे हुए हैं। इसके कारण उनकी जगहंसाई ही हो रही है, पर शायद उन्हें इसकी परवाह नहीं।

स्वदेशी पर फोकस

जो भी हो, भारत को जहां आत्मनिर्भरता के अपने प्रयासों को गति देनी होगी, वहीं स्वदेशी के मंत्र को भी प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाने के साथ उनकी निरंतर समीक्षा भी करनी होगी। यह इसलिए करनी होगी, क्योंकि स्वदेशी अपनाने और आत्मनिर्भर बनने की बातें कोविड महामारी के बाद से ही हो रही हैं और सब जानते हैं कि उनके अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं किए जा सके। कम से कम अब तो वांछित नतीजे हासिल करने के लिए ठोस उपाय किए ही जाने चाहिए। ये उपाय तब सफल होंगे, जब हमारे कारोबारी ट्रंप की ओर से पेश की गई टैरिफ की चुनौती का सामना करने के लिए अपनी उत्पादकता एवं गुणवत्ता को बेहतर बनाएंगे। वे सरकार से सहायता की अपेक्षा तो कर सकते हैं, लेकिन उन्हें अपने हिस्से की जिम्मेदारी खुद उठानी होगी। लड़ाई केवल कारोबार की नहीं, आत्मसम्मान की भी है। सरकार, कारोबार जगत के साथ देश की आम जनता को इसके लिए भी तैयार रहना होगा कि ट्रंप का भारत विरोधी रवैया लंबे समय तक कायम रह सकता है।

अमेरिका नहीं चाहता भारत का उभार

भारत द्वारा 1998 में पोखरण परमाणु परीक्षणों के बाद अमेरिका द्वारा उस पर लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों का कोई प्रभाव न होते देख और चीन एवं इस्लामिक कट्टरपंथ के उभार से चिंतित अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने यह निर्णय लिया कि भारत से कटकर एशिया की भूराजनीति चलाना संभव नहीं है। हालांकि उस दौर में दोनों देशों के संबंधों में इतनी कटुता आ चुकी थी कि एकदम से सबकुछ सामान्य हो पाना संभव नहीं था। इसलिए भारत और अमेरिका कैसे एशिया की अगली सदी को मिलकर गढ़ सकते हैं, इस पर चर्चा के लिए अमेरिकी उप विदेश मंत्री स्ट्रोब टालबोट और भारतीय विदेश मंत्री जसवंत सिंह के बीच 11 दौर की गुप्त वार्ता विश्व में अलग-अलग स्थानों पर हुई। इन वार्ताओं से अमेरिका में यह सहमति बनी कि भारत के सामरिक उदय को सुनिश्चित किया जाना पूरे एशिया और समूचे विश्व की सुरक्षा और स्थिरता के लिए आवश्यक है। यह कुछ-कुछ वैसा ही था, जैसा निक्सन और किसिंजर द्वारा 1970 के दशक में यह तय करना कि अमेरिका सोवियत संघ को कमजोर करने के लिए चीन का उदय सुनिश्चित करेगा। टालबोट-जसवंत वार्ता की परिणति ही भारत के ऊपर से अमेरिकी प्रतिबंध हटाए जाने, कारगिल युद्ध के समय राष्ट्रपति क्लिंटन के भारत की ओर झुकाव के रूप में दिखाई दी। भारत के उदय को सुनिश्चित करने की इस नीति के पक्षधर

डेमोक्रेट और रिपब्लिकन दोनों ही बने। क्लिंटन के बाद रिपब्लिकन राष्ट्रपति जार्ज बुश ने पहले प्रधानमंत्री वाजपेयी और बाद में मनमोहन सिंह के साथ मिलकर भारत-अमेरिका परमाणु समझौते की रूपरेखा तैयार की और उसे मूर्त रूप भी दिया गया। इसके जरिये भारत को परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर किए बिना भी एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति के तौर पर स्वीकार कर लिया गया और अमेरिका ने चीन के विरोध को दरकिनार करते हुए भारत को परमाणु आपूर्तिकर्ता संगठन का सदस्य भी बनवाया।

द्विपक्षीय संबंधों में प्रगाढ़ता धीरे-धीरे आगे बढ़ती रही। दोनों देशों के बीच 2005 में बनी रणनीतिक साझेदारी को 2020 में राष्ट्रपति ट्रंप के पहले कार्यकाल में समग्र वैश्विक और सामरिक साझेदारी का रूप दिया गया। भारत ने अमेरिका के साथ कई अहम रक्षा समझौते भी किए। यह सिलसिला एक बड़ी हद तक ट्रंप के पहले कार्यकाल और बाइडन के दौर तक चलता रहा, लेकिन ट्रंप के दूसरे कार्यकाल विशेषकर ऑपरेशन सिंदूर के बाद के परिदृश्य में अमेरिकी रवैया बदल गया। कुछ लोग इसे भारत-पाकिस्तान के बीच संघर्षविराम के ट्रंप के दावे को भारत द्वारा बार-बार खारिज करने से भी जोड़कर देख रहे हैं। यह पूरी तरह सही नहीं है।

अमेरिका में एक तबका भारत से कुछ अनावश्यक उम्मीदें रखता आया है। ऐसी ही एक उम्मीद ताइवान से जुड़ी है। वहां एक वर्ग चाहता है कि ताइवान पर संभावित चीनी हमले की स्थिति में भारत उसके मुकाबले में सहायक बने, मगर भारत यूक्रेन की तरह अमेरिकी सामरिक हितों को साधने के लिए कोई भाड़े पर लड़ने वाला देश नहीं बन सकता। यह बात वाशिंगटन को पच नहीं रही। यह उसकी समझ से बाहर है कि अमेरिका संग कई रक्षा समझौतों के बाद भी कोई देश अपना सामरिक चुनाव खुद कैसे कर सकता है? भारत के मामले में ऐसा होते देख अमेरिका की सामरिक बिरादरी कुंठा और गुस्से से भरी पड़ी है।

भारतीय मामलों पर वाशिंगटन में एक बड़ी आवाज माने जाने वाले एश्ले टैलिस ने 2023 में ही एक लेख में लिखा था कि अमेरिका ने भारत पर गलत दांव लगाया है। एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि अमेरिका चीन के साथ युद्ध की स्थिति में भारत की तटस्थता बर्दाश्त नहीं कर सकता। टैलिस वाशिंगटन में भारत को लेकर पनप रही खिसियाहट को ही दर्शा रहे थे। यह वही समय था जब यूक्रेन युद्ध फंस चुका था। अमेरिका रूस से सीधा टकराव नहीं मोल लेना चाहता था। चीन को वह दबाव में ले नहीं सकता था, इसलिए भारत को रूसी तेल खरीदने के आरोप में दबाव में लेने का फैसला लिया गया। तब से ही यही नीति जारी है। बस बाइडन और ट्रंप के तरीके अलग हैं। बाइडन प्रशासन भारत को दबाव में लेने के लिए खालिस्तान कार्ड खेलता रहा। कनाडा की ट्रूडो सरकार के जरिये भारतीय नेतृत्व पर खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या के आरोप लगाए गए। इतने से बात नहीं बनी तो गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश रचने के आरोप भी मढ़े गए।

खत्म हो सकती है डॉलर की बादशाहत

पिछले कई दशकों से अमेरिकी डॉलर दुनिया पर राज कर रहा है। यूं कहें कि इसका एकाधिकार दुनिया के व्यापार में है, तो इसमें कोई बुराई नहीं होगी। लेकिन जिस तरह से अमेरिका ने रूस की संपत्तियां जब्त कीं और कई देशों पर प्रतिबंध लगाए, इससे विकल्पों पर विचार होना शुरू हो गया। कई देश धीरे-धीरे अपनी करेंसी में व्यापार करने लगे हैं, हालांकि इसकी मात्रा अभी बहुत सीमित है। पिछले काफी दिनों से चर्चा है कि ब्रिक्स समूह अपनी करेंसी लॉन्च कर सकता है और अब सबकी निगाहें आगामी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन पर टिकी हैं। उम्मीद की जा रही है कि इसमें ब्रिक्स करेंसी को लॉन्च किया जा सकता है। अगर यह करेंसी लॉन्च होती है, तो जाहिर है इससे डॉलर पर असर पड़ेगा और दुनिया को व्यापार करने का एक नया रास्ता भी मिलेगा। अमेरिकी डॉलर की बादशाहत कई वजहों से कायम है। तेल का कारोबार लगभग 95 प्रतिशत से अधिक डॉलर में ही होता है। अगर यह करेंसी बनाई जाती है, तो रूस, चीन और भारत समेत इसमें शामिल कई देशों के लिए यह फायदे का सौदा होगा। ब्रिक्स देशों के अपनी करेंसी बनाने के पीछे कई कारण हैं। हाल की चुनौतियां और अमेरिका की आक्रामक विदेश नीतियों ने ब्रिक्स देशों को इसके विकल्प तलाशने पर मजबूर कर दिया है। यूक्रेन युद्ध के बाद जिस तरह से रूस को डॉलर में कारोबार करने में परेशानी आई, वहीं हाल ही में इस समूह में शामिल ईरान पिछले कई सालों से अमेरिकी प्रतिबंध झेल रहा है। ब्रिक्स करेंसी कब जारी की जाएगी और इसका मूल्य किस आधार पर तय होगा, इसको लेकर अभी कोई निश्चित तारीख का ऐलान नहीं हुआ है।

ट्रंप का पाकिस्तान प्रेम

जब ट्रंप दोबारा सत्ता में वापस आए तो उन्होंने पाकिस्तान के साथ नजदीकियां बढ़ानी प्रारंभ कर दी थीं। जब पहलगाम हमला हुआ, तब उनके प्रतिनिधि पाकिस्तान के साथ क्रिप्टोकरेंसी डील पर हस्ताक्षर करने की तैयारी कर रहे थे। ऐसे में यह सोचना एक भूल है कि भारत-पाकिस्तान सीजफायर का श्रेय न मिलने से क्रुद्ध ट्रंप ने भारत पर टैरिफ लगाए हैं। वाशिंगटन में अब यह सोच बन चुकी है कि भारत के महाशक्ति के रूप में उदय का समर्थन करने से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि वह अमेरिका के इशारों पर नाचने वाला नहीं है। अमेरिका को लगता है कि जब चीन से निपटना ही उसे भारी पड़ रहा है तो सामरिक रूप से स्वायत्त महाशक्ति के रूप में भारत का उदय तो भविष्य में उसके वैश्विक प्रभुत्व के लिए चुनौती बढ़ाने का ही काम करेगा। अमेरिका भारत को अगला चीन बनते नहीं देखना चाहेगा।

अमेरिकी अर्थशास्त्री जैफरी सैक्स कहते हैं कि भारत को सफल होते देख अमेरिका उसका विरोध करेगा, क्योंकि यह उसके स्वभाव में है। इसी कारण पहले अमेरिका रूस का विरोध कम्युनिज्म के नाम पर करता था। अब कम्युनिज्म के पतन के बाद भी उसका विरोध जारी है, क्योंकि अभी भी रूस एक बड़ी भूराजनीतिक शक्ति है और वह कभी अमेरिकी कठपुतली नहीं बनेगा। भारत के चमत्कारिक आर्थिक विकास के चलते यही अमेरिकी रवैया

अब भारत के प्रति दिखने लगा है। ऐसे में यदि भारत को आर्थिक और सैन्य महाशक्ति बनने की अपनी यात्रा जारी रखनी है तो हमारे उद्योगपतियों, शिक्षाविदों, अनुसंधानकर्ताओं, पेशेवरों और छात्रों को चौगुनी शक्ति से काम करना होगा।

ट्रंप के टैरिफ का यूएस में विरोध

टैरिफ मामले में फेडरल कोर्ट के फैसले के बाद अब सीनेट में भी ट्रंप की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। अमेरिकी संसद में विदेश मामलों की कमेटी ट्रंप के टैरिफ पर एक्शन ले सकती है। डेमोक्रेट सांसद ग्रेगरी मीक्स ने हाउस ऑफ रिप्रजेंटेटिव्स के स्पीकर माइक जॉनसन से टैरिफ खत्म करने के प्रस्ताव पर विचार करने की अपील की है। ग्रेगरी ने कहा कि ट्रायल और अपीलीय दोनों अदालतों ने ट्रंप को टैरिफ को अवैध बताया है। इसलिए स्पीकर जॉनसन को ट्रंप की अराजकता को छुपाना बंद करना चाहिए और टैरिफ खत्म करने के लिए मेरे प्रस्तावों को सदन में रखना चाहिए। भारत पर टैरिफ लगाने के फैसले के खिलाफ अमेरिकी व्यवस्था में लोग एकजुट हो रहे हैं। इन्हें डर है कि कहीं टैरिफ की वजह से भारत से दोस्ती न टूट जाए। दरअसल, फेडरल कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि ट्रंप को कानूनी तौर पर नेशनल इमरजेंसी घोषित करने और दुनिया के लगभग हर देश पर आयात कर लगाने का अधिकार नहीं है। कोर्ट ने कहा कि ट्रंप के ज्यादातर ग्लोबल टैरिफ गैरकानूनी हैं। हालांकि, कोर्ट ने यह भी कहा है कि ये टैरिफ 14 अक्टूबर तक लागू रहेंगे, ताकि ट्रंप प्रशासन को सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का समय मिल सके।

अदालत के फैसले के बाद, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि देशों पर लगाए गए सभी टैरिफ लागू रहेंगे। उन्होंने कोर्ट के फैसले को एकतरफा और गलत बताया। ट्रंप ने कहा, वे जानते हैं कि अंत में अमेरिका की जीत होगी। अगर ये टैरिफ कभी हटा दिए गए, तो यह देश के लिए पूरी तरह से विनाशकारी होगा। यह हमें आर्थिक रूप से कमजोर बना देगा, और हमें मजबूत होना होगा। 2 अप्रैल को ट्रंप ने अमेरिका के साथ व्यापार घाटा झेल रहे 60 देशों पर नए टैरिफ लगाने की घोषणा की थी। ट्रंप ने इस दिन को लिबरेशन डे नाम दिया। भारतीय सामानों पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाया गया है। रूसी कच्चा तेल खरीदने पर 25 प्रतिशत पेनाल्टी भी लगाई गई। 27 अगस्त से भारतीय सामानों पर कुल 50 प्रतिशत टैरिफ लागू हो गया है।

ट्रंप ने पिछले साल राष्ट्रपति चुनाव के दौरान वादा किया था कि वह चुनाव जीतने के एक दिन के भीतर रूस-यूक्रेन युद्ध खत्म करा देंगे। लेकिन अभी तक ऐसा नहीं कर पाए। अब अमेरिका जंग खत्म न होने का ठीकरा भारत पर फोड़ रहा है। अमेरिका ने भारत पर रूसी तेल खरीद से मुनाफा कमाने का आरोप लगाया और 27 अगस्त से भारतीय सामानों पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगा दिया। रूस-यूक्रेन के बीच फरवरी 2022 से जंग जारी है। जंग में 4 लाख से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। रूस में सैनिकों समेत 2.5 लाख लोगों की मौत हुई है। वहीं यूक्रेन में मौतों का आंकड़ा 1 लाख से ज्यादा है। आखिर ट्रंप अपनी नाकामी का ठीकरा भारत पर क्यों फोड़ रहे हैं। यूरोप यूक्रेन के साथ मजबूती से खड़ा है। अमेरिका चाहता है कि यूरोपीय देश भी भारत पर टैरिफ लगाएं, लेकिन यूरोपियन यूनियन ने इस मामले पर चुप्पी साध रखी है। अब ट्रंप के सलाहकार युद्ध में मोदी की भूमिका की बात कहकर भारत को निशाना बना रहे हैं।

ट्रंप ने 15 अगस्त को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन से अलास्का में मुलाकात की थी। दोनों नेता किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाए। इसके बाद 18 अगस्त को व्हाइट हाउस में यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की और यूरोपीय देशों के साथ वार्ता की। ये मीटिंग्स भी बेनतीजा रहीं। 29 अगस्त को ट्रंप के ट्रेड एडवाइजर पीटर नवारो ने कहा कि भारत पर टैरिफ लगाकर पुतिन की वॉर मशीन को मिलने वाली वित्तीय मदद रोकी गई है। नवारो ने एक दिन पहले ही रूस-यूक्रेन संघर्ष को ही मोदी का युद्ध कहा था। नवारो ने आरोप लगाया था कि रूस से तेल खरीदकर भारत इस जंग को हवा दे रहा है।

ट्रंप लागातार बाइडन पर जंग शुरू करवाने का आरोप लगाते रहे हैं। उनका कहना है कि वे राष्ट्रपति होते तो युद्ध शुरू ही नहीं होता। ट्रंप यह आरोप लगाते रहे और शांति के नतीजे पर पहुंचने की बात करते रहे। हालांकि रूस-यूक्रेन के बीच जल्द ही शांति समझौता होता नहीं दिख रहा। ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने कहा कि इस साल समझौता होना मुश्किल है। समझौता फेल होने से पहले ट्रंप की टीम भारत को घेरने में जुट गई है। ट्रंप की धमकियों का भी रूस और यूक्रेन पर कोई असर नहीं पड़ा है। ट्रंप ने 22 अगस्त को रूस-यूक्रेन के बीच शांति वार्ता के लिए 2 हफ्ते का समय दिया था। ट्रंप ने कहा, 2 हफ्ते के भीतर हमें इसकी जानकारी मिल जाएगी, ऐसा नहीं हुआ तो हमें शायद कोई अलग रास्ता अपनाना होगा। ऐसा पहली बार नहीं है, जब ट्रंप ने यूक्रेन मुद्दे पर विचार-विमर्श के लिए 2 हफ्ते की समयसीमा तय की थी, वे पहले भी ऐसे मुद्दों पर 2 हफ्ते की टाइमलाइन दे चुके हैं। उन्होंने मई में कहा था कि अगर पुतिन शांति समझौते को गंभीरता से नहीं लेते, तो अलग तरीके से जवाब दिया जाएगा।

भारत के जरिए रूस पर दबाव बनाने की कोशिश

अमेरिका सीधे तौर पर रूस पर दबाव नहीं बना पा रहा है। भारत की एंट्री कराकर रूस पर दबाव बनाने की कोशिश है। टैरिफ में सफल नहीं हो पाए। हालांकि ट्रंप का ये दांव भी उल्टा पड़ता नजर आ रहा है। भारत ट्रंप के टैरिफ का मुकाबला करने के लिए 40 देशों में संपर्क साध रहा है ताकि भारतीय सामानों की ग्लोबल मार्केट में पहुंच बढ़ सके। अमेरिकी अर्थशास्त्री रिचर्ड वोल्फ ने कहा कि ट्रंप भारत पर टैरिफ लगाकर ऐसा व्यवहार कर रहा है जैसे वह सख्त आदमी हों, लेकिन वास्तव में वह अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। ऐसा करके ट्रंप ब्रिक्स को पश्चिम का आर्थिक विकल्प बनाने पर जोर दे रहे हैं। ट्रंप के एडवाजर नवारो ने आरोप लगाया कि यूक्रेन जंग से पहले भारत 1 प्रतिशत से भी कम रूसी तेल इंपोर्ट करता था, जो कि अब 30 प्रतिशत से भी ज्यादा यानी 15 लाख बैरल प्रतिदिन है। इस इजाफे की वजह घरेलू मांग नहीं है। इससे भारी मुनाफा कमाया जा रहा है। हालांकि भारत का कहना है कि उसने रूसी तेल की खरीद से ग्लोबल मार्केट में तेल की कीमतें स्थिर रखी हैं।

भ्रष्टाचार रुकेगा तो बढ़ेगा भारत

गिरफ्तारी के बाद पद छोड़ने वाली व्यवस्था पर इतना हंगामा क्यों?

गंभीर आपराधिक आरोपों में गिरफ्तार या हिरासत में लिए जाने पर प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रियों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री या मंत्रियों को पद से हटाने के प्रविधान वाले विधेयकों पर लोकसभा में विपक्ष का जरूरत से ज्यादा हंगामा समझ नहीं आया। यह अच्छा हुआ कि गृहमंत्री अमित शाह ने अपनी ओर से इन विधेयकों को संसद की संयुक्त समिति को भेजने का प्रस्ताव रखा, जिसे लोकसभा अध्यक्ष ने स्वीकार भी कर लिया। कम से कम अब तो विपक्ष को विरोध के सुर थामकर इस पर विचार करना चाहिए कि आखिर ऐसी कोई व्यवस्था क्यों नहीं बननी चाहिए, जिससे उच्च पदों पर बैठे लोगों की गंभीर मामलों में गिरफ्तारी अथवा उन्हें हिरासत में लिए जाने पर उनके लिए पद छोड़ना आवश्यक हो जाए? जो पहल की जा रही है, उसमें यह कहा गया है कि केंद्र सरकार अथवा केंद्रशासित प्रदेशों में महत्वपूर्ण पदों पर आसीन लोगों को तब अपना पद छोड़ना होगा, जब उन्हें किसी संगीन मामले में गिरफ्तार किया जाता है अथवा हिरासत में लिया जाता है। यह रियायत दी गई है कि ऐसी स्थिति में इन व्यक्तियों को 30 दिनों के अंदर इस्तीफा देना होगा। इस समयसीमा के अंदर इस्तीफा न देने पर उन्हें स्वतः पदमुक्त माना जाएगा। आखिर ऐसी किसी व्यवस्था में समस्या क्या है?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से 103 मिनट के अपने लंबे संबोधन में देश-दुनिया का ध्यान खींचने वाली जो महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं, उन पर अब तक चर्चा हो रही है। चर्चा इसलिए हो रही है, क्योंकि कुछ घोषणाएं देश का कायाकल्प करने वाली हैं। जीएसटी में व्यापक बदलाव समेत नए दौर के आर्थिक सुधार लाने, रोजगार की नई योजना शुरू करने, डेमोग्राफी मिशन की तैयारी से लेकर रक्षा से जुड़ी सुदर्शन चक्र और ऊर्जा सुरक्षा संबंधी समुद्र मंथन जैसी योजनाओं की घोषणाएं ऐसी हैं कि यदि उन पर आधा भी अमल हो सके तो देश का भाग्योदय हो सकता है।

प्रधानमंत्री मोदी ने जबसे कार्यभार संभाला है, तब से ही अर्थात् 2014 से लाल किले से दिए गए उनके भाषणों की कुछ बातों का उल्लेख रह-रह कर होता है। ऐसी कुछ घोषणाओं ने तो प्रभावी योजनाओं का रूप भी लिया, जैसे स्वच्छ भारत अभियान, शौचालय निर्माण, आयुष्मान भारत योजना, कृषि सम्मान निधि आदि। प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार के खिलाफ भी कुछ न कुछ कहते रहे हैं। 2024 में उन्होंने दो टूक कहा था, भ्रष्टाचार के खिलाफ मेरी लड़ाई ईमानदारी के साथ जारी रहेगी और भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई जरूर होगी। मैं उनके लिए भय का वातावरण पैदा करना चाहता हूं। देश के सामान्य नागरिकों को लूटने की जो परंपरा बनी है, उसे मुझे रोकना है। इसके अलावा वे प्रधानमंत्री बनने के पहले यह भी कह चुके हैं कि न खाऊंगा और न खाने दूंगा। क्या यह कहा जा सकता है कि भ्रष्ट तत्वों के लिए भय के वातावरण का निर्माण हो सका है? इसका सीधा जवाब है-नहीं। केवल यह कहना ही सही नहीं कि सरकारी क्षेत्र में जहां किसी तरह का निर्माण, वहां भ्रष्टाचार। सच यह भी है कि जहां भी किसी तरह का सरकारी दखल, वहां पैसे लेने-देने का चलन। यदि सरकारी तंत्र को कोई अनुमति-स्वीकृति देनी है या किसी तरह का प्रमाणन या नवीनीकरण करना है तो वह बिना जेब ढीली किए होना मुश्किल है।

कई बार लोगों के जायज काम भी कुछ दिए बिना नहीं होते और सब जानते हैं कि नाजायज काम होते रहते हैं। सरकारी तंत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार बढ़ते-बढ़ते इतना व्यापक हो गया है कि वह निजी क्षेत्र में भी घुस गया है। सरकारी क्षेत्र में मलाईदार पदों पर नियुक्तियों, कोई काम या ठेका देने अथवा खरीद में जैसा भ्रष्टाचार है, वैसा ही कुछ-कुछ निजी क्षेत्र में भी है। कमीशनबाजी हर कहीं है। यह है तो दलाली और घूसखोरी ही, पर अब उसे सुविधा शुल्क भी कहते हैं। इसके आधार पर ऐसे निष्कर्ष पर भी नहीं पहुंचा जाए कि देश गड्ढे में जा रहा है अथवा सबके सब सरकारी अधिकारी-और कर्मचारी भ्रष्ट हैं। ऐसा नहीं है। भारत विरोधाभासों का देश है। अपने यहां कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी-कर्मचारी भी हैं और वे अपना काम सही तरीके से भी करते हैं। कुछ तो फोन पर भी जनता की शिकायत सुनकर उसका समाधान कर देते हैं, पर यह कहना बहुत कठिन है नौकरशाही में उनकी ही अधिकता है। ऐसा होता तो आज परिदृश्य कुछ और होता। इसके बाद भी यह सही से काम करने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों की ही कर्तव्यनिष्ठा का नतीजा है कि कुछ सरकारी विभागों का कामकाज सुधरा और सुगम हुआ है। इसका लाभ भी मिला है। यदि उदाहरण देना हो तो पासपोर्ट कार्यालय, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) आदि का दिया जा सकता है। राज्य सरकारों के भी कुछ विभागों के कामकाज में सुधार के साथ पारदर्शिता बढ़ी है। यदि कहीं-कहीं सरकारी काम में लगने वाला समय कम हुआ है, कुछ सरकारी दफ्तरों में कतारें कम या खत्म हुई हैं और समय के साथ औसत लोगों की आय बढ़ी है एवं देश पांचवीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है तो इसका मतलब है कि कुछ अच्छा हुआ है और हो रहा है, लेकिन क्या हम विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में सही गति और दिशा में बढ़ रहे हैं?

हम विकसित देश के लक्ष्य को पाने की सही गति और दिशा पकड़ सकें, इसके लिए अभी बहुत कुछ करना है-केंद्र सरकार को भी, राज्य सरकारों को भी और सबसे बड़ी बात उनकी नौकरशाहों को भी। भ्रष्ट नेताओं और नौकरशाहों के गठजोड़ को प्राथमिकता के आधार पर खत्म करना होगा। यह गठजोड़ स्थानीय निकायों के स्तर पर ही शुरू हो जाता है। यदि सरकारी वेतन बढ़ रहे हैं तो सरकारी तंत्र में भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्ती भी बढ़ानी होगी। भ्रष्ट तत्वों के मन में सचमुच दंडित होने का भय होना चाहिए, भले ही वे कितने ही उच्च पद पर हों। भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्ती दिखाने की बातें तो होती रहती हैं, लेकिन नतीजा वैसा नहीं, जैसा दिखना चाहिए। अपने देश में भ्रष्ट सरकारी अफसरों-कर्मियों को दंडित करना अब भी कठिन है। शीर्ष स्तर के भ्रष्ट अफसरों को तो दंड देना कुछ ज्यादा ही कठिन है। कई बार नेताओं से भी अधिक। यह ठीक है कि उन्हें एक हद तक संरक्षण मिलना चाहिए, ताकि वे बिना किसी भय और दबाव के फैसले ले सकें, लेकिन इस कवच के दायरे में भ्रष्ट तत्व क्यों आने चाहिए? निसंदेह कोई भी देश और यहां तक कि लाखों की आबादी वाले देश भी भ्रष्टाचार से पूरी तरह मुक्त नहीं, लेकिन वे भ्रष्ट तौर-तरीकों पर प्रभावी रोक लगा सकते हैं। सबसे अधिक आबादी वाला भारत भी ऐसा कर सकता है। जब भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी, तभी भारत तेजी से आगे बढ़ेगा और विकसित देश के सपने को साकार करेगा।

● रजनीकांत पारे

बिहार में आर-पार

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले राज्य का चुनावी माहौल गरमा गया है। संसद से लेकर सड़क तक घमासान मचा हुआ है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने जनता को साधने के लिए वोटर अधिकार यात्रा निकाली है। इस यात्रा में गठबंधन के नेताओं ने लोगों से सीधे संवाद किया और अपने वादों की लिस्ट पर्चे के जरिए घर-घर तक पहुंचाया। वहीं सत्तारूढ़ पार्टी और उसके सहयोगी दल भी मैदानी मोर्चे पर सक्रिय हो गए हैं।

बिहार विधानसभा चुनाव से करीब तीन महीने पहले लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने वोटर अधिकार यात्रा निकालकर संदेश दे दिया है कि हम चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार हैं। राहुल गांधी ने बिहार के 25 जिलों को 15 दिन में कवर किया और, इस दौरान तेजस्वी यादव उनके साथ रहे। कोशिश तो कांग्रेस की तरफ से सहयोगी दलों को साथ रखने की ही लग रही है, लेकिन ये कोशिश कब तक और कहां तक रंग लाती रहेगी, ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए ये सवाल भी अभी तक खत्म नहीं हो सका है।

दरअसल, यह महज संयोग हो सकता है। बिहार में विधानसभा चुनावों से तीन-चार महीने पहले चुनाव आयोग ने अचानक जून के आखिरी हफ्ते में विशेष वोटर पहचान महीने भर में पूरा करने की कवायद शुरू की, तो साथ ही संगीन अपराधों की भी झड़ी लग गई। ऐसी कि जितना हल्ला चुनाव आयोग की भाषा में विशेष सघन पुनर्रीक्षण (एसआईआर) से उठा, उससे कहीं ज्यादा हाहाकार बेखौफ अपराधियों की हत्या, लूट, फिरौती, वसूली, बलात्कार की वारदातों के सिलसिले से मचा। इस सिलसिले के दरवाजे राज्य के तकरीबन सभी 38 जिलों में खुलते गए। राजधानी पटना में तो बेहद सुरक्षित बताए या आंके जाने वाले वीवीआईपी इलाके भी, एक नहीं कई-कई वारदातों से अछूते नहीं रहे। जुलाई में ही हत्या की तकरीबन 80 वारदातें हो चुकी हैं। इससे विपक्ष तो विपक्ष, सत्तारूढ़ एनडीए के सहयोगी, लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास पासवान) के सर्वेसर्वा तथा केंद्र सरकार में मंत्री चिराग पासवान भी कह उठे, यह बेहद अफसोसजनक है। ऐसी सरकार के साथ होने पर तो शर्म आती है।

कभी लालू प्रसाद और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दोनों के ही करीबी सहयोगी रहे प्रेम कुमार मणि कहते हैं, रोजाना गोलीबारी की घटनाएं फिर आम हो गई हैं। यह बिल्कुल लालू के जमाने जैसा है। यह जंगल राज की वापसी है। इसी शर्मनाक हालात, वोटरों के नाम कटने के डर और किसी तरह सरकारी कागजात हासिल करने की अफरा-तफरी के साथ नए सियासी समीकरणों के उभार से बिहार शायद 2025 में सबसे पेचीदे विधानसभा चुनाव के दौर में है, जो अक्टूबर-नवंबर में होने तय हैं।

हालांकि सत्तारूढ़ों की राय बिल्कुल अलहदा है। नीतीश मौन हैं। लेकिन 17 जुलाई को पटना के बेहद चर्चित और महंगे पारस अस्पताल में सरेआम पिस्तौल लहराते एक सजायाफ्ता मरीज को गोली मारने की घटना के बाद जनता दल-यूनाइटेड या जदयू के शीर्ष नेताओं में एक, केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह ने मीडिया बाइट दी, ई कोई क्राइम है जी, दो मिले मार दिया तो यह आपसी हुआ न। उसी दिन राज्य के एडीसी (पुलिस हेडक्वार्टर) कुंदन कृष्णन बोले, गर्मी के मई-जून और बरसात में जुलाई वगैरह के महीनों में लोग खेती-किसानी से खाली हो जाते हैं, तो क्राइम हमेशा बढ़ ही जाता है। इस बार चुनाव नजदीक है, तो ज्यादा हल्ला हो रहा है। अलबत्ता भाजपा नेता, उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा इतना जरूर कहते हैं कि हालात चिंताजनक हैं। लेकिन वे यह भी कहते हैं, यह जंगल राज जैसा नहीं है। अपराध राजद के दौर में संगठित और सरकार प्रायोजित था। अब ऐसा नहीं है। अब पुलिस फौरन सक्रिय होती है।

सिर्फ अपराधियों की मोटरसाइकिल दौड़ाते, पिस्तौल लहराते तस्वीरें ही दहशत पैदा नहीं कर रहीं, बल्कि सामाजिक तनाव और महिलाओं के खिलाफ बलात्कार, हत्या, कुछ मामलों में जिंदा जला देने की वारदातें भी रफ्तार पकड़ती दिख रही हैं। आसन्न चुनावों में एनडीए और राजद के तेजस्वी यादव की अगुवाई वाले महागठबंधन या इंडिया ब्लॉक के बाद तीसरा कोण बनाने में जुटे जनसुराज पार्टी के प्रशांत किशोर कहते हैं, यह जंगल राज नहीं तो और क्या है। सरकार का इकबाल लुट गया है। वे यह भी कहते हैं कि एनडीए के इशारे पर पूरी सरकारी मशीनरी नई वोटर लिस्ट तैयार करने में झोंक दी गई है। उनकी बात में एक हद तक दम हो सकता है कि चुनाव आयोग की अधिसूचना के बाद से महीने भर में वोटरों के नए सिरे से नाम भरने में समूची सरकारी मशीनरी दिन-रात जुटी रही,

प्रभावी होंगे नए उभरते मुद्दे

अपराध और वोटर लिस्ट के मसलों के अलावा महंगाई, बेरोजगारी और पलायन के मुद्दे बड़े होकर उभरते नजर आ रहे हैं। ये मुद्दे नए हल्ले में भले ढंक गए हों, मगर प्रभावी हो सकते हैं। इसमें परीक्षा-पत्र लीक के भी मामले युवाओं के रोष का कारण बने हुए हैं। इस बीच महागठबंधन ने नौकरी देने, पेपर लीक की जांच और दोषियों को दंडित करने, पेंशन 1,500 रुपए तक बढ़ाने और 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने का वादा किया, तो सरकार ने भी इससे मिलते-जुलते ऐलान कर डाले। पेंशन 400 रुपए से 1,100 रुपए की गई, 125 यूनिट तक बिजली मुफ्त की गई, नौजवानों की समस्या के लिए युवा आयोग के गठन वगैरह का ऐलान किया गया। लेकिन बड़े सवाल ज्यों के त्यों खड़े हैं। बिहार मानव विकास पैमाने पर देश में सबसे निचले पायदान पर खड़ा है। विकास के सबसे बड़े कारक शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण के मामले में बुरी स्थितियां और निवेश में कमी उसे गरीबी, पलायन की ओर धकेल रही हैं। इसमें सरकार की बजटीय प्राथमिकताएं बरसों से बाधा रही हैं। बहरहाल, इन सभी मुद्दों और अराजकता की धारणा चुनाव आयोग की कवायद से और गहरी हो गई है। जो भी हो माहौल बेहद पेचीदा और आशंकाओं से भरा हुआ है। देखा जाए आगे क्या नजारा उभरता है।

अपराध के आंकड़े बढ़ाएंगे परेशानी

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के 2022 के आंकड़े बताते हैं कि उस वर्ष, बिहार में अपराध में 23 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जो देश में सबसे अधिक थी। 2,930 हत्याओं के साथ, उप्र के बाद बिहार दूसरे स्थान पर था। अपहरण के 11,822 मामलों के साथ यह तीसरे स्थान पर था। 2017 और 2021 के बीच, राज्य में 14,800 से ज्यादा हत्या की वारदातें दर्ज की गईं, यानी औसतन 2,800 से 3,150 ऐसी घटनाएं प्रतिवर्ष हुईं। बिहार के पूर्व डीजीपी अभयानंद को नीतीश कुमार की पिछली सरकारों में अपराध नियंत्रण में अहम माना जाता था। वे एडीजी (मुख्यालय) के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान अपने स्पीडी ट्रायल की पहल को याद करते हैं। अभयानंद कहते हैं, हमने फौरन सुनवाई की व्यवस्था की थी, खासकर आर्म्स एक्ट के मामलों में अपराधियों को गिरफ्तारी के सात दिनों के भीतर सजा सुनाई गई। इससे अवैध बंदूक रखने पर अंकुश लगा और अपराध में काफी हद तक कमी आई। उनका मानना है कि अपराध काले धन से प्रेरित होता है और इससे निपटने के लिए इसके वित्तीय स्रोतों पर निशाना साधना जरूरी है।

क्योंकि वोटरों के कागजात की जांच करने और नए दावों और नाम-जोड़ने घटाने का भारी दबाव झेलना पड़ सकता है। ऐसी कई रिपोर्ट्स हैं कि कुछ सरकारी अधिकारियों ने खुद ही फॉर्म या गणना-प्रपत्र भर डाला और मतदाताओं के दस्तखत भी बीएलओ खुद ही कर रहे हैं। फिलहाल चुनाव आयोग के मुताबिक, इसी साल फरवरी में तीन-चार महीने की समीक्षा के बाद जारी अंतिम वोटर सूची में से तकरीबन 65 लाख वोटर पते पर नहीं पाए गए। उनमें करीब 19 लाख की मृत्यु हो चुकी है, कुछ दूसरी जगहें चले गए हैं। यही पेच है, जिससे विपक्षी पार्टियां आशंकित हैं।

हालांकि चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में पेश 21 अप्रैल के हलफनामे में यह जिक्र नहीं किया है कि उसे कोई विदेशी या संदिग्ध वोटर मिला, जिसका आजादी के बाद पहली बार ऐसी विशेष पुनर्रीक्षण की एक बड़ी वजह के तौर पर अधिसूचना में जिक्र किया गया था। बीच में चुनाव आयोग ने कहा था कि वोटर लिस्ट में कई नेपाली, बांग्लादेशी, म्यांमारी (रोहिंग्या) लोगों के होने की आशंका है। यह खबर भी उड़ाई गई थी कि सूची में करीब 35 लाख परदेसी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई में कहा कि आयोग को वोटरों को बाहर करने पर नहीं, बल्कि बड़े पैमाने पर वोटरों को जोड़ने पर ध्यान देना चाहिए। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और जयमाल्य बागची की पीठ ने यह भी कहा कि आधार कार्ड, राशन कार्ड या वोटर आईडी का फर्जी होना कोई दलील नहीं है, क्योंकि किसी भी कागजात के फर्जी होने की आशंका तो रहती ही है, इसलिए यह हरेक मामले के आधार पर तय होना चाहिए। इस दलील के साथ अदालत ने आयोग को आधार, वोटर आईडी वगैरह को स्वीकार करने को कहा और यह भी हिदायत दी कि गड़बड़ पाए जाने पर पूरी प्रक्रिया रद्द भी की जा सकती है।

फर्जी का मामला भी दिलचस्प है। आयोग ने जिस आवास प्रमाण-पत्र को अपनी स्वीकृत सूची में रखा है, उससे संबंधित एक ट्वीट कांग्रेस की ओर से आया, जिसमें आरा जिले में डॉग जी के नाम बाकायदा दुरुस्त मुहर के साथ एक आवास-पत्र बन गया है। खैर, एक अन्य सुनवाई में अदालत ने एडीआर के वकील प्रशांत भूषण से कहा कि गलतियां दिखाइए, यानी ऐसे 15 नाम आप ले आएं, जिन्हें मृत बताया गया और जिंदा मिले तो हम आदेश देंगे। इस बीच, बिहार विधानसभा में एसआईआर पर बहस के दौरान प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के साथ सत्तापक्ष की तीखी झड़प हुई। विपक्ष ने विधानसभा के बाहर चुनाव आयोग की कवायद के खिलाफ प्रदर्शन किया। संसद में कई दिन आयोग की विशेष कवायद के खिलाफ प्रदर्शन और बहस की मांग को लेकर हंगामा हुआ और संसद परिसर में इंडिया ब्लॉक की सभी सांसदों ने कागज पर लिखे एसआईआर को फाड़कर कूड़ेदान के हवाले किया। विधानसभा में तेजस्वी ने कहा कि हम वोटर लिस्ट के पुनर्रीक्षण के खिलाफ नहीं है, जैसे यह किया जा रहा है और जिस हड़बड़ी में किया जा रहा है, उससे नीयत पर शक होता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें टोका लेकिन वे एसआईआर पर नहीं पिछली बातों पर ही बोलते रहे कि कैसे उन्होंने राज्य में विकास किया, महिलाओं को अधिकार दिलाया है।

तेजस्वी ने विधानसभा में तो नहीं, लेकिन बाहर पत्रकारों के सामने कहा कि अगर भाजपा चुनाव आयोग की कवायद के जरिए अपनी जीत का इंतजाम कर चुकी है तो ऐसा चुनाव लड़ने के क्या मायने। ऐसे में हम चुनाव के बहिष्कार पर भी विचार कर सकते हैं। भाजपा के नेता, उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इसे विपक्ष के पहले ही हार स्वीकार करना बताया। हालांकि अंतिम सूची में फिलहाल करीब 7.9 लाख वोटरों में से 50 लाख कम होते हैं तो कुल 243 विधानसभा क्षेत्रों में औसतन एक क्षेत्र में तीन-चार हजार वोट कम हो सकते हैं। यह जरूरी तो नहीं कि किसी एक पार्टी के वोटर कटेंगे, लेकिन विपक्ष को आशंका है कि यह भाजपा के इशारे पर किया गया है। फिर पिछले 2020 के चुनावों में 35 सीटों पर जीत का फर्क लगभग इतने का ही था। नए सियासी समीकरण भी उभर रहे हैं, जो चुनाव के दोतरफा मुकाबले की संभावना को बहुकोणीय कर सकते हैं।

इस बार तीसरा कोण चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर अपनी जनसुराज पार्टी के जरिए पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले साल चार विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनावों में उनकी पार्टी को इतने वोट मिले थे, जिससे चुनावी नतीजे प्रभावित हुए। शायद उनकी कोशिश कुछ और छोटी पार्टियों को साथ मिलाकर तीसरा मोर्चा बनाने की है। एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी का गणित महागठबंधन से नहीं बैठता है तो प्रशांत के साथ तालमेल के कयास हैं। पारस पासवान की लोजपा पर भी उनकी नजर बताई जाती है। कयास यह भी है कि रालोसपा के उपेंद्र कुशवाहा भी एनडीए और खासकर वोटर लिस्ट की समीक्षा पर नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। अगर वे टूटते हैं तो प्रशांत उन्हें भी जोड़ सकते हैं। प्रशांत किशोर 2023 की गांधी जयंती से पूरे प्रदेश की पैदल यात्रा कर चुके हैं और अगड़ी जातियों के साथ दलित, अति पिछड़ी जातियों और अल्पसंख्यक युवाओं को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। इस वर्ष परीक्षा-पत्र लीक मामले में नौजवानों के धरने पर भी बैठे और एक मौके पर पुलिस की लाठी भी झेली तथा कुछेक घंटे हिरासत भी। उनके निशाने पर नीतीश और तेजस्वी दोनों हैं, लेकिन विपक्ष ज्यादा सतर्क दिख रहा है।

● विपिन कंधारी

> संसद का मानसून सत्र पूरी तरह हंगामे की भेंट चढ़ गया। 21 जुलाई से शुरू हुए सत्र में चर्चा के लिए कुल 120 घंटे का समय निर्धारित था, लेकिन लगातार हंगामे के कारण लोकसभा में महज 37 घंटे ही चर्चा हो पाई। लोकसभा चुनाव में भाजपा को अकेले दम बहुमत से वंचित करने से उत्साहित विपक्ष संसद के पहले सत्र में आक्रामक दिखा था। फिर हरियाणा और महाराष्ट्र में भाजपा की जीत से वह उत्साह उड़न छू हो गया और सत्तापक्ष की आक्रामकता लौट आई। कुछ मुद्दों पर तकरार अनापेक्षित नहीं है लेकिन उसका मर्यादा की सीमाएं लांघ जाना स्वीकार्य नहीं हो सकता।

देश को निराश करती संसद

विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की संसद ने एक बार फिर देश को निराश किया। 21 जुलाई से 21 अगस्त तक चले संसद के मानसून सत्र में भी काम कम, हंगामा ज्यादा हुआ। लोकसभा में मात्र 37 घंटे कामकाज हो पाया तो राज्यसभा में 41 घंटे 15 मिनट। करदाताओं की मेहनत की कमाई से चलने वाली संसद में हंगामा कभी भी सुखद नहीं कहा जा सकता। मानसून सत्र कठिन चुनौतियों के साये में हुआ था, फिर भी संसद में ऐसा कुछ नहीं दिखा कि सांसदों को देश की चुनौतियों का भान है। हमेशा की तरह शोर-शराबे के बीच ही सरकार अपना विधायी कामकाज निपटाने में सफल हो गई, लेकिन संसदीय कार्यवाही की दृष्टि से लोकसभा में 83 घंटे और राज्यसभा में 73 घंटे हंगामे की भेंट चढ़ गए। संसद की कार्यवाही पर आने वाले खर्च की नजर से देखें तो 204 करोड़ रुपए से भी ज्यादा हंगामे के चलते बर्बाद हो गए। यह तय है कि हमारे सांसद कभी काम नहीं, तो वेतन नहीं की नैतिकता नहीं दिखाएंगे।

पहलगाम पर आतंकी हमला, उसके जवाब में ऑपरेशन सिंदूर, ट्रम्प का संघर्ष विराम का श्रेय लेने का अंतहीन राग तथा उनकी ही ओर से छेड़े गए टैरिफ युद्ध जैसी जटिल चुनौतियों के साये में हुए मानसून सत्र में संसद का देश हित से विमुख होकर दलगत राजनीति का बंधक बन जाना देश के प्रति एक प्रकार का अपराध ही है। संसद से अपेक्षा थी कि अपनी संवैधानिक भूमिका का निर्वाह करते हुए इन तमाम मुद्दों पर गंभीर चर्चा से देश का मार्गदर्शन करेगी, लेकिन पूरा सत्र ही दलगत राजनीति से प्रेरित आरोप-प्रत्यारोप और हंगामे की भेंट चढ़ गया। हंगामा अक्सर विपक्ष ही करता है, लेकिन काम से ज्यादा हंगामे की बढ़ती प्रवृत्ति के लिए किसी एक पक्ष को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।

अगर राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े आतंकवाद और ऑपरेशन सिंदूर जैसे मुद्दों पर भी हमारी संसदीय चर्चा की दिशा दलगत राजनीति तय करेगी तो फिर वर्तमान राजनीति की दशा-दिशा के बारे में कहने को ज्यादा कुछ नहीं रह जाता। हमने बहुदलीय लोकतंत्र चुना है। इसलिए दलगत विभाजन और नीतिगत मतभिन्नता स्वाभाविक है। उसका सम्मान भी किया जाना चाहिए। सत्तापक्ष और विपक्ष, दोनों की अपनी-अपनी भूमिकाएं हैं, पर जरूरी नहीं कि वे हमेशा परस्पर विरोध की ही रहें।

सत्तापक्ष के कामकाज पर विपक्ष निगरानी रखे, जरूरत होने पर रोक-टोक भी करे, लेकिन देशहित और जनहित के मुद्दों पर दोनों में सहमति और समन्वय की अपेक्षा भी संविधान और संसदीय लोकतंत्र करता है, जो हाल के दशकों में हमारी राजनीति से नदारद है। कड़वा सच यह है कि दोनों ही पक्ष एक-दूसरे की भूमिकाओं को मन, वचन और कर्म से स्वीकार नहीं कर पाए हैं। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस एक दशक बाद भी स्वीकार करती नहीं दिख रही कि अब भाजपा सत्ता में है और वह विपक्ष में। दूसरी ओर तमाम तरह के दागी और बागी कांग्रेसियों को गले लगाने के बावजूद भाजपा कांग्रेसमुक्त भारत के सपने में ही जी रही है, जबकि लोकसभा में 99 सांसदों के अलावा कांग्रेस की तीन राज्यों में सरकार भी है। इस वास्तविकता के साथ ही देशहित और जनहित से मुंह मोड़ने का भी परिणाम है कि ऑपरेशन सिंदूर और संघर्ष विराम सरीखे संवेदनशील मामलों में भी सत्तापक्ष और विपक्ष अपने-अपने राजनीतिक मुद्दों को ही धार देते नजर आए। यह संभव नहीं कि सत्तापक्ष वही जवाब दे, जो विपक्ष सुनना चाहता है। संभव यह भी नहीं है कि विपक्ष श्रद्धालु बनकर सत्तापक्ष के जवाब को प्रवचन की तरह सुने। जटिल मुद्दों पर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सहमति और समन्वय की जरूरत होती है।

अहम चर्चाएं और बहस

सत्र के दौरान पहलगाम आतंकी हमले के बाद शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर पर विस्तृत बहस हुई। लोकसभा में इस मुद्दे पर 18 घंटे 41 मिनट चर्चा चली जिसमें 73 सांसदों ने हिस्सा लिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवाब दिया। वहीं राज्यसभा में 16 घंटे 25 मिनट चली बहस में 65 सांसदों ने भाग लिया और गृहमंत्री अमित शाह ने जवाब दिया। इसके अलावा भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री के अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने और विकसित भारत 2047 में अंतरिक्ष कार्यक्रम की भूमिका पर चर्चा शुरू हुई लेकिन बार-बार के हंगामें के कारण इसे पूरा नहीं किया जा सका। हंगामे के बावजूद कई हम विधेयक पारित हुए। इनमें आयकर विधेयक 2025, राष्ट्रीय खेल संचालन विधेयक 2025, ऑनलाइन गेमिंग विधेयक 2025, पोर्ट्स और शिपिंग से जुड़े 5 विधेयक, भारतीय प्रबंधन संस्थान विधेयक 2025 और खनन एवं खनिज संशोधन विधेयक 2025 शामिल हैं। दीवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता विधेयक 2025 और जन विश्वास संशोधन विधेयक 2025 को चयन समिति को भेजा गया। वहीं संविधान विधेयक 2025। केंद्र शासित प्रदेश शासन विधेयक 2025 और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2025 को संयुक्त समिति के पास भेजा गया। इसके अलावा मणिपुर में राष्ट्रपति शासन को 13 अगस्त 2025 से अगले 6 महीने के लिए बढ़ाने की मंजूरी दी गई और राज्य का बजट और विनियोग विधेयक भी पास हुआ।

अतीत में कई मौके आए, जब दलगत मतभिन्नता से ऊपर उठकर सत्तापक्ष और विपक्ष ने देशहित और जनहित में सहमति और समन्वय की परिपक्वता दिखाई, पर तब शायद ऐसी परस्पर कटुता नहीं थी। अब तो दलगत राजनीति एक तरह की निजी रंजिश में तब्दील दिखती है। इसी का नतीजा है कि विपक्ष को सत्तापक्ष निर्वाचित सरकार के बजाय तानाशाह नजर आता है, तो सत्तापक्ष को विपक्ष देशविरोधी। इस चश्मे की अपनी सीमाएं हैं, जो लगातार उजागर हो रही हैं और उसकी कीमत देश चुका रहा है। काम के बजाय हंगामा ज्यादा करने की प्रवृत्ति की बात अतिरंजना हर्गिज नहीं है। इस साल के बजट सत्र को अपवाद मान लें तो पिछले साल शीतकालीन सत्र में भी संसद की सर्वोच्चता की प्रति अत्यंत संवेदनशील हमारे प्रतिनिधि काम से ज्यादा हंगामा करते दिखे थे।

लोकसभा चुनाव में भाजपा को अकेले दम बहुमत से वंचित करने से उत्साहित विपक्ष संसद के पहले सत्र में आक्रामक दिखा था। फिर हरियाणा और महाराष्ट्र में भाजपा की जीत से वह उत्साह उड़न छू हो गया और सत्तापक्ष की आक्रामकता लौट आई। कुछ मुद्दों पर तकरार अनापेक्षित नहीं है, लेकिन उसका मर्यादा की सीमाएं लांघ जाना स्वीकार्य नहीं हो सकता। एक-दूसरे के प्रति आपत्तिजनक भाषा और व्यवहार अब आम हो चला है। पिछले सत्र में तो बात धक्का-मुक्की तक पहुंच गई थी।

भाजपा ने आरोप लगाया कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने संसद में प्रदर्शन के दौरान उसके सांसदों को धक्का दिया, जिसमें उसके दो सांसद प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत घायल हो गए। इस मामले में राहुल के विरूद्ध छह धाराओं में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। अप्रैल में पहलगाम में 26 निर्दोष पर्यटकों की उनका मजहब पूछकर निर्मम हत्या के बाद सर्वदलीय एकजुटता से उम्मीद जगी कि शायद देशहित के मुद्दों पर हमारी राजनीति दलगत संकीर्णता से उबरने की परिपक्वता रखती है, लेकिन उसे टूटने में ज्यादा समय नहीं लगा। सुरक्षा चूक की जवाबदेही और संघर्ष विराम की शर्तों के खुलासे की मांग से शुरू राजनीति चीन को जमीन सौंपने से लेकर पीओके वापस लिए बिना 1971 के पाक सैनिक बंदियों की रिहाई पर गैरजिम्मेदार आरोप-प्रत्यारोपों तक पहुंच गई। मानसून की बारिश अगर देश में तबाही का सबब बन रही है तो संसद के मानसून सत्र में सत्तापक्ष और विपक्ष में बढ़ी कटुता भी लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। इसके खतरे के निशान तक पहुंचने से पहले ही संभल जाने में समझदारी है।

सपा, तृणमूल कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की शिवसेना समेत आम आदमी पार्टी उस विधेयक पर विचार के लिए गठित संयुक्त संसदीय समिति में शामिल होने को तैयार नहीं, जिसके तहत आपराधिक मामलों में 30 दिन तक हिरासत अथवा जेल में रहने वाले प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रियों और केंद्र शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों एवं उनके मंत्रियों को पद छोड़ना होगा। इन दलों के इस फैसले ने केवल कांग्रेस और उसके कुछ सहयोगी दलों का असमंजस बढ़ाने का ही काम नहीं किया, बल्कि विपक्षी गठबंधन आईएनडीआईए की एकजुटता पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस अपने नेतृत्व वाले गठबंधन की एका का परिचय देने के लिए कुछ भी करे, इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि जो दल संसदीय समिति में शामिल होने को तैयार नहीं, वे वही हैं, जो व्यक्ति या परिवार विशेष की ओर से संचालित हैं।

यह पहली बार नहीं, जब व्यक्ति या परिवार केंद्रित दल राजनीतिक एवं चुनावी सुधारों की किसी पहल को प्रभावी बनाने में असहयोग कर रहे हों। अपने देश में राजनीतिक भ्रष्टाचार एक कटु सच्चाई है, लेकिन जब भी उस पर लगाम लगाने की कोई पहल होती है, किसी न किसी बहाने उसका विरोध शुरू हो जाता है। इसका ही ताजा उदाहरण है 130वें संविधान संशोधन विधेयक का विरोध। आमतौर पर जब विपक्ष सदन में किसी विधेयक का विरोध करता है तो उसे संसदीय समिति भेजने की भी मांग करता है। अब जब किसी मामले में फंसकर जेल गए सत्ताधारी नेता को हटाने के प्रविधान वाले विधेयक को ऐसी ही समिति में भेजने का फैसला कर लिया गया है, तब कई विपक्षी दल उसका बहिष्कार करना आवश्यक समझ रहे हैं। यह और कुछ नहीं, संसदीय परंपरा और प्रक्रिया से पलायन है।

समझना कठिन है कि विपक्षी दल उक्त विधेयक पर अपनी आपत्ति दर्ज कराने के लिए तैयार क्यों नहीं हैं? कोई भी समझ सकता है कि उक्त विधेयक मुख्यतः भ्रष्ट नेताओं के भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए लाया जा रहा है। आखिर यह काम क्यों नहीं किया जाना चाहिए? क्या यह किसी से छिपा है कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल किस तरह जेल से सरकार चलाने की जिद पकड़े थे? हालांकि प्रस्तावित कानून पूर्ण राज्य का दर्जा वाले प्रांतों के लिए नहीं है, लेकिन सब जानते हैं कि कुछ समय पहले भ्रष्टाचार के एक गंभीर मामले में कई माह जेल में रहे तमिलनाडु के सेंथिल बालाजी किस तरह जमानत पाते ही मंत्री बना दिए गए थे। क्या विपक्षी दल यह चाहते हैं कि नेताओं को जेल से सरकार चलाने या जमानत पर होते हुए भी मंत्री बनने का अवसर मिलना चाहिए? यदि वे अपने लिए विशिष्ट नियम-कानून चाहते हैं तो यह विशेषाधिकारों की पराकाष्ठा ही है।

● इन्द्र कुमार

कितना हुआ काम और कितना नुकसान

सत्र के दौरान लोकसभा में 14 विधेयक पेश हुए एक वापस लिया गया और कुल 15 विधेयक दोनों सदनों से पारित हुए। फिर भी प्रोडक्टिविटी बहुत खराब रही। लोकसभा में 120 घंटे के लक्ष्य के मुकाबले केवल 37 घंटे ही काम हुआ यानी 31 प्रतिशत प्रोडक्टिविटी रही। वहीं राज्यसभा में 120 घंटे के मुकाबले केवल 41 घंटे 15 मिनट काम हो सका, यानी करीब 39 प्रतिशत प्रोडक्टिविटी रही। संसद के कार्यवाही का खर्च भारी होता है। 1 मिनट में लगभग ढाई लाख रुपए और 1 घंटे में डेढ़ करोड़ रुपए खर्च होते हैं। ऐसे में हंगामे की वजह से दोनों सदनों में करीब 200 करोड़ रुपए से ज्यादा का सीधा-सीधा नुकसान हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्र के नतीजे पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष चर्चा से बचता है ताकि उनके युवा सांसदों की प्रतिभा सामने ना आ सके। वहीं कांग्रेस ने सरकार पर पलटवार करते हुए गतिरोध के लिए गृहमंत्री को जिम्मेदार ठहराया और आरोप लगाया कि सरकार ने असली मुद्दों से ध्यान भटकने के लिए विवादित विधेयक पेश किया। मानसून सत्र 2025 का बड़ा हिस्सा हंगामें और नारेबाजी में बर्बाद हो गया।

सरगुजा संभाग बना राजनीति का केंद्र

छत्तीसगढ़ में राजनीतिक शक्ति का केंद्र दुर्ग संभाग से सरगुजा संभाग की ओर खिसकता दिखाई दे रहा है। राज्य में पहली बार ऐसा हुआ है कि कैबिनेट में सबसे अधिक मंत्री सरगुजा संभाग के हैं। मुख्यमंत्री सहित 5 मंत्री सरगुजा संभाग से आते हैं। दरअसल, प्रदेश की राजनीति में समीकरण लगातार बदलते रहे हैं। पूर्ववर्ती कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार में दुर्ग संभाग सत्ता का केंद्र माना जाता था, तो अब सरगुजा संभाग नए शक्ति केंद्र के रूप में उभरा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार में हुए मंत्रिमंडल विस्तार के बाद सरगुजा प्रदेश का सबसे ज्यादा मंत्री देने वाला क्षेत्र बन गया है। अंबिकापुर विधायक राजेश अग्रवाल के मंत्री पद की शपथ लेने के बाद सरगुजा संभाग से कुल मुख्यमंत्री समेत 5 मंत्री शामिल हो गए। यह प्रदेश की राजनीति में पहली बार हुआ है जब सरगुजा संभाग से ज्यादा संख्या में मंत्री बनाए गए हों।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय स्वयं सरगुजा संभाग के कुनकुरी विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। इनके अलावा रामविचार नेताम (रामानुजगंज), श्यामबिहारी जायसवाल (मनेन्द्रगढ़) और लक्ष्मी राजवाड़े (सूरजपुर) पहले से मंत्री पद संभाल रहे हैं। पांच मंत्रियों की मौजूदगी ने सरगुजा को सत्ता में निर्णायक भूमिका प्रदान कर दी है। मौजूदा समय में सरगुजा की बढ़ती भूमिका यह संकेत देती है कि आने वाले चुनावों में यही संभाग भाजपा की राजनीति का मुख्य आधार बनेगा।

पूर्ववर्ती भूपेश बघेल की कांग्रेस सरकार में दुर्ग संभाग राजनीति का केंद्र था। उस समय छह मंत्री इसी क्षेत्र से थे। पाटन विधानसभा से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल स्वयं थे। उनके साथ कवर्धा से मोहम्मद अकबर, डौंडीलोहारा से अनिला भेड़िया, साजा से रविन्द्र चौबे, अहिवारा से रुद्र गुरु और दुर्ग ग्रामीण से ताम्रध्वज साहू कैबिनेट में शामिल थे। उस दौर में दुर्ग संभाग को सत्ता का गढ़ माना जाता था, लेकिन मौजूदा भाजपा सरकार में समीकरण पूरी तरह सरगुजा के पक्ष में बदल गए हैं। भाजपा ने क्षेत्रीय और जातीय संतुलन साधते हुए सरगुजा को प्राथमिकता दी है।

1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुई। राजधानी रायपुर के पुलिस ग्राउंड में मप्र से अलग होकर नए राज्य का गठन हुआ और अजीत जोगी को पहला मुख्यमंत्री बनाया गया। उस समय 90 सदस्यीय विधानसभा में कांग्रेस के पास 48, भाजपा के 36, बसपा के 3, निर्दलीय 2 और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के पास 1 विधायक था। जोगी ने पहले मंत्रिमंडल में 29 मंत्रियों को शामिल किया। इसमें 24 मंत्री व कुछ राज्य मंत्री भी बनाए गए थे।

क्षेत्रीय दबदबा बढ़ाने का नया राजनीतिक ट्रेंड

राजनीति विशेषज्ञ डॉ. अजय चंद्राकर का कहना है कि प्रथम मुख्यमंत्री अजीत जोगी और भाजपा की तीन बार की डॉ. रमन सरकार के दौरान मंत्रियों के वितरण में संतुलन था। पिछली कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार में मंत्रियों के मामले में दुर्ग संभाग का दबदबा था, यहां सबसे अधिक मंत्री बनाए गए थे। वर्तमान में साय सरकार में सरगुजा से मुख्यमंत्री सहित सबसे अधिक मंत्री बनाए गए हैं। यह क्षेत्रीय दबदबा बढ़ाने का राजनीति में नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है। पूर्व प्रमुख सचिव चंद्रशेखर गंगराड़े का कहना है कि पहले 13 से ज्यादा मंत्री हुआ करते थे। संविधान के 91वें संशोधन अधिनियम, 2003 के तहत अनुच्छेद 164 में खंड 1(ए) जोड़ा गया। इस प्रविधान के अनुसार किसी भी राज्य के मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती।

औसतन हर तीसरे विधायक को मंत्री पद मिला। जोगी कैबिनेट में राजेंद्र प्रसाद शुक्ला, रामचंद्र सिंहदेव, महेंद्र कर्मा, प्रेमसाय सिंह टेकाम, नंदकुमार पटेल, रविंद्र चौबे, सत्यनारायण शर्मा, गीतादेवी सिंह और अमितेष शुक्ला जैसे दिग्गज शामिल थे। गीतादेवी उस समय की एकमात्र महिला मंत्री थीं। राज्य मंत्रियों में भूपेश बघेल, मोहम्मद अकबर, मनोज मंडावी और ताम्रध्वज साहू को जिम्मेदारी मिली। दिलचस्प यह भी कि जोगी उस समय विधायक नहीं थे। वे बाद में भाजपा विधायक रामदयाल उइके से मारवाही की सीट खाली कराकर उपचुनाव जीते और सदन पहुंचे।

केंद्र की अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने संविधान में संशोधन कर मंत्रियों की संख्या पर सीमा तय की थी। संविधान के 91वें संशोधन अधिनियम 2003 के तहत अनुच्छेद 164 में खंड 1(ए) जोड़ा गया। इसके अनुसार किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या विधानसभा सदस्यों के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। यानी छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री समेत केवल 13 मंत्री ही बन सकते हैं। इस बदलाव ने तत्कालीन मुख्यमंत्री अजीत जोगी को अपने कैबिनेट से रजिंदर पाल सिंह भाटिया, विक्रम उसेंडी, पूनम चंद्राकर, सत्यानंद राठिया और महेश बघेल को मंत्री पद से हटाना पड़ा।

2003 में भाजपा की पहली सरकार बनी तो डॉ. रमन सिंह के नेतृत्व में 18 मंत्रियों की टीम बनी। इसमें अजय चंद्राकर, अमर अग्रवाल, बृजमोहन अग्रवाल, गणेशराम भगत, हेमचंद यादव और ननकीराम कंवर जैसे नाम शामिल थे। छह महीने बाद संवैधानिक प्रावधान लागू होने के बाद पांच मंत्रियों को हटाना पड़ा। रमन सरकार के दूसरे कार्यकाल 2008 में ननकीराम कंवर, रामविचार नेताम, पुन्नूलाल मोहिले, बृजमोहन अग्रवाल, अमर अग्रवाल, चंद्रशेखर साहू, लता उसेंडी, राजेश मूणत, विक्रम उसेंडी, हेमचंद्र यादव, केदार कश्यप मंत्री रहे। वहीं 2013 के तीसरे कार्यकाल में राम सेवक पैकरा, अजय चंद्राकर, प्रेम प्रकाश पांडेय, रमशिला साहू, अमर अग्रवाल, भैयालाल राजवाड़े, पुन्नूलाल मोहिले, बृजमोहन अग्रवाल, राजेश मूणत, केदार कश्यप, महेश गागड़ा, दयाल दास बघेल मंत्री रहे।

● रायपुर से टीपी सिंह

खुद डूबे और उद्धव को भी ले डूबे राज!

बीएमसी चुनाव से पहले उद्धव और राज ठाकरे को बड़ा झटका लगा है। करीब दो दशक बाद साथ आए ठाकरे बंधु को बृहन्मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट (बेस्ट) क्रेडिट सोसायटी के चुनाव में करारी शिकस्त मिली है। शिवसेना और एमएनएस का पैनल 21 सीटों पर चुनाव लड़ा था और सभी में हार मिली। राज और उद्धव मतभेदों को बुलाकर 5 जुलाई, 2025 को एकसाथ आए थे। दोनों भाइयों ने मंच साझा किया था। दोस्ती के बाद दोनों का ये पहला चुनाव था। ऐसे में ये हार उनके लिए झटके से कम नहीं है। मुंबई बेस्ट क्रेडिट सोसाइटी में 15 हजार से ज्यादा सदस्य हैं। 9 साल बाद चुनाव हुआ था। इस इलेक्शन से पहले तक यहां पर शिवसेना (यूबीटी) का नियंत्रण था। ये चुनाव राज-उद्धव के लिए इस वजह से भी झटका है, क्योंकि इसमें ज्यादातर सदस्य मराठी हैं और ठाकरे बंधु खासतौर से राज मराठियों के हक की लड़ाई लड़ने का दावा करते हैं।

ठाकरे भाइयों की हार से भाजपा खुश है। चुनाव के नतीजों के बाद खुद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ठाकरे परिवार ने ही इसे राजनीतिक बना दिया था। हम इसे क्रेडिट सोसाइटी के चुनाव के तौर पर देख रहे थे। अब ऐसा लग रहा है कि जनता ने ठाकरे ब्रांड को नकार दिया है। वहीं, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि ईवीएम पर शक जताने वालों को करारा जवाब मिल गया है। महाराष्ट्र की जनता ने तय कर लिया है कि जो काम करते हैं उन्हें काम करने का मौका दिया जाए और जो घर बैठते हैं उन्हें घर बैठा दिया जाए। ठाकरे भाइयों ने उत्कर्ष पैनल के तहत चुनाव लड़ा था, जिसने 21 उम्मीदवार उतारे थे। सहकार समृद्धि पैनल से भाजपा नेता प्रसाद लाड और प्रवीण दरेकर चुनाव मैदान में थे। यूनियन नेता शशांक राव ने भी शशांक राव पैनल के तहत अपने उम्मीदवार उतारे थे। हार के बाद मनसे नेता संदीप देशपांडे ने कहा, इसे लिटमस टेस्ट मानना गलत है। इसकी तुलना बीएमसी चुनावों से नहीं की जा सकती। उन्होंने पहले दावा किया था कि चुनाव प्रचार के दौरान पैसे बांटे गए थे। शिवसेना यूबीटी नेता सुहास सामंत ने भी दावा किया कि उनकी पार्टी धनबल के सामने टिक नहीं सकती। चुनाव जीतने के बाद शशांक राव ने उद्धव ठाकरे की कड़ी आलोचना की और दावा किया कि यह परिणाम बेस्ट कर्मचारियों द्वारा शिवसेना-यूबीटी की निजीकरण नीति, कर्मचारियों के भविष्य से खिलवाड़ और ग्रेच्युटी फंड को अपने पसंदीदा ठेकेदारों की तिजोरियों में भरने के खिलाफ दिया गया जवाब है। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ इस चुनाव की बात नहीं है। असल में, पूरा ध्यान हमेशा इस बात पर रहता है कि आप क्या करते हैं। क्रेडिट सोसाइटी मुद्दा नहीं थी। उन्होंने कहा कि इस बार, हम चुनाव प्रचार में बहुत देर से शामिल हुए, लेकिन कर्मचारी उस स्थिति से वाकई नाराज थे जो पैदा की गई थी। भर्तियां सालों से लंबित थीं, कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग का लाभ नहीं मिला था। कई सेवानिवृत्त कर्मचारियों को तीन साल से ग्रेच्युटी नहीं मिली थी।

ठाकरे बंधुओं द्वारा एक भी सीट न जीत पाने को अब एक बड़ी राजनीतिक शर्मिंदगी के रूप में देखा जा रहा है। नगर निगम चुनावों से पहले एकता दिखाने और जनभावनाओं को परखने की उनकी कोशिश उल्टी पड़ गई है। बीएमसी चुनाव नजदीक है ऐसे में यह नतीजा उनके गठबंधन के भविष्य और मुंबई में सत्तारूढ़ गठबंधन को कड़ी चुनौती देने की उनकी क्षमता पर गंभीर सवाल खड़े करता है। सवाल उठता है कि क्या अब भी ठाकरे भाई साथ चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि बीएमसी चुनाव में चुनौती सोसायटी चुनाव से भी बड़ी होगी। बेस्ट क्रेडिट सोसायटी में अधिकांश कर्मचारी मराठी भाषी लोग हैं और इस चुनाव को मराठी मतदाताओं की निष्ठा के बारे में एक छोटा सा संकेत माना जा रहा है। उद्धव और राज के रास्ते पिछले दो दशकों में अलग-अलग रहे हैं। उद्धव ने शिवसेना को कांग्रेस-एनसीपी के साथ महाविकास अघाड़ी में लाया, तो राज ने पीएम मोदी और भाजपा की तारीफ करते हुए आक्रामक हिन्दुत्व और मराठी मानुस की राजनीति को धार दी। लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव में दोनों को भारी नुकसान हुआ। ऐसे में अब दोनों ने विरोधियों से लड़ने के लिए अपनों से समझौते की राजनीति शुरू की।

जानकार कहते हैं कि शिवसेना (यूबीटी)-मनसे को इस चुनाव को ठाकरे बंधुओं के संयुक्त मोर्चे के रूप में पेश नहीं करना चाहिए था। कोई भी सहकारी ऋण समिति का चुनाव इतना हाई-प्रोफाइल नहीं रहा। मनसे-शिवसेना (यूबीटी) को इस चुनाव को इतना प्रमुख नहीं बनाना चाहिए था। अब, यह स्पष्ट है कि भाजपा उनकी हार का फायदा उठाएगी। यह परिणाम दोनों दलों के लिए एक करारा झटका है, खासकर पार्टी कार्यकर्ताओं के मनोबल के लिहाज से। हार गठबंधन के लिए इस वजह से भी झटका है क्योंकि वर्षों से इस सोसायटी पर बेस्ट कामगार सेना का प्रभुत्व रहा है, जो उद्धव ठाकरे के गुट से संबद्ध है। इन नतीजों से यह भी तय हो गया कि भाजपा गठबंधन को ठाकरे भाइयों के साथ आने से कोई खतरा नहीं है और प्रभावशाली सहकारी संस्था पर उनका अपना प्रभुत्व भी कम हो गया। हालांकि नतीजों ने ठाकरे गठबंधन की प्रभावशीलता और एनडीए के खिलाफ एक बड़े मराठी मोर्चे की व्यवहार्यता पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

● बिन्दु माथुर

फडणवीस और राज ठाकरे के बीच पक रही नई खिचड़ी...

महाराष्ट्र की राजनीति में सियासी हलचल तेज हो गई है। गत दिनों महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बीच बैठक हुई। राज ठाकरे मुख्यमंत्री से मिलने उनके वर्षा बंगले पर पहुंचे। इसी के बाद राज और फडणवीस की मुलाकात पर राजनीतिक चर्चाओं का दौर फिर शुरू हो गया है। मीटिंग के बाद राज ठाकरे ने बताया कि उनकी मुख्यमंत्री से किन मामलों को लेकर चर्चा हुई। राज ठाकरे और मुख्यमंत्री के बीच में हुई इस मुलाकात के समय को लेकर अटकलें तेज हो गई है। दरअसल, हाल ही में ठाकरे बंधु राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक मंच पर मराठी भाषा के मामले को लेकर साथ आए। लेकिन, अब राज ठाकरे ने मुख्यमंत्री फडणवीस से उस समय मुलाकात की है जब ठाकरे बंधु बीईएसटी कर्मचारी सहकारी क्रेडिट सोसायटी चुनाव में पूरी तरफ से फेल हो गए।

वन स्टेट-वन इलेक्शन पर फंसा पेंच...

राजस्थान सरकार ने निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर अपनी मंशा स्पष्ट कर दी है। पंचायती राज और स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने घोषणा की कि राज्य सरकार दिसंबर 2025 में निकाय और पंचायत चुनाव कराने की पूरी तैयारी कर रही है। इसके साथ ही, सरकार वन स्टेट वन इलेक्शन की तर्ज पर इन चुनावों को एक साथ कराने की दिशा में कदम उठा रही है। मंत्री खर्रा ने कहा कि हाईकोर्ट के हालिया निर्देशों का अध्ययन किया जा रहा है और विधिक राय के आधार पर जल्द ही अंतिम फैसला लिया जाएगा। बता दें, हाल ही में राजस्थान हाईकोर्ट ने पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में देरी को लेकर सरकार के खिलाफ सख्त रुख अपनाया था। जस्टिस अनूप ढंड की अदालत ने स्पष्ट किया कि संविधान के अनुच्छेद-243ई और राजस्थान पंचायती राज अधिनियम की धारा-17 के तहत पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने से पहले चुनावी प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए। कोर्ट ने परिसीमन के बहाने चुनाव टालने पर नाराजगी जताते हुए कहा कि इससे स्थानीय शासन में रिक्तता पैदा होती है, जिसका सेवाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। कोर्ट ने सरकार को जल्द से जल्द चुनाव कराने और बिना उचित प्रक्रिया के निलंबित किए गए पंचायत प्रशासकों को बहाल करने के निर्देश दिए।

राज्य निर्वाचन आयुक्त मधुकर गुप्ता ने कहा कि हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद आयोग पूरी तरह सक्रिय हो गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि कोर्ट के आदेशों की पालना में जल्द ही चुनाव कार्यक्रम जारी किया जाएगा। गुप्ता ने कहा कि हाईकोर्ट का आदेश हमें प्राप्त हो चुका है। अब हमारे पास जल्द चुनाव कराने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। हालांकि, उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन की संभावना को खारिज करते हुए कहा कि इसके लिए संवैधानिक संशोधन की जरूरत है, जो अभी संभव नहीं है। मधुकर गुप्ता ने कहा- कानूनी प्रावधान साफ है कि 5 साल के अंदर पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकायों के चुनाव होने चाहिए। हाईकोर्ट ने जो आदेश दिया है, वह इन्हीं प्रावधानों के अंदर दिया है। विभिन्न हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश हैं, उनसे हमने समय-समय पर राज्य सरकार को आगाह किया। हरियाणा-पंजाब में भी चुनाव में देरी हुई तो पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने उसमें दखल दिया और इसी तरह के आदेश दिए। अभी जो आदेश हुए हैं, उसी से मिलते-जुलते आदेश हैं। कर्नाटक में भी देरी हो रही थी, वहां भी कोर्ट ने दखल दिया। यह केवल राजस्थान की समस्या नहीं, अन्य राज्यों में भी है। अन्य राज्यों में सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट ने दखल दिया है और इसी तरह के निर्देश दिए हैं।

भजनलाल शर्मा सरकार जहां वन नेशन वन इलेक्शन से पहले वन स्टेट वन इलेक्शन का ट्रायल करना चाह रही है, वहीं कांग्रेस ने इस फैसले को चुनाव से भागने की साजिश बताया है। राजस्थान की राजनीति में यह मुद्दा अब लगातार गरमाता जा रहा है और सत्ता तथा विपक्ष आमने-सामने नजर आ रहे हैं। दरअसल, राजस्थान में कई नगर निगम, परिषदों और पंचायतों का कार्यकाल पूरा हो चुका है। लेकिन चुनाव कराने की बजाय सरकार ने वहां प्रशासक नियुक्त कर दिए हैं। इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने आज जयपुर में स्वराज बचाओ के नाम से बड़ा विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस दफ्तर से शहीद स्मारक तक मार्च निकाला गया। इस दौरान पुलिस से धक्का-मुक्की भी हुई। कांग्रेस का कहना है कि कोर्ट भी सरकार को चुनाव करवाने के लिए कह चुका है, लेकिन भाजपा सरकार हार के डर से चुनाव टाल रही है और वन स्टेट वन इलेक्शन का बहाना बना रही है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने इसे जनता के अधिकारों पर हमला बताया। वहीं, सरकार ने कांग्रेस के आरोपों को सिरे से नकारा है। नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा का कहना है कि अलग-अलग समय पर पंचायत और स्थानीय निकाय चुनाव होने से जनता पर खर्च का बोझ बढ़ता है। ऐसे में सरकार ने फैसला लिया है कि दिसंबर में सभी चुनाव एक साथ कराए जाएंगे। सरकार का मानना है कि इससे संसाधन भी बचेंगे और प्रशासनिक कामकाज भी सुचारू रहेगा।

इधर, राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से वन स्टेट, वन इलेक्शन को नकारे जाने के बाद इस मामले में पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने कहा- इस मामले में सामूहिक निर्णय करेंगे। जो निर्णय होगा, उसके अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्य, प्रधान और जिला प्रमुख चुनाव की घोषणा बाद में होगी। 21 जिला परिषदों और 222 पंचायत समितियों के सदस्यों और प्रधान, जिला प्रमुखों का कार्यकाल नवंबर-दिसंबर में खत्म होगा। इसलिए उनकी घोषणा बाद में होने के आसार हैं। 6 जिला परिषदों और 78 पंचायत समितियों का कार्यकाल अगस्त-सितंबर 2026 में खत्म होगा। 4 जिला परिषदों और 30 पंचायत समितियों का कार्यकाल नवंबर-दिसंबर 2026 में खत्म होगा।

हाईकोर्ट के आदेश के बाद राज्य चुनाव आयोग ने जल्द चुनाव कराने की घोषणा कर दी हैं। वहीं सरकार का कहना है कि वह वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत ही एक साथ चुनाव कराने पर विचार कर रही हैं। जिसके बाद आयोग और सरकार में टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। इसी के चलते सरकार ने सिंगल बैंच के आदेश को डिवीजन बैंच में चुनौती दी है। सरकार का कहना है कि पंचायत और निकायों में परिसीमन में समय लगा हैं। इसके साथ ही नए जिले बनने पर वार्डों के पुनर्गठन के चलते चुनाव कराने के लिए समय दिया जाए।

● **जयपुर से आर.के. बिन्नानी**

सरकार के परिसीमन का क्या होगा?

सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकायों के वार्डों का परिसीमन किया है। नई पंचायत बनाने का भी फैसला किया है। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने साफ किया है कि सरकार जिन नई पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकायों के गठन और वार्डों के परिसीमन का नोटिफिकेशन जारी कर देगी, उनके चुनाव नए परिसीमन के हिसाब से हो जाएंगे। अगर नोटिफिकेशन नहीं हुआ तो फिर पुराने इलाकों के हिसाब से चुनाव करवाए जाएंगे। जानकारों का मानना है कि राजस्थान में स्थानीय निकाय और पंचायत चुनाव हमेशा सरकारों की लोकप्रियता की बड़ी परीक्षा माने जाते हैं। भजनलाल सरकार अब पूरे होमवर्क के साथ वन स्टेट वन इलेक्शन करवाकर न सिर्फ खर्च और संसाधन बचाने की कोशिश कर रही है, बल्कि इसे वन नेशन वन इलेक्शन का ट्रायल भी माना जा रहा है। अगर यह प्रयोग सफल रहा तो भाजपा आगे चलकर देशभर में एक साथ चुनाव कराने के लिए और मजबूत माहौल बना सकती है।

विकास कम, सत्ता की लालसा ज्यादा

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा के मानसून सत्र के चौथे दिन सदन में अपने साढ़े आठ साल के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाते हुए विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने 1947 से 2017 तक विपक्षी दलों के शासन की तुलना 2017 से 2025 तक अपनी सरकार के कार्यकाल से की और विपक्ष पर परिवारवादी सोच को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री ने विपक्ष के पीडीए नारे को परिवार विकास प्राधिकरण करार दिया और उनकी सीमित सोच पर कटाक्ष किया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने समावेशी एवं समग्र विकास को उप्र एवं भारत के विकास का आधार बताया। उन्होंने कहा, हर विधानसभा क्षेत्र में विकास हो और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ बिना किसी भेदभाव के सभी तक पहुंचे। समावेशी विकास ही विकसित उप्र और विकसित भारत की अवधारणा को साकार कर सकता है। विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि उनकी चर्चाओं में विकास कम और सत्ता की लालसा ज्यादा होती है। मुख्यमंत्री ने चार्वाक का उदाहरण देते हुए विपक्ष पर परिवारवादी सोच का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आप केवल अपने परिवार तक सीमित हैं। आपका परिवार विकास प्राधिकरण दृष्टिकोण स्वामी विवेकानंद के कूप मण्डूक दर्शन को प्रतिबिम्बित करता है। दुनिया प्रतिस्पर्धा के रास्ते पर आगे बढ़ रही है, लेकिन आप अभी भी परिवार तक ही सीमित हैं।

मुख्यमंत्री ने उप्र के अतीत की कड़वी सच्चाई सामने रखते हुए कहा कि 1960 के बाद से राज्य का लगातार पतन होता गया है। उन्होंने कहा कि विशाल सामर्थ्य, उपजाऊ भूमि, नदियां और श्रमशक्ति होने के बावजूद नीतिगत उदासीनता के कारण उप्र 1980 के दशक के बाद देश का सबसे बीमारू राज्य बन गया। योजनाएं बनती थीं, घोषणाएं होती थीं, लेकिन न इच्छाशक्ति थी और न ही क्रियान्वयन का संकल्प। उन्होंने उस दौर की समस्याओं का जिक्र करते हुए कहा कि युवाओं को रोजगार नहीं मिलता था, किसानों को राहत नहीं थी और निवेशकों में भरोसे की कमी थी। अपराध और अराजकता का बोलबाला था। पलायन, गरीबी, इन्सेफलाइटिस और डेंगू जैसी बीमारियों से होने वाली मौतें, भ्रष्टाचार, भेदभाव और भाई-भतीजावाद ने उप्र को जकड़ रखा था। मुख्यमंत्री ने 2017 के बाद डबल इंजन सरकार के तहत हुए बदलावों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि 2017 के बाद कानून का राज स्थापित हुआ। अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई। उद्योगों के लिए अनुकूल माहौल बनाया गया और उप्र निवेशकों के लिए ड्रीम डेस्टिनेशन बन गया। योजनाओं का क्रियान्वयन बिना भेदभाव और तुष्टिकरण के हो रहा है। उन्होंने गर्व के साथ कहा कि आज उप्र की पहचान सुशासन से है। बेहतर कानून व्यवस्था, मजबूत इन्फ्रास्ट्रक्चर और सरकार की सकारात्मक सोच ने उप्र को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है।

मुख्यमंत्री ने उप्र की आर्थिक प्रगति के प्रभावशाली आंकड़े पेश किए। उन्होंने बताया कि 2016-17 में उप्र की जीएसडीपी 13 लाख करोड़ रुपए थी, जो इस वित्तीय वर्ष के अंत तक 35 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने की उम्मीद है। राष्ट्रीय जीडीपी में उप्र का योगदान 8 फीसदी से बढ़कर 9.5 फीसदी हो गया है। प्रति व्यक्ति आय 43 हजार रुपए से बढ़कर 1 लाख 20 हजार रुपए तक पहुंच चुकी है। निर्यात 84 हजार करोड़ रुपए से बढ़कर 1 लाख 86 हजार करोड़ रुपए हो गया है और राज्य का बजट 3 लाख करोड़ से बढ़कर 8 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। डिजिटल लेनदेन 122 करोड़ रुपए से बढ़कर 1400 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उप्र बीमारू राज्य से रेवेन्यू सरप्लस स्टेट बनने की ओर अग्रसर है। मुख्यमंत्री ने भारत की आर्थिक प्रगति का उल्लेख करते हुए कहा कि 1947 में भारत दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था, लेकिन 1980 तक यह 11वें स्थान पर खिसक गया। 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने प्रगति की और 2017 में सातवें, 2024 में पांचवें और 2025 में चौथे स्थान पर पहुंच गया है। उन्होंने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि आपने छठी अर्थव्यवस्था को 11वें स्थान तक पहुंचा दिया था, लेकिन आज भारत अपनी सामर्थ्य और शक्ति का परिचय दुनिया को दे रहा है।

मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, इनकी नीयत कभी सबके विकास की नहीं रही। इन्होंने साथ तो सबका लिया, लेकिन विकास सिर्फ अपने परिवार का किया। इनके समय में न व्यापारी सुरक्षित था, न बेटी सुरक्षित थी। यही वजह रही कि देश और प्रदेश पिछड़ते चले गए। 8 से 9 साल पहले एटा की पहचान अपराध और माफिया के गढ़ के रूप में थी। गरीबों की जमीन पर कब्जा होता था, उनकी सुनवाई नहीं होती थी। जब नागरिक की संपत्ति ही सुरक्षित न हो, तब सरकार उसके कल्याण के लिए क्या करेगी? यही स्थिति तब थी। लेकिन आज एटा बेहतरीन कानून-व्यवस्था और निवेश की नई पहचान बना है।

● **लखनऊ से मधु आलोक निगम**

निवेशकों में विश्वास पैदा हुआ

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत 17वीं-18वीं सदी में दुनिया की नंबर-1 अर्थव्यवस्था था। 1947 से 1960 तक छठे स्थान पर रहा, लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की नीतियों ने इसे 2014 तक 11वें स्थान पर पहुंचा दिया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने सबका साथ, सबका विकास का मंत्र दिया और आज भारत चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अगले दो वर्षों में यह तीसरे स्थान पर होगा। दुनिया के सामने भारत का नया गौरवशाली चेहरा उभरेगा। योगी ने कहा कि 2017 में जब उनकी सरकार बनी तो उप्र देश की सातवीं अर्थव्यवस्था था। आज उप्र दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। यह तब हुआ जब सत्ता पोषित गुंडे-माफिया पर कार्रवाई हुई, दंगाइयों के खिलाफ कठोर कदम उठे और निवेशकों में विश्वास पैदा हुआ। मुख्यमंत्री ने कहा कि उप्र अब तक 45 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव आकर्षित कर चुका है, जिनमें से 15 लाख करोड़ जमीनी धरातल पर उतारे गए हैं। इससे अब तक 60 लाख युवाओं को रोजगार मिला है। उन्होंने बताया कि हाल ही में पुलिस बल में 60,244 युवाओं की भर्ती हुई है, जिसमें एटा के भी युवा शामिल हैं। नौकरी बिना भेदभाव, बिना चेहरा देखे, सिर्फ योग्यता के आधार पर दी जा रही है। साथ ही मुख्यमंत्री युवा योजना के तहत 70,000 युवाओं को ब्याज और गारंटी मुक्त ऋण तथा मार्जिन मनी दी गई है ताकि वे अपना उद्यम स्थापित कर सकें।

सीट बंटवारे पर उठा-पटक

बिहार विधानसभा चुनाव अक्टूबर-नवंबर के बीच कराए जा सकते हैं। उससे पहले राजनीतिक पार्टियां सीट शेयरिंग फॉर्मूला बैठाने में लगी हुई हैं। सूबे के सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) में सीटों के बंटवारे पर विचार-विमर्श लगभग तय माना जा रहा है, लेकिन असल पेंच चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) यानी एलजेपी (आरवी) के बीच फंसा हुआ है। एनडीए के बड़े दल जेडीयू 100 और भाजपा 105 सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं। पिछले बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में नीतीश कुमार की जेडीयू ने 115 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे और उसे 43 सीटों पर जीत हासिल हुई थी, जबकि भाजपा ने 110 सीटों पर चुनाव लड़ा और 74 सीटों पर विजय पताका फहराई। दोनों ही पार्टियों के स्ट्राइक रेट में काफी अंतर देखने को मिला, लेकिन इसके बावजूद नीतीश कुमार गठबंधन के नेता बने रहे। दिलचस्प बात ये है कि अबकी बार चिराग पासवान की पार्टी के स्ट्राइक रेट की बात ज्यादा हो रही है क्योंकि वे जिस आधार पर सीटों की मांग कर रहे हैं उससे सवाल खड़े हो रहे हैं। आइए जानते हैं जब से एलजेपी का उदय हुआ है तब से उसका बिहार विधानसभा चुनाव में प्रदर्शन कैसा रहा है।

चिराग पासवान की पार्टी ने पिछले विधानसभा चुनाव में अकेले ताल ठोकी थी। वह इस बार एनडीए का हिस्सा होगी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, चिराग 40 सीटों की मांग पर अड़े हुए हैं, जो उन्हें मिलने की संभावना कम ही दिखाई दे रही है। सूत्रों के मुताबिक, चिराग को 20 सीटें मिल सकती हैं, इससे ज्यादा भाजपा और जेडीयू देने के मूड में दिखाई नहीं दे रहे हैं क्योंकि दोनों ही पार्टियां जीतनराम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (सेक्युलर) और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम (राष्ट्रीय लोक मोर्चा) के बीच संतुलन बैठाने की कोशिश में लगी हुई हैं। चिराग के पिता रामविलास पासवान ने साल 2000 में एलजेपी का गठन किया और पहला विधानसभा चुनाव फरवरी 2005 में लड़ा। उन्होंने अपनी पार्टी का एक्स्ट्रीमली बैकवर्ड क्लास (ईडब्ल्यूएस) पर फोकस रखा। पासवान ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया और लालू प्रसाद यादव की आरजेडी के खिलाफ 178 उम्मीदवार उतारे और 29 विधानसभा सीटों पर विजय पताका फहराई। पार्टी को 12.62 फीसदी वोट मिले। पहले चुनाव में इतनी बड़ी जीत हासिल होने के बाद भी किसी भी गठबंधन को बहुमत हासिल नहीं हुआ। पासवान ने किसी भी गठबंधन को समर्थन देने से इनकार कर दिया। इसके बाद सूबे में राष्ट्रपति शासन लगा और कुछ महीनों के बाद विधानसभा भंग कर दी गई।

अक्टूबर 2005 में फिर से चुनाव कराए गए। इस बार एलजेपी ने 203 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए, लेकिन केवल 10 सीटें ही जीत सकी। पार्टी का वोट फीसदी घट गया। उसे 11.10 फीसदी वोट मिले। इसके बाद साल 2010 में पार्टी ने आरजेडी के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ा। उसने सीट शेयरिंग फॉर्मूले के तहत 75 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे, लेकिन केवल 3 सीटों पर जीत मिली और वोट फीसदी घटकर 6.74 पर आ गया। एलजेपी ने 2015 में एनडीए के नेतृत्व में 42 सीटों पर चुनाव लड़ा। इस बार उसकी एक और सीट कम हो गई। वह मात्र 2 सीटों पर सिमट गई। पार्टी का ग्राफ लगातार विधानसभा चुनाव में गिरता गया। उसका वोट फीसदी घटकर 4.83 पर गया। पार्टी की टूट के बाद चिराग पासवान ने नई पार्टी बनाई, जिसका नाम एलजेपी (आरवी) रखा और उन्होंने अपने दम पर 2020 में चुनाव लड़ा। उन्होंने एनडीए गठबंधन से नाता तोड़ा और 135 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे, लेकिन 1 सीट पर जीत हासिल हुई। हालांकि उनके वोट फीसदी में पिछले विधानसभा के मुकाबले बढ़त मिली। उन्हें कुल वोट 5.66 फीसदी मिले। साल 2020 के विधानसभा चुनावों में चिराग के एनडीए से अलग हो जाने की वजह से जेडीयू को झटका लगा था। भाजपा के स्ट्राइक रेट की तुलना में उसका प्रदर्शन खराब हो गया था। राजनीति के जानकारों का कहना था कि चिराग ने जेडीयू के खिलाफ उम्मीदवार उतारे जिससे उसे बड़ा नुकसान हुआ। 64 ऐसी सीटें थी जहां एलजेपी के उम्मीदवारों ने जीते हुए कैंडिडेट के अंतर से ज्यादा वोट पाए। अब एलजेपी दावा कर रही है कि उसने लोकसभा चुनाव 2024 में 6 फीसदी से ज्यादा वोट हासिल किए हैं, जो दर्शाता है कि पार्टी का सूबे में जनाधार बढ़ रहा है। इसी वजह से चिराग पासवान 40 सीटों की मांग कर रहे हैं।

एनडीए में सीटों के बंटवारे को लेकर फॉर्मूला तैयार है। सीटों के बंटवारे को लेकर घटक दलों में सहमति बन चुकी है। अंतिम निर्णय के लिए बड़े नेताओं की बैठक होगी। पिछले विधानसभा चुनाव के हिसाब से ही सीटों का बंटवारा होगा। हालांकि इसमें चिराग पासवान को एडजस्ट करना होगा। सूत्रों के अनुसार वे चालीस प्लस सीटें मांग रहे हैं। भाजपा सूत्रों का मानना है कि पासवान के लिए ज्यादा सीटें मांगना राजनीतिक मजबूरी है क्योंकि उन्हें अपने समर्थकों का हौंसला बनाकर रखना है। सूत्रों के मुताबिक चिराग पासवान गठबंधन के लिए जरूरी हैं और सीट बंटवारे में उनकी भावनाओं का ध्यान रखा जाएगा। हालांकि, जेडीयू चिराग को 20 से अधिक सीटें देने के पक्ष में नहीं है।

● **विनोद बक्सरी**

दो से तीन चरणों में हो सकता है चुनाव

सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार की अगुवाई में ही चुनाव लड़ा जाएगा। चुनाव जीतने पर वे ही तय करेंगे कि आगे क्या करना है। नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं हैं लेकिन इस बारे में वे ही निर्णय करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव दो से तीन चरणों में हो सकता है। दिवाली और छठ को ध्यान में रखकर चुनाव की तारीख तय होगी। बिहार विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर 2025 को समाप्त हो रहा है। लिहाजा उससे पहले चुनाव की प्रक्रिया पूरी होना आवश्यक है। इस बार दिवाली 20 अक्टूबर को है जबकि छठ पर्व 25-28 अक्टूबर के बीच मनाया जाएगा। 2020 में तीन चरणों में और 2015 में पांच चरणों में चुनाव हुआ था। 2020 में पहले चरण में 71 विधानसभा सीटों पर 28 अक्टूबर 2020 को वोटिंग कराई गई थी। वहीं दूसरे चरण में 3 नवंबर 2020 को 94 विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ था। तीसरे और आखिर चरण के लिए 7 नवंबर 2020 को 78 विधानसभा सीटों पर वोट डाले गए थे। 10 नवंबर 2020 को वोटों की गिनती हुई थी।

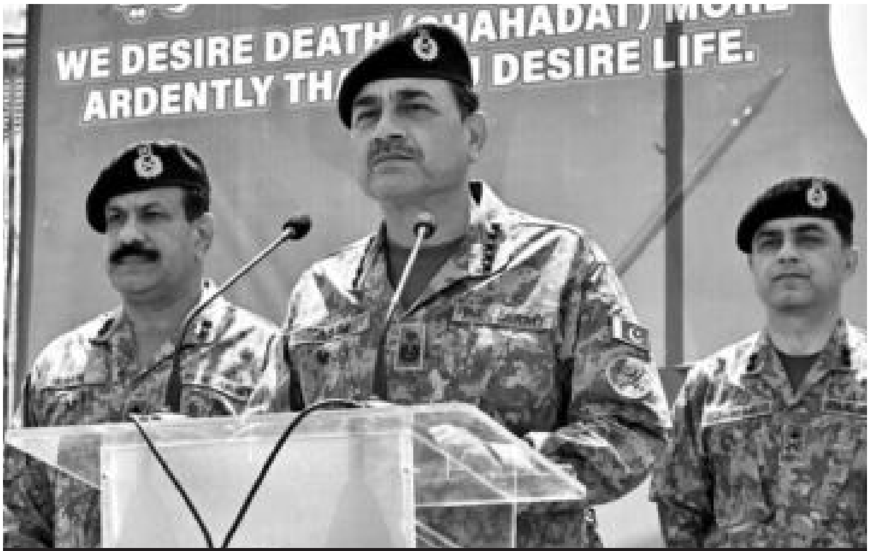

डॉलर बम के चंगुल में पाक

पाकिस्तान की सबसे बड़ी त्रासदी यह रही है कि वहां की हुकूमत की बागडोर अधिकतर फौज के हाथों में रही है। कहने को तो समय-समय पर वहां जम्हूरियत के नाम पर चुनाव होते रहे हैं, लेकिन जनता द्वारा चुनी गई सरकार के प्रधानमंत्री से कहीं अधिक शक्तिशाली वहां का फौज प्रमुख होता है। जनता के प्रतिनिधि होने के बावजूद वहां किसी सियासी हुक्मरान के लिए यह मुमकिन नहीं है कि वह आर्मी चीफ की मुखालफत कर सके। अगर किसी ने कभी दुस्साहस किया तो उसे सूली पर चढ़ा दिया गया, या जेल में डाल दिया गया, या मुल्क से बाहर निर्वासित कर दिया गया। आश्चर्य नहीं कि वहां के फौजी जनरल आने-जाने वाली सरकारों को कठपुतलियों की तरह नचाते रहते हैं। पाकिस्तान को वजूद में आए 78 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन वहां आज भी स्थितियां जस की तस हैं। आज भी पाकिस्तान के आर्मी जनरल आसिम मुनीर वहां के वजीर-ए-आजम शहबाज शरीफ से ज्यादा शक्तिशाली हैं, भले ही आधिकारिक तौर पर वहां फौज का शासन नहीं है। यह अतिश्योक्ति नहीं कि पाकिस्तान में नेशनल असेंबली नहीं, आर्मी सर्वोपरि है। अभी आर्मी के सर्वेसर्वा मुनीर साहब हैं, जिन्हें हाल में भारत के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मुंह की खाने के बावजूद फील्ड मार्शल के ओहदे से नवाजा गया है।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी यह बात छिपी नहीं है। अगर ऐसा न होता तो हाल में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को मिलने के लिए बुलाते, मुनीर को नहीं। क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी राष्ट्राध्यक्ष या राष्ट्र प्रमुख ने भारत के किसी सेनाध्यक्ष को बातचीत के लिए बुलाया हो? पाकिस्तान के संदर्भ में यह बात अटपटी नहीं लगती। यही वजह है कि मुनीर का हौसला ट्रम्प के साथ रोटियां तोड़ने के बाद बुलंद हो गया है। वे उसे पाकिस्तान को अमेरिका के खुले समर्थन के रूप में देख रहे हैं। ट्रम्प द्वारा भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाए जाने की घोषणा के बाद उन्हें शायद यह भी लगता है कि अब भारत को सबक सिखाने का मौका आ गया है। इसलिए वह अमेरिका की सरजमीं से भी भारत के खिलाफ परमाणु युद्ध की धमकियां देने से बाज नहीं आ रहे हैं। वे आधी दुनिया की तबाही की बात भी कर रहे हैं। उन्होंने फ्लोरिडा में रह रहे पाकिस्तानियों के एक समूह से कहा कि भविष्य में भारत के साथ युद्ध में उनके देश के अस्तित्व पर खतरा होता है तो वे परमाणु बम के इस्तेमाल से परहेज नहीं करेंगे, भले ही आधी दुनिया को उसकी कीमत चुकानी पड़े। उनके बयान के मायने निकाले जा रहे हैं कि बिना ट्रम्प की शह के वे ऐसा नहीं कह सकते, खासकर जब वे अमेरिका में मौजूद हों।

जो भी हो, मुनीर आज के दौर में तेजी से बदलते वैश्विक परिस्थितियों से नावाकिफ लगते हैं। वे शायद इस मुगालते में हैं कि अगर भारत के साथ पाकिस्तान का भविष्य में कभी युद्ध होता है, तो अमेरिका उनकी खुले तौर पर मदद करेगा, जैसा कभी निक्सन के दौर में हुआ था। लेकिन, दुनिया शीतयुद्ध के उस दौर से बहुत आगे निकल चुकी है, जब वह मुख्य रूप से दो भागों में बंटी हुई थी। वैसे तो जंग को किसी मसले के समाधान का बेहतर जरिया पहले भी नहीं समझा जाता था लेकिन आज के परिदृश्य में यह बिलकुल बेमानी हो गया है। अगर किसी मसले का समाधान किसी देश की सामरिक शक्ति के आधार पर होता, तो रूस बनाम यूक्रेन और ईरान बनाम इजराइल युद्ध का फैसला कुछ ही दिन में सामने आ जाता।

दरअसल आज के दौर की लड़ाईयां आर्थिक मोर्चे पर होनी है। बाजारवाद के बढ़ते दौर में दुनिया भर के बाजार नए रणक्षेत्र बन गए हैं। जिसका आधिपत्य जितने बड़े बाजार पर है, वह उतना ही बड़ा सुपर पावर है। ट्रम्प द्वारा भारत, चीन या ब्रिक्स के अन्य देशों के खिलाफ शुरू किया गया टैरिफ वॉर शायद उसी रणनीति का हिस्सा है, जिसका समाधान सामरिक हस्तक्षेप से नहीं, दो देशों के बीच की व्यापारिक नीतियों से होना है। ट्रम्प भले ही भारतीय अर्थव्यवस्था को मृत घोषित कर चुके हों, इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता है कि भारत आज आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभर चुका है।

जाहिर है, वैश्विक बाजार में पहले ब्रिक्स के गठन और फिर चीन और भारत जैसे देशों की निरंतर बेहतर होती अर्थव्यवस्था भविष्य के लिए अमेरिका जैसे सुपर पावर को गवारा नहीं हो सकता। इसलिए ट्रम्प के लिए अपने मन-मुताबिक ट्रेड डील की नीति ही हर मर्ज की दवा है। उनकी सारी हालिया कवायद भारत को अपनी शर्तों पर ट्रेड डील के लिए राजी करना है। उनके लिए भारत-पाकिस्तान के बीच पुराने मसलों के समाधान से कहीं ज्यादा अहम उनकी अपनी अर्थव्यवस्था है। पाकिस्तान के सियासी हुक्मरानों और उनके फौजी आकाओं को यह समझना पड़ेगा कि अब किसी सुपर पावर के लिए जंग जीतने के खातिर परमाणु बम से अधिक डॉलर बम मुफीद लगता है। यही नई वैश्विक व्यवस्था की हकीकत है।

● सुश्री नित्या

रेको दिक खदान पर फूल रहे मुनीर

महंगाई, कर्ज और बदहाली, पाकिस्तान पर ये शब्द सटीक बैठते हैं। अपनी कंगाली दूर करने के लिए पाक लगातार आईएमएफ से लेकर विश्व बैंक तक और अपने मित्र देशों के आगे कटोरा लिए नजर आया और उसे मदद मिली भी, लेकिन देश के आर्थिक हालात सुधरते नजर नहीं आए। लेकिन पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर को लगता है कि देश का भविष्य रेको दिक खदान में दफन है और इसके जरिए न सिर्फ बदहाल पाक की कंगाली दूर हो सकती है, बल्कि वो अमीर देशों की लिस्ट में शामिल हो सकता है। आसिम मुनीर ने इस तरह के दावे किए हैं। उन्होंने कहा कि, पाकिस्तान दुर्लभ खनिजों के भंडार पर बैठा हुआ है, हम जल्द ही अपना कर्ज कम कर देंगे और दुनिया के सबसे समृद्ध समाजों में से एक बन जाएंगे। उन्होंने बलूचिस्तान प्रांत में मौजूद रेको दिक खदान को एक खजाना बताते हुए कहा कि अगले साल से हम कम से कम 2 अरब डॉलर प्रतिवर्ष उत्पादन शुरू कर देंगे।

नौकरी का संकट

भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाने वाला शहर बेंगलूरू गगनचुंबी इमारतों, सड़कों पर दौड़ती लग्जरी कारों और तकनीकी नवाचारों के लिए मशहूर है। पुणे, गुरुग्राम और हैदराबाद जैसे शहर भी इस तकनीकी क्रांति की चमक में पीछे नहीं हैं। इन शहरों ने भारत के आईटी उद्योग की तरक्की को न सिर्फ देखा, बल्कि उसे आकार भी दिया। टीसीएस, इंफोसिस और विप्रो जैसी कंपनियों ने लाखों युवाओं को नौकरियां दीं, छोटे-बड़े शहरों से आए इंजीनियरों के सपनों को पंख दिए और भारत को वैश्विक तकनीकी नक्शे पर स्थापित किया। इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन के अनुसार, भारत का आईटी सेक्टर 283 अरब डॉलर का है, जो देश की जीडीपी में 7 प्रतिशत और निर्यात में आधे से अधिक का योगदान देता है। लेकिन जुलाई 2025 में एक खबर ने इस चमकती दुनिया को हिलाकर रख दिया। देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) ने 12,261 कर्मचारियों की छंटनी की घोषणा की। यह कंपनी के करीब 6,13,069 कर्मचारियों का 2 प्रतिशत है। यह भारतीय आईटी इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी छंटनी है। इस खबर ने न सिर्फ कर्मचारियों में दहशत पैदा की, बल्कि इंफोसिस, विप्रो और एचसीएल टेक जैसी अन्य कंपनियों में भी आशंकाओं का दौर शुरू कर दिया।

फिलहाल तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की नीतियां भारतीय आईटी सेक्टर पर दबाव बढ़ा रही हैं। अमेरिका भारत के आईटी निर्यात का सबसे बड़ा बाजार है। विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि टैरिफ का असर इस सेक्टर तक पहुंचने लगा है। ट्रम्प ने अमेरिकी कंपनियों को भारतीय विशेषज्ञों की सेवा लेने और अपने यहां ही सारा काम करने का आह्वान किया है। वर्ल्ड बैंक के अनुसार, भारत को हर साल 135 अरब डॉलर की रेमिटेंस (विदेश से देश में भेजा गया पैसा) मिलता है, जिसमें आईटी सेक्टर की बड़ी भूमिका है। यह ट्रम्प की आंख में चुभता है। वजह यह भी है कि एआई के कारण कई काम, जो पहले भारतीय इंजीनियरों को मिलते थे, अब अमेरिका में ही पूरे हो रहे हैं, जिससे कॉन्ट्रैक्टर्स की आय घटी है। हालांकि ट्रम्प टैरिफ से आईटी सेक्टर अभी अछूता है। ट्रम्प ने ट्रेड डेफिसिट और रूस से तेल आयात के नाम पर भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाया है। टीसीएस के वित्तीय नतीजे भी इस संकट की तस्वीर पेश करते हैं। अप्रैल-जून 2025 में कंपनी की आय 1.3 प्रतिशत बढ़कर 63,437 करोड़ रुपए रही, जबकि ऑर्डर बुकिंग 1.2 अरब डॉलर से घटकर 0.94 अरब डॉलर हो गई। जॉबस्पीक इंडेक्स की मानें, तो मार्च 2025 में नौकरी मिलने की दरों में 8 प्रतिशत की गिरावट आई। सालाना भी यह दर 8 प्रतिशत है। वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही में शीर्ष 6 आईटी कंपनियों ने केवल 3,847 नई नौकरियां जोड़ीं, जो पिछले तिमाही की 13,935 से 72 प्रतिशत कम है।

भारतीय ही नहीं, बल्कि वैश्विक आईटी कंपनियों में भी बदलाव दिख रहा है। 2025 में माइक्रोसॉफ्ट ने 15,000 और आईबीएम ने 8,000 कर्मचारियों को नौकरी से निकाला। ब्लूमबर्ग के मुताबिक, माइक्रोसॉफ्ट का 30 प्रतिशत कोड एआई जेनरेट करता है। छंटनी के आंकड़ें रखने वाली वाली कंपनी, ले-ऑफ डॉट एफवाईआई की रिपोर्ट के अनुसार, जनवरी से जुलाई 2025 तक 169 टेक कंपनियों ने 80,150 कर्मचारियों को निकाला, जिसमें टीसीएस की छंटनी शामिल नहीं है। 28 जुलाई 2025 को टीसीएस के सीईओ के कृतिवासन ने छंटनी की घोषणा करते हुए इसे कौशल में कमी और सीमित तैनाती अवसरों से जोड़ा। उन्होंने एआई की भूमिका को सिरे से खारिज किया और कहा कि कंपनी भविष्य के लिए तैयार हो रही है। लेकिन विशेषज्ञों की राय इससे अलग है। चर्चाएं हैं कि इस छंटनी में एआई का हाथ है, भले कंपनी इसे औपचारिक रूप से स्वीकार्य न करे। वैश्विक परामर्श फर्म, बैन एंड कंपनी की मार्च 2025 की रिपोर्ट के अनुसार, 2027 तक भारत में 23 लाख से अधिक एआई-संबंधी नौकरियां होंगी, लेकिन केवल 12 लाख कुशल पेशेवर उपलब्ध होंगे, यानी 11 लाख के पास कोई नौकरी नहीं होगी। यह आंकड़ा दर्शाता है कि एआई न सिर्फ नई नौकरियां पैदा कर रहा है, बल्कि पुराने कौशल वालों को हाशिए पर धकेल रहा है। एआई और ऑटोमेशन अब सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, डेटा एनालिसिस और मैनेजरियल कार्यों जैसे दोहराए जाने वाले कामों को तेजी से अपने कब्जे में ले रहे हैं। एआई एक्सपर्ट पूनम मसंद कहती हैं कि टीसीएस की टेस्टिंग टीमों में 36-40 प्रतिशत कर्मचारी ऐसे काम करते हैं, जो अब मशीनें संभाल रही हैं। इससे कंपनी का मुनाफा 10 प्रतिशत तक बढ़ सकता है, क्योंकि मशीनें न सिर्फ तेज हैं, बल्कि इसकी लागत भी कम आती है।

विप्रो ने हाल ही में एक वैश्विक टेक फर्म के साथ मिलकर एजेंटिक एआई सिस्टम विकसित किया, जो इंजीनियरिंग कार्यों को दोगुनी रफ्तार से पूरा करता है। नैसकॉम की रिपोर्ट बताती है कि 15 लाख से अधिक पेशेवरों को एआई और जेन-एआई में प्रशिक्षित किया गया है, लेकिन पुराने कौशल वाले कर्मचारी इस दौड़ में पीछे छूट रहे हैं।

● **ऋतेन्द्र माथुर**

उम्मीद की किरण और चुनौतियां

गुरुग्राम में एक एआई-पावर्ड हेल्थ-लाइफस्टाइल स्टार्टअप, टाइची के फाउंडर प्रद्युम्न ठाकुर कहते हैं कि भारत का आईटी सेक्टर छोटे शहरों के युवाओं के लिए सपनों का पुल रहा है। लेकिन अब दुनिया बदल रही है। पहले जो बदलाव दशकों में आते थे, वे अब चंद महीनों में हो रहे हैं। अगर भारत को वैश्विक दौड़ में आगे रहना है, तो हमें अपने युवाओं को तेजी से नए कौशल सिखाने होंगे। मर्सर मेटल इंडिया ग्रेजुएट स्किल इंडेक्स 2025 के अनुसार, केवल 42.6 प्रतिशत ग्रेजुएट नौकरी के लिए उपयुक्त हैं और 46.1 प्रतिशत ही एआई और मशीन लर्निंग रोल्स के लिए तैयार हैं। हीरो वायर्ड-गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के संयुक्त अध्ययन में पाया गया कि 77 प्रतिशत भारतीय पेशेवर के पास आधुनिक तकनीकों में कौशल की कमी है। इस चुनौती से निपटने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। टीसीएस ने करीब पांच लाख कर्मचारियों को बेसिक एआई स्किल्स और एक लाख को एडवांस्ड एआई में प्रशिक्षित किया है। इंफोसिस ने भी हाल के वर्षों में कई कर्मचारियों को उभरती तकनीकों को सीखने का प्रशिक्षण दिया। आईआईटी के पाठ्यक्रम में भी इन विषयों को जोड़ा जा रहा है। लेकिन पुराने सिस्टम से वाकिफ वरिष्ठ कर्मचारियों के लिए यह बदलाव आसान नहीं है।

आधी आबादी से ही होगा विकसित भारत का निर्माण

भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर अग्रसर है, लेकिन इस प्रगति पर अब एक खतरा मंडरा रहा है। वह है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा भारतीय निर्यात पर प्रस्तावित 50 प्रतिशत का भारी-भरकम टैरिफ। यह टैरिफ भारत से अमेरिका को होने वाले 40 अरब डॉलर के व्यापार को निशाना बनाता है। इससे देश की जीडीपी में लगभग एक प्रतिशत की कमी आ सकती है। यह टैरिफ कपड़ा और रत्न जैसे उन श्रम-प्रधान क्षेत्रों में लाखों भारतीय महिलाओं के रोजगार को अस्थिर कर सकता है, जहां उनकी भागीदारी सबसे अधिक है। लगभग 5.5 करोड़ लोगों को रोजगार देने वाले कपड़ा और रत्न जैसे क्षेत्र 50 प्रतिशत तक के निर्यात में गिरावट का सामना कर सकते हैं। इसके विपरीत चीन अपनी विनिर्माण क्षमता और अफ्रीका, यूरोप जैसे क्षेत्रों में निर्यात विविधीकरण के कारण अमेरिकी टैरिफ की चुनौती का सामना करने में सक्षम दिख रहा है, जबकि भारत इस मामले में असुरक्षित है। इसकी दो मुख्य वजहें हैं-एक तो भारत का 18 प्रतिशत निर्यात अमेरिका पर निर्भर है और दूसरा, वियतनाम जैसे प्रतिस्पर्धियों की तुलना में भारतीय उत्पाद 30-35 प्रतिशत तक महंगे हैं, जो एक बड़ी चुनौती है। ऐसे संकट के समय में महात्मा गांधी के शब्द प्रासंगिक लगते हैं- किसी राष्ट्र की ताकत उसकी महिलाओं में निहित होती है। ऐसे में आधी आबादी को आर्थिक रूप से सशक्त बनाकर हम भी इस चुनौती से पार पा सकते हैं।

भारत में महिला श्रम बल की बेहद कम भागीदारी है, जो 37 प्रतिशत से 41.7 प्रतिशत के बीच बनी हुई है। जबकि वैश्विक औसत और चीन की दर लगभग 60 प्रतिशत है। चीन, जापान और अमेरिका जैसे देश इस बात का प्रमाण हैं कि जब महिलाएं अर्थव्यवस्था में सक्रिय भूमिका निभाती हैं, तो समावेशी विकास संभव हो पाता है। जापान ने वुमेनामिक्स रणनीति अपनाकर महिला भागीदारी को 74 प्रतिशत तक पहुंचाया है। अमेरिका की अर्थव्यवस्था को मजबूती भी महिलाओं की भागीदारी से मिली है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का अनुमान है कि इस लैंगिक अंतर को समाप्त करने से भारत 2025 तक अपनी जीडीपी में 27 प्रतिशत यानी 770 अरब डॉलर की वृद्धि कर सकता है। 2047 तक यह आंकड़ा 14 लाख करोड़ डॉलर तक पहुंच सकता है, पर इसके रास्ते में सांस्कृतिक रूढ़िवादिता, नीतिगत निष्क्रियता और रोजगार के लिए प्रणालीगत बाधाएं आड़े आ सकती हैं। आर्थिकी में महिलाओं की कम भागीदारी और अब टैरिफ का खतरा-देश की आर्थिक क्षमता को और कमजोर कर सकता है।

भारत इस समय अपने जनसांख्यिकीय लाभांश के शिखर पर है। यह एक ऐसा दौर है जब काम करने वाली आबादी आश्रितों की तुलना में बहुत अधिक है। यह अवसर सीमित समय के लिए है और 2045 तक समाप्त हो जाएगा। चीन, जापान और अमेरिका जैसे देश इसी अवसर का लाभ उठाकर विकसित हुए हैं। भारत को इस क्षणिक अवसर को स्थायी समृद्धि में बदलने के लिए तुरंत कदम उठाने होंगे। इसका एकमात्र रास्ता महिलाओं को पूरी तरह से कार्यबल में शामिल करना है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी में थोड़ी वृद्धि हुई है, लेकिन यह ज्यादातर अवैतनिक और पारिवारिक कार्यों तक सीमित है, जिसकी उत्पादकता कम है। दूसरी ओर, शहरी भारत में महिला श्रम बल भागीदारी स्थिर बनी हुई है। इसके अलावा असुरक्षित सार्वजनिक परिवहन, स्वच्छता की कमी और अवैतनिक देखभाल कार्य का भारी बोझ महिलाओं को शिक्षा और रोजगार दोनों से दूर करता है।

आर्थिकी में महिलाओं की कम भागीदारी विकास पर नकारात्मक असर डाल रही है। इसे बदलना होगा। कर्नाटक की शक्ति योजना, जो महिलाओं को मुफ्त सार्वजनिक बस यात्रा प्रदान करती है, एक बेहतरीन उदाहरण है। 2023 में इसके लांच के बाद से महिला यात्रियों की संख्या में 40 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है। इस योजना ने महिलाओं की काम, शिक्षा और उद्यम के लिए गतिशीलता को बढ़ाया है, खासकर ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में। इससे महिलाओं की नौकरी तक बेहतर पहुंच बनी है, पुरुष परिवार के सदस्यों पर निर्भरता कम हुई है और उनकी स्वायत्तता बढ़ी है। इसी तरह राजस्थान की इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना ने 4 करोड़ से अधिक मानव-दिवस का काम सृजित किया है, जिसमें लगभग 65 प्रतिशत नौकरियां महिलाओं को मिली हैं। इस कार्यक्रम के तहत स्वच्छता, पौधरोपण और देखभाल जैसे कार्यों ने उन महिलाओं को भी कार्यबल में प्रवेश करने में सक्षम बनाया है, जो पहले घरेलू जिम्मेदारियों के कारण ऐसा नहीं कर पाती थीं। अर्बन कंपनी जैसे अग्रणी गिग प्लेटफॉर्म ने 45,000 से अधिक महिला सेवा प्रदाताओं को जोड़ा है, जो प्रतिमाह 18,000 से 25,000 रुपए तक कमाती हैं। इन महिलाओं को दुर्घटना बीमा, मातृत्व लाभ और कौशल विकास जैसी सुविधाएं भी मिलती हैं।

● **ज्योत्सना अनूप यादव**

आधी आबादी को काम के बजाय आराम पसंद

अब देखना यह है कि विकसित भारत का सपना दिखाने वाले लोग क्या देश में काम की संस्कृति और राष्ट्र निर्माण के लिए अपने कर्त्तव्य का पालन कर रहे हैं। अभी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक सर्वेक्षण रपट आई है, जिसमें विभिन्न देशों की मेहनत वृत्ति या काम करने की अवस्था का आंकलन किया गया है। इसमें कहा गया है कि भारत में कम से कम आधी आबादी काम के बजाय आराम करना पसंद करती है, क्योंकि मुफ्तखोरी और अनुकंपा संस्कृति का चलन बढ़ रहा है। एक और बात सामने आई है कि भारत में बहुत सारे लोगों की मेहनत को श्रेय या पारिश्रमिक ही नहीं मिलता है। जैसे महिलाएं इस देश की आबादी का करीब आधा हिस्सा हैं। इनमें से ज्यादातर की मेहनत को घर का सामान्य कामकाज ही समझा जाता है। इस काम के लिए उन्हें अलग से कोई नियत वेतन नहीं मिलता। ये महिलाएं दिनभर काम में व्यस्त रहने के बावजूद अपने लिए कोई अलग आर्थिक संबल प्राप्त नहीं कर पातीं। इसमें संदेह नहीं कि आज भी जो बेकारी के आंकड़े सामने आते हैं, उनमें ग्रामीण बेरोजगारी के बाद शहरी बेरोजगारी में भी वास्तविक अर्थों में कोई कमी होती नजर नहीं आ रही। चाहे औपचारिक घोषणाओं में हम यह कहते रहें कि हमने हजारों खाली पद भर लिए हैं, लेकिन प्रश्न यह नहीं है कि हमने कितने खाली पद भरे, बल्कि देश की युवा संतति के कामकाज के लिए कितनी नई कार्य व्यवस्थाएं सृजित की गईं। देश के वार्षिक बजट के आय-व्यय ब्यौरे में हम कितनी उन नई योजनाओं की घोषणा कर पाए, जिनमें युवा पीढ़ी को काम मिले।

गणेशोत्सव पर 28,000 करोड़ का कारोबार

गणेश चतुर्थी, भारत का प्रमुख हिंदू त्योहार, सिर्फ आस्था और भक्ति का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह एक विशाल आर्थिक गतिविधि का केंद्र भी है। यह महोत्सव 10 दिनों तक चलता है और इस दौरान लोग घर-घर गणपति बप्पा की स्थापना करते हैं और विशाल पंडाल में भी बप्पा की बड़ी-बड़ी मूर्तियां बिठाते हैं। गणेश चतुर्थी के साथ ही 10 दिनों तक चलने वाले इस उत्सव की शुरुआत हो चुकी है। कंफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के अनुसार, इस वर्ष गणेश उत्सव से लगभग 28,000 करोड़ रुपए का कारोबार होने का अनुमान है। इसमें पंडालों की सजावट (लगभग 10,000 करोड़), मिठाइयां (2,000 करोड़), कैटरिंग (3,000 करोड़), और पर्यटन (2,000 करोड़) सहित कई क्षेत्र शामिल हैं। रिटेल सेल्स में भी इस दौरान बढ़ोतरी देखने को मिलती है (लगभग 3,000 करोड़)। इवेंट मैनेजमेंट कंपनियां भी इस त्योहार से 5,000 करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार करती हैं। गणेश प्रतिमाओं का कारोबार भी 500 करोड़ से अधिक का है, जिसमें पारंपरिक मिट्टी की मूर्तियों की बढ़ती लोकप्रियता पर्यावरण संरक्षण और स्थानीय कारीगरों को लाभ पहुंचा रही हैं।

मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र में गणेशोत्सव की धूम है। 27 अगस्त से शुरु हुए गणेशोत्सव में लगे लोगों की भीड़ बाजार में देखते ही बनती है। गणेशोत्सव में व्यापारियों की तिजोरी भरने वाली है। इसके चलते व्यापार को एक बहुत बड़ा प्रोत्साहन मिलता है। इस वर्ष व्यापारियों ने विदेशी उत्पादों को पूरी तरह से त्याग कर स्वदेशी वस्तुओं को प्राथमिकता दी है। और ग्राहकों को भी स्वदेशी वस्तुएं इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। गणेश चतुर्थी से महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मप्र, तमिलनाडु और गोवा जैसे राज्यों में बड़ी आर्थिक गतिविधियां होती हैं। गणेश चतुर्थी पर इस बार देशभर में लगभग 21 लाख गणेश पंडाल लगाए जा रहे हैं। महाराष्ट्र में सबसे अधिक करीब 7 लाख पंडाल, कर्नाटक में 5 लाख, आंध्रप्रदेश, तेलंगाना और मप्र में 2-2 लाख, गुजरात में 1 लाख और अन्य राज्यों में 2 लाख से अधिक पंडाल स्थापित किए जा रहे हैं। अगर प्रत्येक पंडाल पर कम-से-कम 50,000 रुपए का खर्च मानें, तो सिर्फ पंडाल सजावट, मूर्ति स्थापना और ध्वनि व्यवस्था पर ही लगभग 10,500 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। गणेश प्रतिमाओं का व्यापार 600 करोड़ रुपए से अधिक का अनुमानित है। पूजा सामग्री फूल, माला, धूप, नारियल, फल आदि की बिक्री लगभग 500 करोड़ रुपए तक पहुंच सकती है। गणपति को प्रिय मोदक और अन्य मिठाइयों की बिक्री इस वर्ष 2,000 करोड़ रुपए से अधिक हो सकती है। वहीं कैटरिंग और स्नैक्स उद्योग को 3,000 करोड़ रुपए के कारोबार की उम्मीद है।

पर्यटन और परिवहन (बस, टैक्सी, ट्रेन, होटल) से 2,000 करोड़ रुपए से अधिक का व्यापार हो सकता है। कपड़े, सजावट, गिफ्ट जैसी रिटेल वस्तुएं 3,000 करोड़ रुपए तक बिक सकती हैं। इवेंट मैनेजमेंट सेवाएं (सुरक्षा, भीड़ प्रबंधन, लॉजिस्टिक्स आदि) अब आधुनिक पंडालों का हिस्सा बन चुकी हैं, जिससे 5,000 करोड़ रुपए का कारोबार होने का अनुमान है। वहीं, आभूषणों (सोना-चांदी) की खरीदारी, भेंट में चांदी की मूर्तियां व सिक्कों से 1,000 करोड़ रुपए का व्यापार संभव है। कैट के राष्ट्रीय मंत्री एवं अखिल भारतीय खाद्य तेल व्यापारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष शंकर ठक्कर ने बताया कि इस वर्ष 28,000 करोड़ से अधिक का व्यापार होने का अनुमान है। इस वर्ष व्यापारियों ने विदेशी उत्पादों को पूरी तरह से त्याग कर स्वदेशी वस्तुओं को प्राथमिकता दी है। ग्राहकों को भी स्वदेशी वस्तुएं इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। कैट के राष्ट्रीय महामंत्री एवं दिल्ली चांदनी चौक से भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने बताया कि गणेश चतुर्थी से महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, आंध्रप्रदेश, तेलंगाना, मप्र, तमिलनाडु और गोवा जैसे राज्यों में बड़ी आर्थिक गतिविधियां होती हैं, जो भारतीय सनातन अर्थव्यवस्था के महत्व को दर्शाती हैं। कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीसी भरतिया ने कहा कि इस साल पूरे देश में करीब 2 लाख से अधिक गणेश पंडाल स्थापित किए जाएंगे।

बढ़ते कच्चे मालों के दामों के करण गणेश प्रतिमाओं का व्यापार 600 करोड़ से अधिक होता है। पूजा सामग्री जिनमें खासकर फूल, माला, नारियल, फल, धूप आदि पूजन लगभग 500 करोड़ से अधिक का होता है। गणपति बप्पा को प्रिय मोदक के लड्डू व अन्य मिठाईयां 2,000 करोड़ से अधिक की बिक्री होती है। पंडालों में प्रतिदिन कोई ना कोई कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है जिसके लिए कैटरिंग व स्नैक्स का लगभग 3,000 करोड़ कारोबार होता है। पर्यटन व परिवहन में 2,000 करोड़ से अधिक का व्यापार होता है। रिटेल एवं त्योहार संबंधित वस्तुओं का 3,000 करोड़ तक व्यापार होता है। गणपति पंडाल अब आधुनिक हो चुके हैं। इसके लिए इवेंट मैनेजमेंट सेवा ली जाती है, जिससे लगभग 5,000 करोड़ का कारोबार होता है। कचरा प्रबंधन और पर्यावरण सेवाओं में बढ़ोतरी, जैसे कृत्रिम टैंक में विसर्जन, सजावट सामग्री का पुनर्चक्रण के लिए भी बड़ा खर्च होता है। इसके अलावा श्रद्धालु गणेशोत्सव पर सोना-चांदी के आभूषणों खरीद कर सार्वजनिक पंडालों में दान देते हैं। वहीं महाराष्ट्र में सभी लोग एक-दूसरे के घरों में गणपति बप्पा के दर्शन के लिए जाते हैं जिसमें भेंट के तौर पर गणेशजी की चांदी की मूर्ति, चांदी के सिक्के भी दिए जाते हैं जिससे आभूषणों का व्यापार करीब 1000 करोड़ के आसपास का होता है।

● ओम

करोड़ों का होता है बीमा

पिछले कुछ वर्षों में धार्मिक स्थलों पर भीड़ बढ़ने से कई हादसे हुए जिसके चलते अब गणेश मंडलों का बीमा शुरू हो गया है। वहीं कई पंडालों में गणपति की मूर्तियों पर लाखों रुपए के गहने भी चढ़े होते हैं ऐसे में किसी अनहोनी की आशंका में गणपति मंडल अपने पंडालों का बीमा भी करते हैं, जिससे बीमा कंपनियों का खूब कारोबार होता है। इस वर्ष 1000 करोड़ से अधिक का बीमा कारोबार होने का अनुमान है। शंकर ठक्कर ने कहा कि यह त्योहारों का सीजन रक्षाबंधन से शुरू होकर गणेश चतुर्थी, नवरात्र, दशहरा, करवा चौथ, दिवाली, छठ पूजा और विवाह मौसम तक चलता है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था को एक गतिशील बहाव की ओर ले जाता है। जो दर्शाता है कि देश में आज भी सनातन अर्थव्यवस्था की भूमिका काफी मजबूत बनी हुई है।

अधूरे सपने

सुबह जब उसने फेसबुक खोला तो सामने आई पोस्ट देखकर हतप्रभ हो गया। ऐसा कैसे हो गया? अभी कल ही तो उससे बात हुई थी और उसने उसे अपने आने का भरोसा भी दिया था। कितना खुश थी वो। लेकिन अब जैसे एक झटके से सबकुछ बिखर और उसके सपने परवान चढ़ने से पहले ही दम तोड़ गए।

आभासी दुनिया से एक-दूसरे से पहचान को दोनों ही रिश्तों के सूत्र में बांधने के उत्सुक थे। दोनों के परिवार वाले भी सहमत थे।

दो दिन बाद ही रक्षाबंधन पर दोनों पहली बार मिलने वाले थे। मां की सहमति से वह खुद उसके घर जाने को लेकर उत्सुक था। मां ने उसके लिए खूबसूरत सी साड़ी मंगा रखी थी। पहली बार अपनी कलाई पर बंधने वाले धागों लेकर वह बच्चों की तरह उतावला हो रहा था।

पोस्ट देखकर कुछ देर तो वह कुछ सोच ही नहीं पाया, फिर हिम्मत करके उसके नंबर पर फोन किया। फोन किया, तो उसके पापा ने फोन रिसीव किया और रुंधे गले से बताया- सॉरी बेटा! तेरी बहन तेरा सपना अधूरा छोड़ गई। आगे वह कुछ बोल न सके। उसके मुंह से बोल तक न निकला। उसने अपनी कलाई को गौर से देखा और अपने दुर्भाग्य पर रो पड़ा। मां ने ढांढस बंधाया और कारण पूछा तो उसने पूरी बात बताई। फिर मां ने उसे उसके घर चलने को कहा।

हिम्मत करके अपने अधूरे सपनों को समेटते हुए उठा और मां को लेकर उसके घर की ओर चल पड़ा, जिससे वह कभी मिला तक नहीं था। पर ईश्वर को उनको सपनों को पूरा होते देखना शायद पसंद नहीं था, तभी तो एक सड़क दुर्घटना में उसको मुंहबोली बहन को छीनकर अधूरे सपने पर अपने निर्णय को थोप दिया।

– सुधीर श्रीवास्तव

चबूतरा

ऑफिसर, यह नोटिस आपने भेजा है!

जी, कोई शक!

क्यों भेजा?

यह तीसरा व आखिरी नोटिस है, जो यह सूचित करता है कि आप अपनी बिना लाइसेंस लिए बनाई गई शराब की फैक्ट्री को, जो सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बनी है, को कल दोपहर तक बंद करवाकर तुड़वा दें!

यदि ना तुडवाऊंतो?

तो कल दोपहर 12 बजे के बाद, उस पर बुल्डोजर चलवा दिया जाएगा!

ऑफिसर, काम अपना भी चलता रहे और आपका भी। इसीलिए कल आपको अटैची भरकर पत्रं पुष्पं भिजवाए थे। पर आपने वापिस कर दिए। यदि कम थे, तो बताते और भिजवा देते!

माफ कीजिए यह चबूतरा बिकाऊ नहीं है!

ऑफिसर, जो चबूतरा हम खरीद नहीं पाते, उसे अपने रास्ते से हटवा देते हैं!

ठीक है, तो कोशिश करके देख लो! पर कल दोपहर 12 बजे से पहले तक, वरना...!

– विष्णु सक्सेना

...तब गीत बुनूंगा

भावों के ताने-बाने
कुछ उलझ गए हैं,
थोड़ा ठहरो, सुलझा लूं,
तब गीत बुनूंगा।।
आंखें नम हैं,
मन का हर कोना घायल है।
सुधियों की गलियों में
भारी कोलाहल है।
सब अच्छा करके भी
जब निंदा ही पाई,
यही अंत में स्वीकारा,
प्रारब्ध प्रबल है।
मुझे पता है,
शूल बिछे हैं सच के पथ में,
पर जब भी चुनना होगा,
पथ यही चुनूंगा।।
हर कोई अपना
बनकर ही छलने आया।
मीठी-मीठी बातें कर
विश्वास जमाया।
रहा एक सा ही अनुभव
सारे अपनों से,
काम हुआ तो फिर न
किसी ने मुख दिखलाया।
समझ आ गया जब,
ऐसी ही है यह दुनिया,
अब ना पछताऊंगा,
अब ना शीश धुनूंगा।।
जो भी मिलता है,
सलाह देकर जाता है।
हमें हमारे ही निर्णय से
भटकाता है।
इतने-इतने मार्ग
बता देती है दुनिया,
भ्रमित हुआ मन खुद को
उलझन में पाता है।
जितनी राय मिली
उतनी ही ठोकर खाई,
सोच लिया है अब न
किसी की बात सुनूंगा।।

– बृज राज किशोर 'राहगीर'

सिराज बन गए भारत के ताज

संघर्ष, मेहनत और आत्मविश्वास का प्रतीक

आज की तारीख में मोहम्मद सिराज सिर्फ एक तेज गेंदबाज का नाम नहीं है। बल्कि यह भारतीय क्रिकेट में संघर्ष, मेहनत और आत्मविश्वास का प्रतीक बन गए हैं। 2025 की इंग्लैंड सीरीज ने यह साबित कर दिया कि वे अब टीम के सहायक नहीं, बल्कि लीडर की भूमिका में हैं। आने वाले वर्षों में उनकी और बुमराह की जोड़ी भारतीय तेज गेंदबाजी का चेहरा बन सकती है। उनकी कहानी उन सभी युवाओं के लिए प्रेरणा है, जो कठिन परिस्थितियों में भी अपने सपनों को पूरा करने का हौसला रखते हैं। सिराज की सूरज सी चमक अभी और तेज होना बाकी है। उनके प्रशंसक इसके इंतजार में हैं।

भारत और इंग्लैंड के बीच हाल ही में समाप्त हुई एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी न केवल शुभमन गिल, जो रूट और बेन स्टोक्स के प्रदर्शन के लिए याद की जाएगी, बल्कि मोहम्मद सिराज के नाम से भी जानी जाएगी। इस पांच टेस्ट मैचों की सीरीज में सिराज ने शानदार गेंदबाजी से क्रिकेट प्रेमियों का ध्यान अपनी ओर खींचा। खास तौर पर पांचवें टेस्ट में, जहां भारत ने रोमांचक मुकाबले में इंग्लैंड को 6 रन से हराकर सीरीज 2-2 से बराबर की। इसमें सिराज ने 9 विकेट लेकर इतिहास रचा। इस शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच का सम्मान भी मिला। पूरी सीरीज में उन्होंने 23 विकेट लिए, जो सबसे अधिक रहे। शुभमन गिल के बाद वे टीम के दूसरे बड़े हीरो के रूप में उभरे। इसी सीरीज के दौरान उन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपने 200 विकेट भी पूरे किए। यह उनके करियर का एक और बड़ा माइलस्टोन है। ओवल टेस्ट में उनकी गेंदबाजी ने मैच का रुख ही पलट दिया। उन्होंने दूसरी पारी में लगभग अकेले अपने दम पर इंग्लैंड की बल्लेबाजी क्रम को ध्वस्त कर दिया। फ्लैट पिच हो या चुनौतीपूर्ण ट्रैक, उन्होंने हर बार अपनी काबिलियत साबित की। फिर भी, कई विशेषज्ञों और प्रशंसकों का मानना है कि उन्हें उनके योगदान को वैसा श्रेय नहीं मिला, जिसके वे हकदार हैं।

सिराज का जन्म 13 मार्च 1994 को हैदराबाद, तेलंगाना में हुआ था। साधारण परिवार से आने वाले सिराज के लिए आर्थिक तंगी हमेशा चुनौती रही। उनके पिता मिर्जा मोहम्मद गौस ऑटो रिक्शा चलाकर परिवार का गुजारा करते थे। मां शबाना बेगम गृहिणी थीं। सिराज के पास न सही जूते थे, न बस का किराया। उन्होंने टेनिस बॉल से गेंदबाजी की शुरुआत की। 2016-17 की रणजी ट्रॉफी में 41 विकेट लेकर वे पहली बार सुर्खियों में आए। सिराज के लिए हमेशा कहा जाता है कि वे डोमेस्टिक क्रिकेट की भट्टी में पके गेंदबाज हैं। इसी संघर्ष ने उन्हें आईपीएल का टिकट भी दिलाया। आईपीएल ने उनके करियर को नया आयाम दिया। 2017 में सनराइजर्स हैदराबाद से शुरुआत करने के बाद वे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलूरू का अहम हिस्सा बने। गेंदबाजी में उनके अनूठे प्रदर्शन ने उन्हें फ्रेंचाइजी क्रिकेट में भी अलग पहचान दिलाई। सिराज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलूरू के लिए कई साल अहम भूमिका निभाते रहे। 2025 की नीलामी में गुजरात टाइटंस ने उन्हें 12.25 करोड़ रुपए में खरीदा, जो उनकी लोकप्रियता और प्रभाव को दर्शाता है। विश्व की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग में उन्होंने अब तक 109 विकेट चटकाए हैं। आईपीएल के इसी अनुभव ने उन्हें अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में आत्मविश्वास और आक्रामकता दी। सिराज ने 2017 में टी20 क्रिकेट से ही भारतीय टीम के लिए डेब्यू किया था।

सिराज के करियर में विराट कोहली का समर्थन बहुत महत्वपूर्ण रहा है। 2020-21 के ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जब उन्होंने टेस्ट डेब्यू किया, उस समय कोहली ने उनका हर कदम पर साथ दिया और उन्हें मौके दिए। सिराज कई बार कह चुके हैं कि कोहली ने मुश्किल वक्त में उनका साथ दिया। कोहली ने ही उन्हें पिच पर आक्रामकता बनाए रखने और बाहर के दबाव को नजरअंदाज करने की सलाह भी दी। टीम में एक वरिष्ठ खिलाड़ी का इतना भरोसा उन्हें मानसिक रूप से मजबूत बनाता रहा। सिराज का टेम्परामेंट इस बात से भी पता चलता है कि 2020 में पिता के निधन के बावजूद उन्होंने ऑस्ट्रेलिया दौरे में शानदार प्रदर्शन किया। यही उनके संकल्प और मानसिक मजबूती की मिसाल है।

मोहम्मद सिराज गाबा की उस प्रसिद्ध जीत में भी शामिल थे, जब भारत ने ऑस्ट्रेलिया की सरजमीं पर उनका गुरूर तोड़कर लगातार दूसरी सीरीज अपने नाम की थी। 2023 विश्वकप में भी उन्होंने 11 विकेट चटकाए थे। इसके बाद, 2024 में जब भारत ने टी20 विश्व जीतकर आईसीसी ट्रॉफी का कई साल का सूखा खत्म किया, तब भी वे टीम के महत्वपूर्ण अंग थे। हालांकि, बीच में ऐसे मौके भी आए, जब सिराज की गेंदबाजी पर सवाल उठे। उन्हें इस साल आईपीएल से पहले आरसीबी ने अपने खेमे से अलग कर दिया। सबसे ताजा उदाहरण इसी साल चैंपियंस ट्रॉफी का है, जब उन्हें भारतीय टीम में नहीं चुना गया। तब भारतीय वनडे कप्तान रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलकर कहा था कि सिराज पुरानी गेंद के साथ उतने प्रभावी नहीं हैं। इसके बाद, सिराज ने जो किया वो अपने आप में मिसाल है। सिराज न केवल आईपीएल में गुजरात के लिए शानदार अवतार में दिखे, बल्कि इस बार इंग्लैंड दौरे पर भी उन्होंने खुद को कई पायदान बढ़ाकर बता दिया कि उन्हें गलतियों से सीखना आता है।

इस सीरीज में जसप्रीत बुमराह की गैरमौजूदगी ने सिराज को अतिरिक्त जिम्मेदारी दी। बुमराह वर्कलोड मैनेजमेंट और चोट के कारण केवल तीन मैच खेल पाए, जबकि सिराज ने पांचों टेस्ट खेले और पूरी आक्रमकता के साथ नेतृत्व किया। बुमराह के बिना खेले गए मैचों में उनके आंकड़े और भी निखरे। उनके औसत और स्ट्राइक रेट, दोनों में सुधार दिखा। गेंदबाजी की दिशा, लगातार अनुशासित बने रहने, तेज गेंदों के साथ सटीक स्विंग और नई गेंद के साथ बेहतर मूवमेंट ने उन्हें इंग्लैंड की बल्लेबाजी के लिए सबसे बड़ा खतरा बना दिया। कई मौकों पर, खासकर निर्णायक पलों में, उन्होंने मैच को भारत की ओर मोड़ने का काम किया। विदेशी पिचों पर उनका प्रदर्शन बताता है कि वे सिर्फ घर में ही नहीं, बल्कि चुनौतीपूर्ण बाहरी स्थितियों में भी उतने ही प्रभावी हैं।

● **आशीष नेमा**

जब अमिताभ को शशि कपूर से छोटा रोल मिलने पर भड़कीं जया बच्चन... बोलीं-

मनोज कुमार ने मेरे पति की प्रतिभा को बर्बाद कर दिया

अमिताभ बच्चन आज बॉलीवुड के महानायक हैं, लेकिन यहां तक का सफर उनके लिए बिलकुल भी आसान नहीं था। उनके सुनहरे दौर से जुड़ी कई कहानियां आज भी फैंस को रोमांचित करती हैं। इन्हीं में से एक घटना साल 1974 की है। किस्सा उस कल्ट क्लासिक फिल्म का है, जिसमें अमिताभ बच्चन के साथ शशि कपूर और जीनत अमान साथ नजर आए थे। फिल्म में बिग बी ने सपोर्टिंग रोल प्ले किया था, जिसको लेकर जया बच्चन बिलकुल भी खुश नहीं थीं।

एक दौर था, जब अमिताभ बच्चन के साथ कोई हसीना काम करने के लिए राजी नहीं थी तो जया ने उनका साथ दिया और ये साबित किया कि वो क्यों खास हैं। उन्होंने अमिताभ के लिए एक बार मशहूर एक्टर-निर्देशक मनोज कुमार से पंगा ले लिया था।

दरअसल, मनोज कुमार की फिल्म रोटी कपड़ा और मकान बना रहे थे। मनोज कुमार के निर्देशन में बनी इस मल्टीस्टारर फिल्म में मनोज कुमार, शशि कपूर, अमिताभ बच्चन, जीनत अमान, मौसमी चटर्जी और अरुणा ईरानी जैसे सितारे शामिल थे। फिल्म बेरोजगारी, गरीबी और सामाजिक असमानता जैसे मुद्दों पर आधारित थी। फिल्म में जहां शशि कपूर को एक बड़े हीरो का किरदार दिया गया था, वहीं उस दौर में करियर बना रहे अमिताभ बच्चन को फिल्म में छोटा-सा रोल मिला था। फिल्म रोटी कपड़ा और मकान ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया। 1.28 करोड़ रुपए के बजट पर बनी इस फिल्म ने 7.50 करोड़ रुपए की कमाई की थी, जिसने इसे उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बनाया बल्कि इसे मनोज कुमार की सबसे बड़ी बॉक्स ऑफिस हिट्स में भी गिना जाता है। कहा जाता है कि अमिताभ का सेट पर आना कई लोगों को पसंद नहीं आता था। इसलिए लोग उन्हें अक्सर ये अभास कराते थे कि वो एक फ्लॉप हीरो हैं और जया आते ही सिनेमा में छा गईं।

जया बच्चन को क्यों लगी ठेस?... *दरअसल, जया बच्चन और अमिताभ बच्चन का विवाह 3 जून 1973 को हुआ था। शादी के महज एक साल बाद, जया ने अपने पति के सीमित स्क्रीन टाइम को लेकर नाराजगी जताई। आईएमडीबी की एक रिपोर्ट के मुताबिक, जया बच्चन ने एक मीडिया इंटरव्यू में कहा था, मनोज कुमार ने फिल्म में अमिताभ बच्चन की प्रतिभा को बर्बाद कर दिया। उनका मानना था कि अमिताभ जैसे एक्टर, जिनमें इतनी क्षमता है, उन्हें सहायक भूमिकाओं में नहीं डाला जाना चाहिए। 1969 में सात हिंदुस्तानी से डेब्यू करने के बाद, कई असफल फिल्मों के बावजूद, जंजीर ने उन्हें पहचान दिलाई थी। लेकिन रोटी कपड़ा और मकान में उन्हें सहायक किरदार में देखकर जया को यह बर्दाश्त नहीं हुआ।*

वो अभिनेत्री, जिसने गोविंदा संग काम करने से कर दिया था मना, डूबने की कगार पर पहुंचा करियर

माधुरी दीक्षित 90 के दशक की टॉप हीरोइनों में से एक रही हैं। उन्होंने अपने करियर में लगभग सभी बड़े सितारों के साथ काम किया है। मगर एक बार उन्होंने गोविंदा के साथ फिल्म में काम करने से मना कर दिया था, क्योंकि उस वक्त एक्टर इंडस्ट्री में नए थे। यह खुलासा हाल ही में फिल्ममेकर पहलाज निहलानी ने किया। पहलाज निहलानी ने फिल्म का नाम सीधे तौर पर नहीं लिया, लेकिन उन्होंने इशारा किया कि उन्होंने माधुरी दीक्षित को गोविंदा के अपोजिट अपनी फिल्म इल्जाम में लीड रोल ऑफर किया था, जो गोविंदा के करियर की दूसरी फिल्म होने वाली थी। लेकिन माधुरी ने उनके साथ काम करने से इनकार कर दिया। पहलाज निहलानी ने बताया, मैंने माधुरी की जगह नीलम कोठारी को लिया। उस वक्त माधुरी की सारी फिल्में या तो बंद हो रही थीं या फ्लॉप हो रही थीं। लेकिन मेरी तीनों फिल्में उसी समय गोल्डन जुबली साबित हुईं। हालात जल्द ही बदल गए और माधुरी के सेक्रेटरी ने निहलानी से एक फिल्म का मुहूर्त रखने की रिक्वेस्ट भी की।

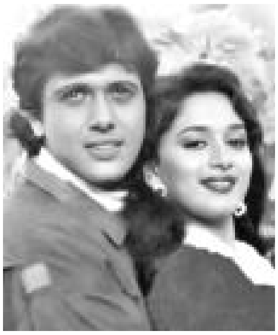

14 की उम्र में ऋषि कपूर की हीरोइन बनी स्टार खुद मारी पैर पर कुल्हाड़ी, फिर ताउम्र पछताई

वो बला की खूबसूरत एक्ट्रेस, जिसने अपने करियर में हर बड़े स्टार के साथ काम किया। महज 14 साल की उम्र में ये एक्ट्रेस इंडस्ट्री में छा गई थीं। लेकिन करियर के पीक पर सलमान, सनी देओल की फिल्में रिजेक्ट कर डायरेक्टर संग शादी रचाकर एक्टिंग को अलविदा कह दिया। 80 और 90 के दौर की जानी-मानी वो खूबसूरत एक्ट्रेस कोई और नहीं, सोनम खान हैं। अपनी डेब्यू फिल्म विजय से ही वह रातोंरात स्टार बन गई थीं। अपने करियर में उन्होंने ऋषि कपूर, अमिताभ बच्चन समेत हर बड़े स्टार के साथ काम किया। ऋषि कपूर के साथ तो वह अजूबा में भी नजर आई थीं। सोनम ने अपने करियर में इसके बाद कई हिट फिल्में दीं। इसके बाद वह फिल्म त्रिदेव में भी नजर आईं। इसी दौरान वह फिल्म के डायरेक्टर राजीव राय संग प्यार में पड़ गई। फिर राजीव और सोनम ने कुछ समय डेटिंग करने के बाद 1991 में शादी कर ली। महज 20 की उम्र में वह प्रेग्नेंट हो गई थीं। इसके बाद राजीव और सोनम विदेश जा बसे और सोनम को इंडस्ट्री को अलविदा कहना पड़ा।

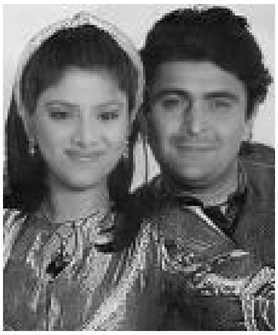

किट्टी देवी की जय...

किट्टी देवी तेरी सदा ही जय हो। ऐसा मुझे दे वरदान तेरी पार्टी में खेले जाने वाले हर गेम में मेरी ही सदा विजय हो। किट्टी देवी तेरा भला हो, तेरी पार्टी में जाते ही हम मिडिल क्लास महिलाओं को एकदम से ही स्वर्ग जैसा अनुभव होने लगता है। जब से तू सोसाइटी में आई है हम मिडिल क्लास महिलाओं की तो जैसे किस्मत ही बदल गई है।

तेरे दरबार में पहुंचकर हमें ऐसा लगने लगता है जैसे हम इंद्र के दरबार में पहुंच गए हैं और सबसे अच्छी बात तो यह होती है कि वहां अप्सराएं भी हम सभी महिलाएं ही होती है। शादी पार्टियां भला रोज-रोज कहां होती हैं, इसी बहाने हमें महीने में कम से कम एक या दो दिन अपने गहने कपड़ों के प्रदर्शन करने का भरपूर मौका तो तुम हमें दे ही देती हो।

बहुत पहले मिडिल क्लास महिलाएं दोपहर में समय मिलने पर अपने घर का काम किया करती थीं जैसे की बड़ी पापड़ वगैरह बनाना उसके बाद समय और थोड़ा सा बदला तब महिलाएं कपड़ों पर कसीदे करती थीं, स्वेटर बुनाई करती थीं और भी न जाने कई तरह के हस्त कलाएं बनाकर अपना समय व्यतीत करती थीं।

अब आ गया रेडीमेड का जमाना, अब ना बच्चों को बुनाई किए हुए स्वेटर पसंद आते हैं और ना ही पति इन्हें पसंद करते हैं। अब उनका भी कोई रोल नहीं रहा, अब तो उनसे केवल सजावटी चीजें ही बनाई जाती हैं। बड़ी और पापड़ बनाना भी किसी बड़े झंझट से कम वाला काम नहीं है। अब यह भी करना हम सबको पसंद बिल्कुल भी नहीं है। नौकरीपेशा महिलाएं नौकरी करने चली जाती हैं और हम हाऊस वाइफ घर पर बोर होती रहती हैं। किट्टी देवी तेरा बहुत बड़ा सहारा हमको मिल जाता है। 1 महीने में दो बार या एक बार भी हम महिलाएं एक साथ मिलजुल कर हंसी-मजाक इसकी चुगली, उसकी चुगली आदि करके अपना मनोरंजन करती हैं। साथ ही साथ पकवानों का भी लुत्फ उठा लेती हैं, अब भला हमें और क्या चाहिए किट्टी देवी तेरी कृपा से हमें यह सब प्राप्त हो रहा है, यह हमारे लिए किसी वरदान से कम नहीं होता।

हाई सोसाइटी की महिलाएं किसी क्लब का गठन करती हैं, जिसमें उन्हें चंद के रूप में कुछ पैसे भी खर्च करने पड़ते हैं पर तेरी पार्टी में ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ता बल्कि यहां पर खेल खेलने पर पैसों की या पुरस्कारों की वृद्धि होती है। हाऊजी रुपी जुए में भी बड़ा मजा आता है। जीतने पर ऐसी प्रसन्नता होती है जैसे महाभारत के जुए में शकुनी मामा को हुआ करता था। हार जाने पर थोड़ा सा हमारा मेकअप वाला चेहरा उतर जाता है पर कोई बात नहीं... हम समझ लेते हैं कि चलो जीवन में और खेल में हार और जीत तो चलता ही रहता है।

नाम में हमें भले ही प्लास्टिक का साधारण सा टिफिन सेट या वाटर बोतल ही क्यों ना मिले पर कहा जाता है ना पुरस्कार तो पुरस्कार ही होता है। ऐसी साधारण सी चीज यदि हमारे कोई रिश्तेदार आकर दे तो हम मुंह बनाते हुए कहेंगे हु... यह भी कोई देता है क्या? लेकिन वही साधारण चीज हमें पुरस्कार में मिले तो... किसी गोल्ड मेडल या किसी ट्रॉफी से कम नहीं लगती।

किट्टी देवी, तेरी ही वजह से हमने जाना कि सावन की हरियाली क्या होती है वरना हमें तो सावन में आने वाले त्योहारों के लिए पकवान बनते-बनते ही सावन कब भादों में बदल जाता था, पता ही नहीं लगता था। तू ही हमें ब्रह्मांड सुंदरी, विश्व सुंदरी से ना सही पर हरियाली और सावन सुंदरी के खिताब से नवाजती है तो हम स्वयं को किसी विश्व सुंदरी या ब्रह्मांड सुंदरी से कम नहीं समझ पाते। और साथ ही जय हो मीडिया वालों का जो हमारी तस्वीर अखबार पर छापकर हमें और भी पुलकित कर देते हैं। साथ ही फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पर भी हम छा जाती हैं, तो मां कसम हमें कितनी खुशी महसूस होती है, हम मिडिल क्लास हाउसवाइफ सातवें आसमान पर पहुंच जाती हैं। नाम में हमें भले ही प्लास्टिक का साधारण सा टिफिन सेट या वाटर बोतल ही क्यों ना मिले पर कहा जाता है ना पुरस्कार तो पुरस्कार ही होता है। ऐसी साधारण सी चीज यदि हमारे कोई रिश्तेदार आकर दे तो हम मुंह बनाते हुए कहेंगे हु... यह भी कोई देता है क्या? लेकिन वही साधारण चीज हमें पुरस्कार में मिले तो... किसी गोल्ड मेडल या किसी ट्रॉफी से कम नहीं लगती।

कुछ भी हो आजकल के जमाने में जब हम सब तरफ से अकेले पड़ जाते हैं और हां किट्टी देवी एक बात का मैं तुम्हें और धन्यवाद करना चाहती हूं कि अब तेरा आयोजन घरों में न होकर किसी होटल में भी होने लगा है, वरना हम मिडिल क्लास गृहिणियों को होटल भी देखने को कहां मिलते थे तेरे ही बहाने से हम किसी रिसोर्ट, वाटर पार्क या और भी ऐसी सुंदर जगह का दर्शन कर लेते हैं।

किट्टी देवी तेरी कृपा हम सब पर बनी रहे। किट्टी देवी सदा सहाय।

● **अमृता जोशी**

PRISM®
CEMENT

प्रिज़्म® चैम्पियन प्लस

ज़िम्मेदारी मज़बूत और टिकाऊ निर्माण की.

- ज्यादा मज़बूती
- ज्यादा महीन कण
- ज्यादा वर्कबिलिटी
- बेहतरीन निर्माण कार्य
- इको–फ्रेन्डली
- कन्सिसटेंट क्वालिटी
- ज्यादा प्रारम्भिक ताक़त
- ज्यादा बचत

PRISM®
चैम्पियन प्लस
सीमेंट

दूर की सोच®

Toll free: 1800-572-1444 Email: cement.customerservice@prismjohnson.in

मध्यप्रदेश सरकार का संकल्प

अक्षय जल, सुरक्षित कल

नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

जल गंगा संवर्धन अभियान

"जल की हर बूंद में आने वाले कल का भविष्य छिपा है। इसलिए इस अमूल्य धरोहर की किसी भी मूल्य पर रक्षा करना हमारा दायित्व है।"

- डॉ. मोहन यादव, मुख्यमंत्री

जल संरक्षण का 'जन संकल्प'

जल संचय में वृद्धि

- ₹2048 करोड़ लागत के 83 हजार से अधिक खेत तालाबों का निर्माण पूर्ण, जिससे खेत का पानी खेत में सिंचित होगा
- ₹254 करोड़ लागत से 1 लाख से अधिक कूप तैयार
- अमृत सरोवर 2.0 के तहत ₹ 354 करोड़ लागत से 1 हजार से अधिक नए अमृत सरोवरों का निर्माण
- शहरी क्षेत्रों में 3300 से अधिक जल स्रोतों का पुनर्जीवन, 2200 नालों की सफाई एवं 4000 वर्षा जल संचयन संरचनाओं का निर्माण पूर्ण

जनभागीदारी

- 40 लाख लोगों की भागीदारी से 5 हजार से अधिक जल स्रोतों का हुआ जीर्णोद्धार
- My Bharat पोर्टल के माध्यम से 2.30 लाख से अधिक जलदूत बनाए गए
- ग्रामीण क्षेत्रों में पानी चौपाल का आयोजन

तकनीकी नवाचार

- GIS आधारित SIPRI सॉफ्टवेयर के उपयोग से जल स्रोतों का चयन एवं AI आधारित मॉनिटरिंग की गई
- नर्मदा परिक्रमा पथ एवं अन्य तीर्थ मार्गों के डिजिटलीकरण के जरिए श्रद्धालुओं की सुविधाओं का रखा जा सकेगा ख्याल

पर्यावरणीय एवं कृषि प्रभाव

- 57 प्रमुख नदियों में मिलने वाले 194 से अधिक नालों का चिह्नांकन एवं उनके शोधन के लिए योजना तैयार
- जैव विविधता संरक्षण हेतु घड़ियाल और कछुओं का किया गया जलावतरण
- 145 नदियों के उद्गम क्षेत्रों को चिन्हित कर हरित विकास हेतु योजना तैयार
- अविरल निर्मल नर्मदा योजना में 5600 हेक्टेयर में पौधारोपण प्रारंभ
- वन्य जीवों के लिए जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु 2500 से अधिक तालाब, स्टॉप डैम का निर्माण
- पौधारोपण हेतु लगभग 6 करोड़ पौधों की नर्सरी विकसित

वॉटरशेड हेतु कार्य

- ₹1200 करोड़ लागत की 91 वॉटरशेड परियोजनाएं स्वीकृत, 5.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को मिलेगी सिंचाई सुविधा
- 9000 से अधिक जल संरक्षण संरचनाओं के जरिए किसानों को 1 वर्ष में दो से तीन फसलों का मिल रहा लाभ